



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 25, 1993/ आश्विन 3, 1915

No. 39]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 25, 1993/ASVINA 3, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

## भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II) PART II—Section 3—Sub-Section (II)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएँ  
Statutory Orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than  
Ministry of the Defence)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1993

का. आ. 1982.—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आन्ध्र प्रदेश सरकार की सहमति से, जो गृह (एस. सी.-ए) विभाग जी.ओ.आर. टी. सं. 682, तारीख 20 मार्च, 1993 द्वारा दी गई थी, केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा रजिस्ट्रीकृत आर. सी. 13(ए)/92 हैदराबाद में नीचे उपदर्शित मुसंगत अधिनियम के उपबंधों के अधीन दंडनीय अपराधों और उक्त अपराधों तथा वैसे ही या उन्हें या उनसे संबंधित तथ्यों से उद्भूत होने वाले संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए किन्हीं अन्य अपराधों के संबंध में या उनसे सम्बन्धित प्रयत्नों, दुष्प्रवृत्तियों और पशुचर के अन्वेषण के लिए, जो निम्नलिखित प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा

किए गए अभिकथित हैं, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार संपूर्ण आन्ध्र प्रदेश राज्य पर करती है।

आर.सी.-मं. और विधि की धाराएं	अभियुक्त का नाम
भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम सं. 45) की धारा 420, 468, 471 के साथ पठित धारा 120ब और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम सं. 49) की धारा 13(1)(घ) के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन आर.सी. 13(ए)/92—हैदराबाद, तारीख 20 मार्च, 1993	डा. जी. स्वामी, एम. बी. बी. एस., निर्मल क्लोनिक, 0-4-194, रेजीमेंटल बाजार सिकन्दराबाद और अन्य प्रभावित प्राइवेट व्यक्ति।

[संख्या 228/59/93—ए.जी.डी. II]

आर. एम. विष्ट, अवर सचिव

## MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel &amp; Training)

New Delhi, the 3rd Sept. 1993

S.O. 1982.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946) the Central Government, with the consent of the State Government of Andhra Pradesh accorded vide Home (SC-A) Department G.O. Rt. No. 682 dated 20-3-1993 hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Andhra Pradesh for investigation of the offences of RC 13(A) 92-Hyd. registered by the Central Bureau of Investigation and attempts, abetments and conspiracy in relation to or in connection with the said offences and any other offences committed in the course of the same transaction and or arising out of the same or related facts, punishable under the provisions of relevant Act indicated below alleged to have been committed by the following private persons.

RC No. &amp; Secs. of Law

Re. 13(A)/92-Hyderabad dated 20-3-93 u/s. 1208 read with 420, 468, 471 of the Indian Penal Code, 1860 (Act No. 45 of 1860) and 13(2) read with 13(1)(d) of the prevention of Corruption Act, 1988 (Act No. 49 of 1988)

— Name of the accused

Dr. G. Swamy, M.B.B.S. Nirmal Clinic  
0-4-194 Regimental Bazar Secunderabad  
— and other unknown Private Persons.

[No. 228/59/93-AVD. II]

R.S. BISHT, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1993

का. आ. 1983—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम सं. 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पब सं. 70—जी आई/6-4223 बी/84, तारीख 15 अप्रैल, 1993 द्वारा दी गई उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की सहमति से, श्री सतीश चन्द चोपड़ा सुपुत्र श्री नन्द लाल चोपड़ा, आयु लगभग 55 वर्ष, निवासी कमल कुंज, कच्चा हटा, अमीनाबाद लखनऊ की हत्या के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य में आलमबाग लखनऊ पुलिस थाने में रजिस्ट्रीकृत मामला सं. 385/83 के बारे में भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम सं. 45) की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराधों और उक्त अपराधों तथा उन्हीं तथ्यों से उद्भूत होने वाले वैसे ही संयवहार के अनुक्रम में किये गये किन्हीं अन्य अपराधों के संबंध में या उगसे संसक्त प्रयत्नों, दुष्प्रेरणाओं और पद्धतियों के अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार संपूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य पर करती है।

[संख्या 228/53/93—ए. बी. डी. — II]

आर. एस. बिष्ट, अवसर सचिव

New Delhi, the 9th September, 1993

S.O. 1983.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 read with Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946), the Central Government, with the consent of the State Government of Uttar Pradesh accorded vide letter No. 70-G.I./6-4223B/84 dated 15-4-1993 hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Uttar Pradesh for investigation of the offences punishable under Section

302 of the Indian Penal Code, 1860 (Act No. 5 of 1860) and attempts, abetments and conspiracies in relation to or in connection with the said offences and any other offences committed in the course of the same transaction arising out of the same facts in regard to case No. 385/83 relating to the murder of Sri Satish Chand Chopra S/o. Sri Nand Lal Chopra aged about 55 years r/o. Kamal Kunj, Kachha Hata, Aminabad, Lucknow, registered at Police Station Alambagh, Lucknow in the State of Uttar Pradesh.

[No. 228/53/93-AVD II]

R. S. BISHT, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 1993

का. आ. 1984—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (क) इन नियमों का सक्रिय नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) संशोधन नियम, 1993 है।

(ख) ये 25 सितम्बर, 1993 को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 में, नियम 48ख के पश्चात् निम्नलिखित नियम अतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“48ग: साधारण रिजर्व इंजीनियर बन में पायनरिंग के मामले में अर्हक सेवा में परिवर्धन —

(1) मूल नियमों के नियम 56 के खंड (क) के दूसरे परन्तुक के अधीन या सिविल सेवा विनियमों के अनुच्छेद 459 के खंड (च) के पहले परन्तुक के अधीन सेवानिवृत्त होने वाले पायनरिंग की

सेवानिवृत्त की तारीख को अर्हक सेवा में 5 वर्ष से अधिक की अवधि तक इस शर्त के अधीन रहते हुए वृद्धि की जाएगी कि सरकारी सेवक द्वारा की गई कुल अर्हक सेवा किसी भी दशा में 33 वर्ष से अधिक नहीं होती है।

(2) मूल नियमों के नियम 56 के खण्ड (ड) के तीसरे परन्तुक के अधीन या सिविल सेवा विनियमों के अनुच्छेद 459 के खण्ड (च) के दूसरे परन्तुक के अधीन सेवानिवृत्त होने वाले पायनरों की सेवानिवृत्ति की तारीख की अर्हक सेवा में 5 वर्ष से अधिक की अवधि तक इस शर्त के अधीन रहते हुए वृद्धि की जाएगी कि सरकारी सेवक द्वारा की गई कुल अर्हक सेवा किसी भी दशा में 33 वर्ष से अधिक नहीं होती है और यह उसे अधिवर्षिता की तारीख के पश्चात् नहीं ले जाती है।

(3) उपर्युक्त उपनियम (1) और उपनियम (2) के उपबंध, नियम 48ख में उल्लिखित सुसंगत नियमों के अधीन स्वच्छता सेवानिवृत्ति चाहने वाले पायनरों की दशा में उसमें अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और उन नियमों द्वारा विहित शर्तों को उनके द्वारा पूरा करने के अधीन रहते हुए होंगे

[सं. 38/66/93-पे. एवं पे. भो. क. (ए)]

कशमीरी लाल, उप सचिव

पाद-टिप्पण :

केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 को का. आ. 934 तारीख 1-4-1972 के रूप में प्रकाशित किया गया था। नियमों का चतुर्थ संस्करण (जुलाई 1988 तक संशोधित) 1988 में प्रकाशित किया गया था। उक्त नियमों के पश्चात्तवर्ती संशोधन पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा किए गए :—

क्रम संख्या	अधिसूचना संख्या	तारीख
1	2	3
1.	का. आ. सं. 254	4-2-1989
2.	का. आ. सं. 970	6-5-1989
3.	का. आ. सं. 2467	7-10-1989
4.	का. आ. सं. 899	14-4-1990
5.	का. आ. सं. 1454	26-5-1990
6.	का. आ. सं. 2329	6-9-1990
7.	का. आ. सं. 3269	8-12-1990
8.	का. आ. सं. 3270	8-12-1990
9.	का. आ. सं. 3273	8-12-1990

1	2	3
10.	का. आ. सं. 409	9-2-1991
11.	का. आ. सं. 464	16-2-1992
12.	का. 7 (14)-पी. एंड पी. डब्ल्यू/एफ/90	23-8-1991
13.	का. 4 (15)-पी. एंड पी. डब्ल्यू/88-डी	9-10-1991
14.	का. 7 (10)-पी. एंड पी. डब्ल्यू/89-एफ	28-11-1991
15.	का. 28/40-पी. एंड पी. डब्ल्यू/88-बी	9-1-1992
16.	का. 38 (189)-पी. एंड पी. डब्ल्यू/88-एफ	4-2-1992
17.	43/4/92-पी. एंड पी. डब्ल्यू/जी	27-11-1992
18.	1 (10)-पी. एंड पी. डब्ल्यू/ई	31-12-1992
19.	का. 1 (66)-पी. एंड पी. डब्ल्यू/89-ई	18-1-1993
20.	का. 1 (65)-पी. एंड पी. डब्ल्यू/91-ई	19-5-1993
21.	का. 38 (84)-पी. एंड पी. डब्ल्यू/93-एफ	3-9-1993

New Delhi, the 13th September, 1993

S.O. 1984.—In exercise of powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 namely ;

(1) (a) These rules may be called the Central Civil Services (Pension) Fourth Amendment Rules, 1993.

(b) They shall come into force w.e.f. 25th September, 1993.

2. After rule 48-B in the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 the following rule shall be inserted, namely :—

"48-C.—Addition to qualifying service in the case of Pioneers in General Reserve Engineers Force;

1. The qualifying service of Pioneers as on the date of retirement, retiring under the 2nd proviso to clause (e) of rule 56 of the Fundamental Rules or 1st proviso of clause (f) of article 459 of the Civil Service Regulations shall be increased by the period not exceeding 5 years, subject to the condition that the total qualifying service rendered by the Government servant does not in any case exceed 33 years.

2. The qualifying service of the Pioneers as on the date of retirement, retiring under the 3rd proviso of clause (e) of rule 56 of the Fundamental Rules or the 2nd proviso to clause (f) of article 459 of the Civil Service Regulations shall be increased by the period not exceeding 5 years, subject to the condition that the total qualifying service rendered by the Government servant does not in any case exceed 33 years and it does not take him beyond the date of superannuation.

3. The provisions in sub-rule (1) and sub-rule (2) above will be without prejudice to the provisions contained in rule 48-B in the event of the Pioneers seeking voluntary retirement under the relevant rules mentioned therein and sub-

ject to their fulfilment of the conditions prescribed by those rules.”

[No. 33/66/93-P & PW(A)]  
KASHMIRI LAL, Dy. Secy.

#### FOOT NOTE :

The Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 were published as S.O. No. 934 dated 1-4-1972. The Fourth Edition (corrected upto July, 1988) of the rules was published in 1988. The rules were subsequently amended vide Department of Pension and Pensioners' Welfare notifications given below :—

Sl. No. Notification No. Date

1. S.O. No. 254 dated 4-2-1989
2. S.O. No. 970 dated 6-5-1989
3. S.O. No. 2467 dated 7-10-1989
4. S.O. No. 899 dated 14-4-1990
5. S.O. No. 1454 dated 26-5-1990
6. S.O. No. 2329 dated 6-09-1990
7. S.O. No. 3269 dated 8-12-1990
8. S.O. No. 3270 dated 8-12-1990
9. S.O. No. 3273 dated 8-12-1990
10. S.O. No. 409 dated 9-02-1991
11. S.O. No. 464 dated 16-02-1991
12. F. 7(14)-P&PW/F/90 dated 23-08-1991
13. F. 4(15)-P&PW/88-D dated 9-10-1991
14. F. 7(10)-P&PW/89-F dated 28-11-1991
15. F. 28(40)-P&PW/88-B dated 9-01-1992
16. F. 38(189)-P&PW/88-F dated 4-02-1992
17. F. 43(493)-P&PW(G) dated 27-11-1992
18. F. 1(10)-P&PW/92-E dated 31-12-1992
19. F. 1(66)-P&PW/89-E dated 18-01-1993
20. F. 1(65)-P&PW/91-E dated 19-05-1993
21. F. 38(84)-P&PW/93-F dated 3-09-1993.

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1993

का. आ. 1985.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने जिसे विशेषी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/181/92-सी. शु.-8 तारीख 18-12-92 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री दिलीप जैन सुपुत्र श्री शेषमल जैन, मेसर्स डी. आर. ज्वैलर्स, आराम भवन, जेल रोड, डोंगरी (पूर्व), बम्बई-400009 को निषेध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, बम्बई में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे भविष्य में तस्करी के माल को छिपाने, रखने तथा लाने से जाने के प्रलावा तस्करी के माल का धंधा करने जैसी गतिविधियों में लिप्त रहने से रोका जा सके।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, बम्बई के समक्ष हाजिर हों।

[फा. सं. 673/181/92-सी. शु.-8]

रूप चन्द, अव्वर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 16th August, 1993

S.O. 1985.—Whereas the Joint Secretary of the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of foreign Exchange and prevention of smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F. No. 673/181/92-Cus. VIII dated 18-12-1992 under the said sub-section that Shri Dilip Jain S/o Shri Sheshmal Jain, M.s. D. R. Jewellers, Aram Bhavan, Jail Road, Dongri (east), Bombay-400009 be detained and kept in custody in the Central Prison, Bombay with a view to preventing him from dealing in smuggled goods otherwise than by engaging in concealing keeping and transporting smuggled goods in future.

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Bombay within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/181/92-CUS. VIII]

ROOP CHAND, Under Secy.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1993

का. आ. 1986—आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 की उपधारा (2) के खंड (ए) के अधीन प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन स्पष्टीकरण के प्रयोजनार्थ कर निर्धारण वर्ष 1993-94 के लिए निम्नलिखित श्रेणी के कर निर्धारितियों के संबंध में देय तारीख 31 अक्तूबर, 1993 के रूप में विनिर्दिष्ट करती है :—

कर निर्धारितियों की श्रेणी

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 40 के खंड (बी) के उपखंड (5) के अधीन स्पष्टीकरण (4) में यथा परिभाषित फर्मों में कार्यरत भागीदारों को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44 एबी के उपबंधों के अनुसार कर निर्धारण वर्ष 1993-94 से संगत दिनांक 31-3-1993 को समाप्त हुए पिछले वर्ष के संबंध में अपने लेखों की लेखा परीक्षा करवाना अपेक्षित होता है बशर्ते कि ऐसा कार्यरत भागीदार उन फर्मों से दिनांक 31-3-1993 को समाप्त हुए पिछले वर्ष के लिए पारिश्रमिक प्राप्त करने का हकदार है जैसा कि सहभागिता दस्तावेज के द्वारा प्राधिकृत अथवा

शर्तों के अनुरूप है और उक्त पारिश्रमिक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 40 के खंड (बी) के उपखंड (5) के अन्तर्गत स्पष्टीकरण (3) में यथा परिभाषित पुस्तक लाभों के समानुपात के रूप में देय है।

[अधिसूचना सं. 9358/फा. सं. 220/6/93-आयकर-नि-II]

अजय कुमार, अवसर सचिव

#### CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 26th August, 1993

S.O. 1986.—In exercise of the powers conferred under clause (a) of sub-section (2) of Section 119 of the Income-tax Act, 1961, the Central Board of Direct Taxes hereby specifies the due date for the purposes of Explanation under sub-section (1) of Section 139 as 31st October, 1993 in respect of the following class of assessee for the assessment year 1993-94 :—

#### CLASS OF ASSESSEES

The working partners as defined in Explanation (4) under sub-clause (v) of clause (b) of section 40 of the Income-tax Act, 1961, in firms which are required to get their accounts audited in respect of the previous year ended 31-3-1993 relevant to the assessment year 1993-94 in accordance with the provisions of section 44-AB of the Income-tax Act, 1961, provided that such working partners are entitled to receive remuneration for the previous year ended 31-3-1993 from such firms, as authorised by or in accordance with the terms of the partnership deed and the said remuneration is payable as a proportion of the book profits as defined in Explanation (3) under sub-clause (v) of clause (b) of section 40 of the Income-tax Act, 1961.

[Notification No. 9358/F. No. 220/6/93-ITA. II]  
AJAY KUMAR, Under Secy.

रक्षा मंत्रालय

(भारी वाहन निर्माणी)

आवडी, 6 सितम्बर, 1993

का.आ. 1987—चूंकि मैं महाप्रबन्धक, भा.वा.नि. का विचार है कि श्री के. उन्निकुमरन टि.न. 74296/1021 हाइली स्कूलड, भा.वा.नि. आवडी को विभागीय जांच के संबंध में साक्षी के रूप में किसी प्रलेख को मंगाने के लिये, इनको सम्मन देना आवश्यक है:

1. श्री ए.के. उमापति, फोरमेन, (रिटायर्ड),  
न. 9, कोकिलाम्बल स्ट्रीट, पूम्पुहार नगर,  
अम्बतूर, मद्रास-600053
2. श्री के. एस. एच. मेनन, मार्फत श्री एस.पी. मदान  
सप्टागिरी, न. 11, एम.टी.एच. रोड,  
अम्बतूर, मद्रास-600053
3. श्री एम.वी. मथई, नगचरो गांव,  
पनिपरा पोस्ट, ऐरनाकुलम जिला,  
केरल-686692

इसलिये अब, विभागीय जांच (साक्षी की उपस्थिति एवं प्रलेखों के प्रस्तुतीकरण के बाध्यकरण) अधिनियम,

1972 (1972 का 18) के खण्ड 4 के उप-खंड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरी श्री के. आर. महबूब जान, उप-महाप्रबन्धक, भा.वा. नि. आवडी को ऊपर उल्लिखित अधिनियम के खण्ड 5 में विनिर्दिष्ट शक्तियों की जांच प्राधिकारी के रूप में श्री के. उन्निकुमरन में संबंधित जांच के लिये साक्षियों को सम्मन भेजने तथा प्रलेखों को मंगाने के उपयोग हेतु प्राधिकृत करता हूं।

[नं०. स्था./विज/86/60(ए)]

वी.एन. पट्टाविरामन, महाप्रबन्धक

#### MINISTRY OF DEFENCE

(Heavy Vehicles Factory)

Avadi, the 6th September, 1993

S.O. 1987.—Whereas I, the General Manager, HVF is of the opinion that for the purposes of the departmental inquiry relating to Shri K. Unnikumaran, T. No. 74296/1021, Highly Skilled, HVF Avadi it is necessary to summon as witnesses/call for any document from :

1. Shri A. K. Umapath, Foreman (Retired)  
No. 9, Kokilambal Street, Poompuhar Nagar,  
Ambattur, Madras-600053.
2. Shri KSH Menon, C/o Shri S. P. Madan,  
Sapthagiri, No. 11, MTH Road,  
Ambattur, Madras-600053.
3. Shri M. V. Mathai, Naganchary Village,  
Panipra Post, Ernakulam Dist.,  
Kerala-686692.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Departmental Inquiries (Enforcement of Attendance of Witnesses and Production of Documents) Act 1972 (18 of 1972), the undersigned hereby authorises Shri K. R. Mahaboob John, Dy. General Manager, HVF Avadi as the Inquiring Authority to exercise the power specified in Section 5 of the said Act in relation to summoning of witnesses and call for documents connected to the inquiry in respect of Shri K. Unnikumaran.

[No. ESTT/VIG/86/60 (a)]

V. N. PATTABIRAMAN, General Manager

आवडी, 6 सितम्बर, 1993

का.आ. 1988—विभागीय जांच (साक्षी की उपस्थिति एवं प्रलेखों के प्रस्तुतीकरण के बाध्यकरण अधिनियम 1972 (1972 का 18) के खण्ड 4 के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, भा.वा.नि. का महाप्रबन्धक विशेष रूप से श्री के. आर. महबूब जान, उप-महाप्रबन्धक, भा.वा.नि. आवडी को उपर्युक्त अधिनियम, के खण्ड 4 के उप-खण्ड (1) के द्वारा अधोहस्ताक्षरी को प्रदत्त शक्तियों के उपयोग का प्राधिकार श्री के. उन्निकुमरन टि.न. 74296/1021, हाइली स्कूलड, भा.वा.नि. आवडी, जिसके विरुद्ध विभागीय जांच की जा सकती है, के संबंध में देता हूं।

[नं. स्था./विज/86/60(बी)]

वी. एन. पट्टाविरामन, महाप्रबन्धक

Avadi, the 6th September, 1993

S.O. 1988.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 4 of the Departmental Inquiries (Enforcement of Attendance of Witnesses and Production of Documents) Act 1972, (18 of 1972), I, the General Manager, HVF hereby specify Shri K. R. Mahaboob John, Dy. General Manager, HVF, Avadi as an authority to exercise the power conferred on the undersigned by sub-section (1) of Section 4 of the said Act in respect of Shri K. Unnikumaran, T. No. 74296/1021, Highly Skilled HVF, Avadi against whom a Departmental Inquiry may be held.

[No. ESTT/VIG/86/60 (b)]

V. N. PATTABIRAMAN, General Manager

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 3-सितम्बर, 1993

का. आ. 1989.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कच्चा मांस (द्रुतशीतित/हिमशीतित) का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1992 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कच्चा मांस (द्रुतशीतित/हिमशीतित) का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) (संशोधन) नियम, 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवक्त होंगे।

2. कच्चा मांस (द्रुतशीतित/हिमशीतित) का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1992 में,

(क) नियम 3-5-26, के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“3-5-26 महिला और पुरुष कर्मकारों तथा कर्मचारियों के लिए पर्याप्त संख्या में शौचालयों और वाशबेसिन का प्रबंध किया जाएगा। ये प्रसंस्करण इकाइयों से अलग स्थित होंगे और उनके दैनिक निर्व्यूण के लिए इंतजाम किए जाएंगे। शौचालयों का मुख्य द्वार मक्खी अमेष और स्वतः बंद होने वाले दरवाजों सहित जालीदार होगा। यथोचित परिवर्तनशील कक्ष सुविधाओं का भी प्रबंध किया जाएगा।

(ख) नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“7. निरीक्षण फीस—निर्यातकर्ता/प्रसंस्करणकर्ता अभिकरण को निम्नानुसार निरीक्षण फीस देगा :

(1) शव के रूप में अस्थि सहित भेड़ और बकरे के मांस (ताजा, द्रुतशीतित/ या हिमशीतित) के निर्यात के लिए प्रति परेक्षण न्यूनतम 50 रुपए के अधीन रहते हुए प्रति शव 1.00 रु. की दर से फीस।

(2) अस्थि सहित भैंस के मांस (ताजा, द्रुतशीतित या हिमशीतित) के निर्यात के लिए प्रति परेक्षण न्यूनतम 50 रुपए के अधीन रहते हुए प्रति चौथाई 2.00 रुपया की दर से फीस।

(3) अस्थि रहित ताजे, द्रुतशीतित या हिमशीतित भैंस या भेड़ या बकरा मांस के डिब्बों में निर्यात के लिए प्रति परेक्षण न्यूनतम 100 रुपए के अधीन रहते हुए प्रति डिब्बा 1 रुपए 25 पैसे की दर से फीस।

टिप्पण—प्रत्येक परेक्षण के लिए निर्यातकर्ता/प्रसंस्करणकर्ता द्वारा संदेय निरीक्षण फीस की रकम निकटतम रुपए तक पूर्णांकित की जाएगी और इस प्रयोजन के लिए जहां ऐसी रकम में रुपए का भाग पैसे हों, वहां यदि ऐसा भाग पचास पैसे या अधिक हो तो उसे बढ़ाकर रुपया कर दिया जाएगा और यदि ऐसा भाग पचास पैसे से कम हो तो उसे छोड़ दिया जाएगा”।

[फा. सं. 6/1/92-ईअ ईएण्ड ईपी]

कुमारी सुमा सुब्बण्णा, निदेशक

टिप्पण—मूल नियम अधिसूचना सं. का. आ. 204, तारीख 30-1-93 द्वारा प्रकाशित किए गए हैं।

#### MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 3rd September, 1993

S.O. 1989.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Export of Raw Meat (Chilled/Frozen) (Quality Control and Inspection) Rules, 1992, namely:—

1. (1) These rules may be called the Export of Raw Meat (Chilled/Frozen) (Quality Control and Inspection) (amendment) Rules, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Export of Raw Meat (Chilled/Frozen) (Quality Control and Inspection) Rules, 1992,

(a) for rule 3.5.26, the following rule shall be substituted, namely:—

“3.5.26 sufficient number of lavatories and wash basins shall be provided for each sex of workers and employees. These shall be situated away from the processing halls and arrangements shall be made for their daily disinfection. The main door to the lavatories shall be fly proof and netted with self-closing doors. Adequate changing room facilities shall also be provided.”;

(b) for rule 7, the following rule shall be substituted, namely:—

“7. Inspection fee—Inspection fee shall be paid by the exporter/processor to the Agency as under:

(i) For export of bone-in sheep and goat meat (fresh, chilled or frozen) in carcass form, a fee at the rate of Rupee 1.00 per carcass subject to a minimum of Rupees 50 per consignment.

(ii) For export of bone-in bulalo meat (fresh, chilled or frozen) a fee at the rate of Rupees 2.00 per quarter subject to a minimum of Rupees 50 per consignment.

(iii) For export of boneless fresh, chilled or frozen buffalo or sheep or goat meat in cartons, a fee at the rate of Rupees 1.25 per carton subject to a minimum of Rupees 100 per consignment.

Note : The amount of inspection fee for each consignment payable by the exporter/processor shall be rounded off to the nearest rupee and, for this purpose where such amount contains a part of rupee, then if such a part is fifty paise or more it shall be increased to one rupee and if such part is less than fifty paise, it shall be ignored.

[F. No. 6/1/92-EI&EP]

KUM. SUMA SUBBANNA, Director

Note : The principal rules are published vide Notification No. S.O. 204 dated, 30-1-93.

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1993

का. आ. 1990.—भारतीय सरकार ने निर्यात (कवालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) को धारा 7 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स इन्स्पेक्शन सर्वे एण्ड सर्विलेन्स (इंडिया) प्रा. लिमिटेड, 26/27, एराबालु चैट्टी स्ट्रीट, मद्रास-600001 का भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1498 तारीख 13 मई, 1991 के अनुसार इससे उपाबद्ध अनुसूची I तथा II में विनिर्दिष्ट खनिज तथा शयन (ग्रुप I तथा II) का मद्रास में निर्यात से पूर्व निरीक्षण करने के लिए अभिकरण के रूप में मान्यता दी है;

और मैसर्स इन्स्पेक्शन सर्वे एण्ड सर्विलेन्स (इंडिया) प्रा. लिमिटेड, कलकत्ता ने यह गृहनिर्माण कर लिया है कि उनकी मद्रास शाखा ने अगस्त, 1992 से कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः अब, भारतीय सरकार निर्यात (कवालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) को धारा 7 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स इन्स्पेक्शन सर्वे एण्ड सर्विलेन्स (इंडिया) प्रा. लिमिटेड, 26/27, एराबालु चैट्टी, मद्रास-600001 को दो गणों मान्यता वापस लेती है तथा भारत सरकार वाणिज्य मंत्रालय का अधिसूचना सं. का.आ. 1498 तारीख 13 मई, 1991 को विरुद्धित करती है।

[फा. सं. 5(1)/88—ई आइ एण्ड ई पी]

कुमारा सुमा सुब्बन्ना, निदेशक

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 10th September, 1993

S.O. 1990.—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), had recognised M/s. Inspection Survey and Surveillance (India) Private Limited, 26/27, Errabalu Chetty Street, Madras-600001, as an agency for inspection of Minerals and Ores (Group-I and II), as specified in Schedule I and Schedule II annexed thereto, prior to export at Madras vide notification of the Government of India, in the Ministry of Commerce, No. S.O. 1498 dated the 13th May, 1991;

And whereas it has been confirmed by M/s. Inspection Survey and Surveillance (India) Private Limited, Calcutta that their Madras branch has ceased to exist with effect from August, 1992;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby withdraws the recognition granted to M/s. Inspection Survey and Surveillance (India) Pvt. Limited, 26/27, Errabalu Chetty Street, Madras-600001 and rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 1498 dated the 13th May, 1991.

[File No. 5(1)/88-EI&EP]

KUM. SUMA SUBBANNA, Director

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

आदेश

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1993

का.आ. 1991.—मैसर्स एसियन लेवर (प्रा.) लिमिटेड, कलकत्ता को ई पी सी जी स्कीम के अन्तर्गत संलग्न सूची के अनुसार पूंजीगत भाल के आयात के लिये 8,13,594/- रुपये (आठ लाख तेरह हजार, पांच सौ चौरातने) का एक आयात लाइसेंस सं. पी./सी जी/2101168 दिनांक 9-11-92 प्रदान किया गया था।

2. फर्म ने उपर्युक्त लाइसेंस की विनियम नियंत्रण प्रति की अनुलिपि इस आधार पर जारी करने के लिये आवेदन किया है कि लाइसेंस की मूल विनियम नियंत्रण प्रति खो गई है या गुम हो गई है। आगे यह भी कहा गया है कि लाइसेंस की मूल विनियम नियंत्रण प्रति को सीमाशुल्क सदन, कलकत्ता से पंजीकृत कराया गया था और उसका रु. 5,17,935/- की राशि के लिये उपयोग किया गया है और शेष रु. 2,95,659/- की राशि का उपयोग नहीं हुआ है।

3. अपने तर्क के समर्थन में लाइसेंसधारी ने नोटरी पब्लिक, कलकत्ता के समक्ष विधिवत शपथ लेकर स्टाम्प पेपर पर एक हलफनामा दाखिल किया है। तदनुसार मैं सन्तुष्ट हूँ कि फर्म से आयात लाइसेंस सं. पी./सी जी/2101168, दिनांक 9-11-1992 की मूल विनियम नियंत्रण प्रति खो गई है या गुम हो गई है। यथा-संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की उपधारा 9(गग) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स एसियन लेवर (प्रा.) लि. कलकत्ता को जारी की गई उक्त मूल विनियम नियंत्रण प्रति सं. पी/सी जी/2101168 दिनांक 9-11-92 को एव द्वारा निरस्त किया जाता है।

4. पार्टी को उक्त लाइसेंस की विनियम नियंत्रण प्रति की अनुलिपि अलग से जारी की जा रही है।

[फा.सं. 18/1091/ईपीसीजी-2/93/270]

माधव देवी केम, उपाय महानिदेशक

## (OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS AND EXPORTS)

## ORDER

New Delhi, the 9th September, 1993

S.O. 1991.—M/s. Asian Leather (P) Ltd., Calcutta were granted an import licence No. P/CG/2101168 dated 9-11-92, Rs. 8,13,594 (Rupees Eight lakhs thirteen thousand five hundred ninety four only) import of CG as per list enclosed under EPCG Scheme.

2. The firm has applied for issue of duplicate copy of Exchange control purpose of the above mentioned licence on the ground that the original Exchange Control purpose copy of the licence has been lost or misplaced. It has further been stated that the Exchange Control purpose copy of the licence was registered with Customs House, Calcutta and has been utilised for a sum of Rs. 5,17,935 leaving an unutilised balance of Rs. 2,95,659.

3. In support of their contention, the licensee has filed an affidavit on stamped paper duly sworn in before Notary Public, Calcutta. I am accordingly satisfied that the original Exchange Control purpose copy of import licence No. P/CG/2101168 dated 9-11-92 has been lost or misplaced by the firm. In exercise of the powers conferred under sub-clause 9(cc) of the Import (Control) Order 1955, dated 7-12-1955 as amended, the said original Exchange Control purpose copy No. P/CG/2101168 dated 9-11-92 issued to M/s. Asian Leather (P) Ltd., Calcutta is hereby cancelled.

4. The duplicate Exchange control purpose copy of the said licence is being issued to the party separately.

[F. No. 18/1091/EPCG-II/93](270)]

MAYA D. KEM, Dy. Chief Controller

## कृषि मंत्रालय

(कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग)

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 1993

का.ग्रा. 1992—भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा बनाये गये स्थायी वित्त समिति के विनियम 2(4) के अनुसरण में तथा कृषि उत्पाद उपकर अधिनियम, 1940 की धारा 27(2) में निहित प्रावधानों के अनुसरण में शासी निकाय के निम्नलिखित सदस्यों को इस निकाय द्वारा 29-6-1993 से एक वर्ष की नयी अवधि के लिये स्थायी वित्त समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया जाता है :—

1. प्रोफेसर जगजीत सिंह,  
विपणन और प्रबन्ध संस्थान,  
62 एफ, सुजान सिंह पार्क,  
नई दिल्ली।
2. सुश्री सनीति बधवा,  
द्वारा 138 शेख सराय,  
चरण-1, आर.पी.एस. फ्लेट्स,  
नई दिल्ली-110017
3. श्री सन्तोष कुमार गंगवार,  
संसद सदस्य (लोक सभा),  
27, चौधरी मोहल्ला,  
बरेली (उ.प्र.)  
14 डी फिरोजशाह रोड,  
नई दिल्ली

4. डा. आई.पी. सी. महापात्र,  
कुलपति,  
उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,  
भुवनेश्वर, - 751008(उड़ीसा)

5. डा. ए.के. बसु,  
निदेशक,  
केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान,  
नागपुर(महाराष्ट्र)

6. या. जे. सी. बक्शी,  
132-डी, किचलू नगर,  
लुधियाना-141001(पंजाब)

7. डा. सुखदेव सिंह,  
हाउस नं. 419,  
सेक्टर 38 ए,  
चंडीगढ़-160014

[फा.सं. 6(1)/93-मो.एससी.]

मालती एस. सिन्हा, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agricultural Research and Education)

## INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH

New Delhi, the 18th August, 1993

S.O. 1992.—In pursuance of Regulation 2(iv) of the Standing Finance Committee Regulations, framed by the Indian Council of Agricultural Research and in pursuance of provision contained in Section 7(2) of the A. P. Cess Act, 1940, the Governing Body has elected the following Members to the Standing Finance Committee for a fresh period of one year with effect from 29-6-1993 :—

1. Prof. Jagjit Singh,  
Institute of Marketing and Management,  
62 F, Sujjan Singh Park,  
New Delhi.
2. Ms. Suniti Wadhwa,  
C/o 138, Sheikh Sarai,  
Phase-I, RPS Flats,  
New Delhi-110017.
3. Shri Santosh Kumar Gangwar,  
M.P. (Lok Sabha),  
22, Chaudhary Mohalla,  
Bareilly (U.P.),  
14 D, Ferozshah Road,  
New Delhi.
4. Dr. I. C. Mahapatra,  
Vice-Chancellor,  
Orissa University of Agriculture and Technology,  
Bhubaneswar-751008 (Orissa).
5. Dr. A. K. Basu,  
Director,  
Central Institute for Cotton Research,  
Nagpur (Maharashtra).
6. Dr. J. C. Bakshi,  
132-D, Kitchlu Nagar,  
Ludhiana-141001 (Punjab).
7. Dr. Sukhdev Singh,  
House No. 419,  
Sector 38-A,  
Chandigarh-160014.

[F. No. 6(1)/93-CSC]  
MALTI S. SINHA, Jt. Secy.



## पेट्रोलियम और कैंमिकल मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1993

का. आ. 1993.—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए बेगयम्पेट—यानाम ब्रांच गैस पाइपलाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइपलाइन गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा विछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइपलाइन विछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सूक्ष्म प्राधिकारी गैस अथारिटी ऑफ इण्डिया लिमि. के. जी. बसीन प्रोजेक्ट, राजमुंद्री-533104 आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत करना चाहता है।

## अनुसूची

टाटीपाका-काकीनाडा गैस पाइप में इन लाइन बेगयम्पेट से यानाम ब्रांच लाइन

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे./ एकड़ में)	विवरण		
तूरु गोदावरी	रामचन्द्रपुरम	बेगयम्पेट	170—भाग	0.02.5	जी०पी०		
			169—1 भाग	0.03.5			
			3 भाग	0.00.5			
			6 भाग	0.09.5			
			13 भाग	0.06.0			
			160—भाग	0.17.0			
			161—3 भाग	0.05.5			
			4 भाग	0.04.0			
			157—3 भाग	0.02.5			
			4 भाग	0.02.0			
			5 भाग	0.05.0			
			156—3 भाग	0.01.5			
			4 भाग	0.03—0			
			8 भाग	0.00.5			
			9 भाग	0.03—0			
			10 भाग	0.03.0			
			150—1 भाग	0.07.5			
			146—1 भाग	0.00.25			
			2 भाग	0.05.0			
3 भाग	0.12.0						
हेक्टे.		0.93.75					
		या					
ए०सी०		2.30 1/2 सेन्ट्स					

[सं. ओ.-14016/4/93-जी. पी.]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

## MINISTRY OF PETROLEUM &amp; CHEMICAL

New Delhi, the 9th September, 1993

S.O. 1993.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum and Natural Gas through Vegayamma Peta Yanam Branch Gas Pipeline is to be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (i) of the Section 3 of the Petroleum & Minerals

Pipelines (Acquisition of Right of Users in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. K.G. Basin Project, 29-7-1/3/1, Opp : Gowihani Library, Rajahmundry-533 104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

## SCHEDULE

Branch Gas Pipeline from Vegayamma Peta to YANAM

From : Tatipake—Kakinada Gas Pipe Line Project

District	Mandal	Village	Survey Nos.	Area (In Hect./ Acres)	Remarks
East Godavari	Ramachandra Puram	Vegayamma Peta	170/Part	0.02.5	G.P.
			169/1 Part	0.03.5	
			169/3 part	0.00.5	
			169/6 part	0-09-5	
			169/13 part	0-06-0	
			160/8 part	0-05-5	
			160/6 part	0-11-5	
			161/3 part	0-05-5	
			161/4 part	0-04-0	
			157/3 part	0-02-5	
			157/4 part	0-02-0	
			157/5 part	0-05-0	
			156/3 part	0-01-5	
			156/4 part	0-03-0	
			156/8 part	0-00-5	
			156/9 part	0-03-0	
			156/10 part	0-03-0	
			150/1 part	0-07-5	
			146/1 part	0-00-25	
			146/2 part	0-05-0	
			146/3 part	0-12-0	
				0-93-75	
				Or	
			AC	2.30 1/2 Cents	

[No. O-14016/4/93-GP.]

ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1993

प्रा. प्रा. 1994.--जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए वेगम्पेट-यानाम ब्रांच गैस पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जानी है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

वर्तते कि उक्त भूमि में अपनी रूचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भारत भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति संक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमि. के. जी. बसीन प्रोजेक्ट, राजमंड्री-533104 आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से प्रथमा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत करना चाहता है।

## अनुसूची

टाटीपाका--काकीनाडा गैस पाइप मेड्स लाइन, वेगम्पेट से यानाम ब्रांच लाइन

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे./ एकर में)	विवरण
ईस्ट गोदावरी	पामरु	यरंपोतवरम	32--1 भाग	0.10.5	
			29--भाग	0.01.0	
			7--1 ए भाग	0.00.5	
			1 बि भाग	0.01.5	
			2 बि भाग	0.07.5	
			6--2 भाग	0.07.25	
			5--1 भाग	0.02.5	
			2 भाग	0.06.5	
			3 ए भाग	0.00.25	
			2--ए भाग	0.01.0	
			3--बि भाग	0.00.25	
			4 सी भाग	0.03.0	
			5 भाग	0.00.5	
			6 भाग	0.00.25	
			7 भाग	0.05.5	
			8 ए भाग	0.00.25	
			हेक्टे.	0.48.25	
			या		
			ए०सी०	1.19 1/2 सैन्ट्स	

[सं. ओ.-14016/4/93-जी. पी.]

अर्घेन्नु सेन, निदेशक

New Delhi, the 9th September, 1993

S.O. 1994.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum and Natural Gas through Vigayampeta to Yanam Branch Gas pipeline is to be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (i) of the Section 3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of users in the land) Act,

1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. K.G. Basin Project, 29-7-1/3/1, Opp : Gowthami Library, Rajahmundry-533 104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

## SCHEDULE

Branch Gas pipeline from Vegayampeta to Yanam  
from Tatipako—Kakinada Gas Pipe Line Project

District	Mandal	Village	Survey Nos.	Area (In Hect/ Acres)	Remarks
East Godawari	Pamarru	Yerra Pothavaram	32 1 Part	0-10-5	
			29—Part	0-01-0	G.P.
			7 1A Part	0-00-5	G.P.
			1B Part	0-01-5	
			2B1 Part	0-07-5	
			6 2 Part	0-07-25	
			5—1 Part	0-02-5	
			2 Part	0-06-5	
			3A Part	0-00-25	
			2—1 Part	0-01-0	G.P.
			3B Part	0-00-25	
			4 C Part	0-03-0	
			5 Part	0-00-5	
			6 Part	0-00-25	
			7 Part	0-05-5	
			8A Part	0-00-25	
				0-48-25	
			Or		
			AC	1-19 1/2 Cents	

[No. O-14016/4/93-G.P.]

ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1993

का. धा. 1995.—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए वेगयम्पेट—यानाम ब्रांच गैस पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाईन गैस अप्रारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

वर्षों कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सर्वम प्राधिकारी गैस व्वायरिटी ऑफ इण्डिया लिमि. के. जी. बसीन प्रोजेक्ट, राजमंड़ी-533104 आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दाय कराने समय किसी भी व्यक्ति को विरोध रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत करना चाहता है।

## अनुसूची

टाटीगाला-काकीनाडा गैस पाइप मेइन लाइन वेगयम्मपेट में यानाम  
ब्रांच लाइन

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे.) (एकड़ में)	विवरण
ईस्ट गोदावरी	पामरू	अद्वमपल्ली	131—भाग	0.00.5	
			132—1 भाग	0.07—0	
			2 भाग	0.05—0	
			101—1 भाग	0.03.0	
			2 भाग	0.03.0	
			3 भाग	0.05.0	
			5 भाग	0.05.5	
			6 भाग	0.04.0	
			8 भाग	0.03.5	
			100—भाग	0.03.0	
			97—1 भाग	0.13.0	
			2 भाग	0.06.0	
			96—2 भाग	0.01.25	
			4 भाग	0.05.5	
			95—1 भाग	0.05.5	
			2 भाग	0.04.5	
			4 भाग	0.00.5	
			94—भाग	0.01.0	
			87—1 भाग	0.02.5	
			2 भाग	0.00.5	
			3 भाग	0.02.0	
			4 भाग	0.05.5	
			5 भाग	0.05.5	
			7 भाग	0.03.0	
			88—15 भाग	0.00.25	
			21 भाग	0.01.5	
			83—1 भाग	0.06.0	
			2 भाग	0.01.5	
			3 भाग	0.02.5	
ईस्ट गोदावरी	पामरू	अद्वमपल्ली	6 भाग	0.00.25	
			14 भाग	0.01.5	

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे./ एकड़ में)	विवरण
			84—1 भाग	0.03.0	
			2 भाग	0.00.75	
			82—5 भाग	0.05.0	
			6 ये भाग	0.02.0	
			6 बी भाग	0.02.0	
			77—7 भाग	0.00.25	
			8 भाग	0.03.5	
			9 भाग	0.02.5	
			10 भाग	0.01.0	
			11 भाग	0.04.0	
			80—1 भाग	0.02.0	
			2 भाग	0.02.0	
			3 भाग	0.02.0	
			4 भाग	0.01.0	
			5 भाग	0.02.5	
			79—1 भाग	0.04.0	
			2 भाग	0.01.0	
			3 भाग	0.08.0	
			हक्टे.	1.60.25	
				या	
				3.95 1/2 सेंटी	

[सं. ओ-140 16/4/93-जी. पी.)]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 9th September, 1993

S.O. 1995.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum and Natural Gas through Vegayammapet to Yanam Branch pipeline is to be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, it exercise of the powers confirmed by sub-section (i) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Users in the

Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. K. G. Basin Project, 29-7-1/3/1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533 104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

## SCHEDULE

Branch Gas pipe line from Vegayampota to Yanam  
Tatipake-Kakinada Gas Pipe Line Project

Distriot	Mandal	Village	Survey Nos.	Area (In Heet.)/ Acres)	Remarks
East Godavari	Pamaruru	Addampalli	131—Part	0.00.5	
			132—1 Part	0.07.0	
			2 Part	0.05.0	
			101—1 part	0-03-0	

1	2	3	4	—5	6
			2 Part	--0-03-0	
			3 Part	0-05-0	
			5 Part	0-05-5	
			6 Part	0-04-0	
			8 Part	0-03-5	
			100—Part	0-03-0	G.P.
			9—1 Part	0-13-0	
			2 part	0-06-0	
			96—2 Part	0-01-25	
			4 Part	0-05-5	
			95—1 Part	0-05-5	
			2 Part	0-04-5	
			4 Part	0-00-5	G.P.
			94—Part	0-01-0	G.P.
			87—1 part	0-02-5	
			2 part	0-00-5	
			3 part	0-02-0	
			4 part	0-05-5	
			5 part	0-05-5	
			7 part	0-03-0	
			88—15 part	0-00-25	
			21 part	0-01-5	
East Godavari	Pamarru	Addampalli	83—1 part	0-06-0	
			2 part	0-01-5	
			3 part	0-02-5	
			6 part	0-00-25	
			14 part	0-01-5	
			84-1 part	0-03-0	
			2 part	0-00-75	
			82-5 part	0-05-0	
			6A part	0-02-0	
			6B part	0-02-0	
			77-7 part	0-00-25	
			8 part	0-03-5	
			9 part	0-02-5	
			10 part	0-01-0	
			11 part	0-04-0	
			80-1 part	0-02-0	
			2 part	0-02-0	
			3 part	0-02-0	
			4 part	0-01-0	
			5 part	0-02-5	
			79-1 part	0-04-0	
			2 part	0-01-0	
			3 part	0 08-0	
				1-06-25	
				OR	
			AC	3-95 1/2 Cents	

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1993

का.प्र. 1996.— जहाँकि केन्द्र सरकार यह शानुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए वेगयम्पेट-यानाम ब्रान्च गैस पाइप लाइन परियोजना का अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अध्यागिरी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा विधायता जाना है ।

और यह भी शानुभव करती है कि उन कार्य के लिए इस साध संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोजता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है ।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोजता का अधिकारग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा इस पर प्रयोजता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा को घोषणा करती है ।

बर्तते कि उक्त भूमि में अपनी रची रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भारत भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सज्जम राधिकारी गैस अध्यागिरी आफ इण्डिया लिमि. के.जी. बेसिन प्रोजेक्ट, राजमुंद्री 533104 आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है ।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराने समय किसी भी व्यक्ति को विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अन्तः मन करना चाहता है ।

## अनुसूची

टाटीपाका-काकीनाडा गैस पाइप लाइन; वेगयम्पेट से यानाम ब्रान्च लाइन

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे./एकड़ में)	विवरण
			148-8 भाग	0.05.0	
			9 भाग	0.02.5	
			11 भाग	0.00.5	
			हेक्टे.	0.08.0	
				या	
				Ac 0.19 Cents	

[सं. ओ. 14016/4/93 जी पी]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 9th September, 1993

S.O. 1996.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum and Natural Gas through Vegayampeta to Yanam Branch Gas pipeline is to be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (i) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Users in the

Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. K. G. Basin Project, 29-7-1/3/1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533 104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

## SCHEDULE

Branch Gas pipe line from Vegayampeta to yanam from  
TATIPAKE KAKINADA GAS PIPE LINE PROJECT

DISTRICT	MANDAL	VILLAGE	SURVEY Nos.	AREA (IN HECT/ACRES)	REMARK
1	2	3	4	5	6
EAST			148-8 part	0-05-0	
ADDAVARI	PAMARRU	ANDRANGI	9 part	0-02-5	
			11 part	0-00-5	
				0-08-0	
				Or	
				AC 0-19 Cents	

[No. O-14016/4/93-G.P.]

ARDHENDU SEN, Director



नई दिल्ली, 9 मिनम्बर, 1993

का.आ. 1997 :--जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम वदार्थ एवं प्राकृतिक गैस स्रोतों के लिए बेगम्मेट-याम ब्रान्च गैस पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसका साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोजन का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

आ: पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोजन का अधिकार ग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उस पर प्रयोजन का अधिकार ग्रहण करने की संज्ञा की घोषणा करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमि. के.जी. बसोन प्रोजेक्ट, राजमुंड्री-533100 आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत करना चाहता है।

## अनुसूची

टाटीयाका-काकीनाडा गैस पाइप मैट्रिन लाइन बेगम्मेट से खानाम ब्रान्च लाइन

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे. वृकड में)	विवरण
हुंड गोदावरी	काजुल	कुयुचेर	199-1 भाग	0.08.0	
			198- भाग	0.03.0	
			196-1 भाग	0.09.5	
			2 भाग	0.14.0	
			142-3 भाग	0.03.0	
			4 भाग	0.04.5	
			143-3 भाग	0.01.0	
			143-1 भाग	0.01.0	
			2 भाग	0.11.25	
			6 भाग	0.05.0	
			139- 5 भाग	0.01.0	
			6 भाग	0.07.0	
			145-भाग	0.01-0	
			157-1 भाग	0.04.5	
			3 भाग	0.03.0	
			4 भाग	0.02.5	
			7 भाग	0.03.0	
			8 भाग	0.03.0	
			9 भाग	0.01.5	
			155-3 भाग	0.01.0	
			4 भाग	0.04.5	
			153-भाग	0.05-0	
			154-भाग	0.01-0	

1	2	3	4	5	6
इन्ट गोदावरी	काजुलू	कुयुरेस	150--5 भाग	0.05-0	
			2 भाग	0.04.5	
			97---1 भाग	0.16.0	
			98---1 भाग	0.06-0	
			3 भाग	0.00.50	
			99--21 भाग	0.05.5	
			93--5 भाग	0.05.25	
			8 भाग	0.00.25	
			9 भाग	0.00.25	
			10 भाग	0.03.50	
			11 भाग	0.03-0	
			90--3 भाग	0.03.0	
			6 भाग	0.07.0	
			7 भाग	0.3.0	
			8 भाग	0.02-5	
			88---8 भाग	0.01.0	
			9 भाग	0.00.5	
			10 भाग	0.01.0	
			89---1 भाग	0.05.5	
			2 भाग	0.04.5	
			4 भाग	0.03.0	
			12 भाग	0.03.0	
			87---6 भाग	0.00.5	
			7 भाग	0.00.5	
			86--- भाग	0.03.0	
			82---1 भाग	0.03.0	
			3 भाग	0.03.5	
			4 भाग	0.05.5	
			81---9 भाग	0.03.0	
			11 भाग	0.03.0	
			223---भाग	0.01.5	
			233---1 भाग	0.01.0	
			4 भाग	0.03.0	
			5 भाग	0.07.0	
			229---11 भाग	0.05.5	
			230---4 भाग	0.05.5	
			227---भाग	0.01.0	
			हेक्टे.	2.30.00	
			या		
			एकड़ 5.68 सेन्टम		

[सं. ओ.-14016/4/93-जी पी]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 9th September, 1993

S.O. 1997.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum and Natural Gas through Tatipaka-Kakinada pipeline is to be laid by the Gas Authority of India Ltd.;

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, it exercise of the powers conferred by sub-section (i) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Users in the

Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. K. G. Basin Project, 29-7-1/3/1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533 104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

## SCHEDULE

Branch Gas Pipe line from Vegayammapeta to Yanam  
from Tatipaka-Kakinada Gas Pipe Line Project

District	Mandal	Village	Survey No.	Area (In Hect./ Acres)	Remarks
1	2	3	4	5	6
East Godavari	Kaguhura	Kuyyara	199-1 part	0-08-0	G.P.
			198 part	0-03-0	
			196-1 part	0-09-5	
			196-2 part	0-14-0	
			142-3 part	0-03-0	
			142-4 part	0-04-5	
			143-3 part	0-01-0	
			1 part	0-01-0	
			2 part	0-11-25	G.P.
			6 part	0-05-0	
			139-5 part	0-01-0	
			6 part	0-07-0	
			145 part	0-01-0	
			157-1 part	0-04-5	
			3 part	0-03-0	
			4 part	0-02-5	
			7 part	0-03-0	
			8 part	0-03-0	
			9 part	0-01-5	
			155-3 part	0-01-0	
			4 part	0-04-5	
			153 part	0-05-0	
			154 part	0-01-0	
			150-5 part	0-05-5	G.P.
			150-2 part	0-04-5	
			97-1 part	0-16-0	
			98-1 part	0-06-0	
			98-3 part	0-00-5	
			99-2 1 part	0-05-5	
			93-5 part	0-05-25	
			93-8 part	0-00-25	
			93-9 part	0-00-25	
			93-10 part	0-03-50	
			93-11 part	0-03-0	
			90-3 part	0-03-0	
			90-6 part	0-07-0	
			90-7 part	0-03-0	
			8 part	0-02-5	
			88-8 part	0-01-0	

1	2	3	4	5	6
			88-9 part	0-00-5	
			88-10 part	0-01-0	
			89-1 part	0-00-5	
			89-2 part	0-04-5	
			89-4 part	0-03-0	
			89-12 part	0-03-0	
			87-6 part	0-00-5	G.P.
			87-7 part	0-00-5	
			86 part	0-03-0	G.P.
			82-1 part	0-03-0	
			82-3 part	0-03-5	
			82-4 part	0-05-5	
			81-9 part	0-03-0	
			11 part	0-03-0	
			223 part	0-01-5	G.P.
			233-1 part	0-01-0	G.P.
			233-4 part	0-03-0	
			5 part	0-07-0	
			229-11 part	0-05-5	
			230-4 part	0-11-5	
			227 part	0-01-0	G.P.
				2-30-0	
				Or	
				AC 5-68 Cents.	

[No. O-14016/4/93-G.P.]  
ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1993

का.आ. 1998:— जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए बेगम्पेट-यानाम ब्रान्च गैस पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस ग्रिड-रिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है ;

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है ;

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम, 1962) (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की संज्ञा की घोषणा करती है ;

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमि. के.जी. वसीन प्रोजेक्ट, राजमंडी-53810 आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है ;

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रकट करना चाहता है ।

अनुसूची

टाटीपाका-काकीनाडा गैस पाइप लाइन लायन बेगम्पेट से यानाम ब्रान्च लाइन

जन्मपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे./ एकड़ में)	विवरण
ईस्ट गोदावरी	काजुलूरु	कुगुदूर	274-1 भाग	0.03.0	
			2 भाग	0.01.0	

4	5
4 भाग	0.07.0
9 भाग	0.00.5
14 भाग	0.06.0
16 भाग	0.04.0
17 भाग	0.02.5
276—1 भाग	0.04.0
2 भाग	0.04.5
290—1 भाग	0.03.0
3 भाग	0.10.0
4 भाग	0.05.0
288—4 भाग	0.06.5
5 भाग	0.08.0
6 भाग	0.01.0
294—2 भाग	0.03.5
3 भाग	0.02.5
8 वीं भाग	0.12.5
10 भाग	0.01.5
295—1 भाग	0.04.0
3 भाग	0.05.0
4 भाग	0.07.0
6 भाग	0.03.0
9 भाग	0.04.0
5 भाग	0.01.0
302—3 वीं भाग	0.01.0
301—3 भाग	0.01.5
4 भाग	0.06.0
5 वीं भाग	0.03.0
11 भाग	0.05.5
12 भाग	0.06.0
306—1 बी भाग	0.02.0
1 वीं भाग	0.02.0
2 भाग	0.03.5
3 भाग	0.04.5
298—4 भाग	0.04.5
320—भाग	0.01.5
322—2 भाग	0.06.5
323—1 भाग	0.15.0
327—भाग	0.02.0

हेक्टे.

1.81.0

या

एकड़ 4.47½ सेंट्स

[सं. ओ-14016/4/93-जी पी]

अध्वैन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 9th September, 1993

S.O. 1998,—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum and Natural Gas through Vegayampeta to Yanam Branch Gas Pipeline is to be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, it exercise of the powers conferred by sub-section (i) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of Users in the

Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to Competent Authority. Gas Authority of India Ltd. K. G. Basin Project, 29-7-1/3/1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533 104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

## SCHEDULE

Branch Gas pipe line from Vegayampeta to Yanam from Tatipake-Kakinada Gas Pipe Line project

District	Mandal	Village	Survey No.	Area (In Hect./ Acres)	Remarks
East Godavari	Kajaluru	D. Liggli Dhirru	274-1 part	0-03-0	
			2 part	0-01-0	
			4 part	0-07-0	
			9 part	0-00-5	
			14 part	0-06-0	
			16 part	0-04-0	
			17 part	0-02-5	
			276-1 part	0-04-0	
			2 part	0-04-5	
			290-1 part	0-03-0	
			3B part	0-10-0	
			4 part	0-05-0	
			288-4 part	0-06-5	
			5 part	0-08-0	
			6 part	0-01-0	
			292-2 part	0-03-5	
			3 part	0-02-5	
			8B part	0-12-5	
			10 part	0-01-5	
			295-1 part	0-04-0	
			3 part	0-05-0	
			4 part	0-07-0	
			5 part	0-01-0	
			6 part	0-03-0	
			9 part	0-04-0	
			302-3B part	0-01-0	
			301-3 part	0-01-5	
			4 part	0-06-0	
			5/C part	0-03-5	
			11 part	0-05-5	
			12 part	0-06-0	
			306-1B part	0-02-0	
			1C part	0-02-0	
			2 part	0-03-5	
			3 part	0-04-5	
			299/4-part	0-04-5	G.P.
			320-part	0-01-5	G.P.

322-2 part	0-06-5	
323-1 part	0-15-0	
327-part	0-02-0	G.P.

Hec 1-81-0 Area  
Or

Acres 4-47 1/2

[No. O-14016/4/93-G.P.]  
ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1993

का.आ. 1999:- जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए वेगयम्मूपेट —यानाम ब्रान्च गैस पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

वर्ष 1993 में उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति संक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इण्डिया लि. के.जी. वसीन प्रोजेक्ट, राजामुंद्री-533104 आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को विज्ञापन रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत करना चाहता है।

#### अनुसूची

टाटीपाका-काकीवाडा गैस पाइप लाइन लायन वेगयम्मूपेट से यानाम ब्रान्च लायन

जनपद	तहसाल	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे, एकड़ में)	विवरण
ईस्ट गोदावरी	काजुलूरु	उण्णुमिल्लो	37-1 भाग	0.01.0	
			3 भाग	0.02.5	
			4 भाग	0.03.0	
			5 भाग	0.05.0	
			13 भाग	0.04.5	
			15 भाग	0.09.0	
			16 भाग	0.01.0	
			71-1 भाग	0.00.5	
			72-1 भाग	0.07.5	
			2 भाग	0.04.0	
			11 भाग	0.00.25	
			12 भाग	0.01.0	
			13 भाग	0.03.0	
			14 भाग	0.00.5	

1	2	3	4	5	6
ईस्ट गोदावरी	काजुलूरु	उप्पुमिल्ली	19 भाग	0.01.0	
			20 भाग	0.02.5	
			21 भाग	0.03.0	
			82—1 भाग	0.01.5	
			2 भाग	0.05.5	
			4 भाग	0.03.0	
			5 भाग	0.04.5	
			9 भाग	0.00.5	
			83—2 भाग	0.03.5	
			3 भाग	0.05.0	
			21 भाग	0.05.5	
			22 भाग	0.03.5	
			84—1 भाग	0.00.5	
			2 भाग	0.04.0	
			85— भाग	0.05.5	
			हेक्टे.	0.88.75	
			या		
				AC-2-19½ Cents	

[च. सं. 14010/4/93-जीवी]

अर्धेन्द्र सेन, निदेशक

New Delhi, the 9th September, 1993

S.O. 1999.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum and Natural Gas through Vegayampeta to Yanam Branch Gas pipeline is to be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (i) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of Users in the

Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. K. G. Basin Project, 29-7-1/3/1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533 104 Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

## SCHEDULE

Branch Gas pipe line from Vegayampeta to Yanam  
from Tatipake-Kakinada Gas Pipe Line Project

District	Mandal	Village	Survey No.	Area (In Hect/ Acres)	Remarks
1	2	3	4	5	6
East Godavari	Kajuluru	Uppumilli	37-1 part	0-01-0	
			3 part	0-02-5	
			4 part	0-03-0	
			5 part	0-05-0	
			13 part	0-04-5	
			15 part	0-05-0	
			16 part	0-01-0	



1	2	3	4	5	6
East Godavari	Kajulliru	Uppumilli	71-1 part	0-00-5	
			72-1 part	0-07-5	
			2 part	0-04-0	
			11 part	0-00-25	
			12 part	0-01-0	
			13 part	0-03-0	
			14 part	0-00-5	
			19 part	0-01-0	
			20 part	0-02-5	
			21 part	0-03-0	
			82-1 Part	0-01-5	
			2 part	0-05-5	
			4 part	0-03-0	
			5 part	0-03-5	
			9 part	0-00-5	
			83-2 part	0-01-5	
			3 part	0-05-0	
			21 part	0-05-5	
			22 part	0-03-5	
			84-1 part	0-00-5	
			2 part	0-04-0	
			85-part	0-05-5	G.P.
			Hec	0-88-75	Acres
				Or	
			Acres	2-19½	Cents

[No. O-14016/4/93-G.P.]  
ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1993

का.आ. 2000.—जबकि केन्द्र सरकार का यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए बेगयम्पेट-यानाम ब्रान्च गैस पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उम कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खंड 3 के उपखंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सर्वोच्च प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के. जी. बसीन प्रोजेक्ट, 29-7-1/3/1, लक्ष्मीनगर पेट, अक्विट गैसमि क्षेत्री, राजमंड्री - 533104, आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मन करना चाहता है।

अनुसूची

टाटीपाका-काकीनाडा गैस पाइप मेडन लाइन बेगयम्पेट से यानाम

ब्रान्च लाइन

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे न.	क्षेत्रफल (हेक्टे./ एकड़ में)	विवरण
1	2	3	4	5	6
ईस्ट गोदावरी	काजुलूरु	कोलका	32-भाग	0-26-0	
			37-भाग	0-00-25	

4

5

38-18 भाग	0-11-00
42-भाग	0-09-50
44-1ए भाग	0-14-00
45-1ए भाग	0-02-00
1बी भाग	0-05-00
50-1बी भाग	0-03-00
2 भाग	0-03-75
3 भाग	0-04-00
51-1ए भाग	0-01-00
103-2 भाग	0-11-00
3बी भाग	0-05-00
102-3 भाग	0-08-50
115-4 भाग	0-03-00
5 भाग	0-03-00
3 भाग	0-01-00
1सी भाग	0-08-00
116-1ए भाग	0-06-00
1बी भाग	0-03-00
1सी भाग	0-03-00
125-2 भाग	0-06-00
3 भाग	0-02-50
124-4 भाग	0-05-00
5 भाग	0-05-00
131-2ए भाग	0-09-50
2 बी भाग	0-00-50
130-3 भाग	0-04-50
2 भाग	0-03-50
129-भाग	0-15-00
134-भाग	0-01-00

हेक्टे.

1-83-50 या ए.सी 4-54 एकड

[सं. ओ - 14016/4/93 - जी. पी.]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 9th September, 1993

S.O. 2000.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum and Natural Gas through Vegayammapet to Yanah Brach Gas pipeline is to be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And, whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (i) of the Section 3 of the Petroleum & Minerals

pipelines (Acquisition of Right of Users in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority of India Ltd. K. G. Basin Project, 29-7-1/3/1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

## SCHEDULE

Branch Gas Pipe Line from Vegayampeta to Yanam  
from Tatipake-Kakinada Gas Pipe Line Project

District	Mandal	Village	Survey No.	Area (In Hect./ Acres)	Remarks
East Godavari	Kajulure	Kolanka	32-part	0-26-0	G.P.
			37-part	0-00-25	
			38-1B part	0-11-0	
			42 part	0-09-5	
			44-1A part	0-14-0	
			45-1A part	0-02-0	
			1 B part	0-05-0	
			50-1B part	0-03-0	
			2 part	0-03-75	
			3 part	0-04-0	
			51-1A part	0-01-0	
			103-1 part	0-11-0	
			3/B part	0-05-0	
			102-3 part	0-08-5	
			115-4 part	0-03-0	
			5 part	0-03-0	G.P.
			3 part	0-01-0	
			1C part	0-08-0	
			116-1A part	0-06-0	
			1B part	0-03-0	
			1C part	0-03-0	
			125-2 part	0-06-0	
			3 part	0-02-5	
			124-4 part	0-05-0	
			5 part	0-05-0	
			131-2A part	0-09-5	
			2B part	0-00-5	
			130-3 part	0-04-5	
			2 part	0-03-5	
			129-part	0-15-0	
			134-part	0-01-0	
			Hec	1-83-5	Ares
				Or	
			Acres	4.54	Cents.

[No. O-14016/4/93-G.P.]  
ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1993

का. आ. 2001:— जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए वेगयम्पेट-यानाम ब्रान्च गैस पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणों में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की संज्ञा की घोषणा करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमि. के. जी. बसीन प्रोजेक्ट, राजमंड्री-533104, आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत करना चाहता है।

#### अनुसूची

टाटीपाका—काकीनाडा गैस पाइप मेहन लायन वेगयम्पेट से यानाम

बान्ध लायन

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे न.	क्षेत्रफल (हेक्टे./ एकड़ में)	विवरण
ईस्ट गोदावरी	काजुलूरु	पल्लिपल्लिम	246-2 भाग	0-00-5	
			3 भाग	0-05-5	
			250-भाग	0-01-0	
			258-3 भाग	0-06-5	
			5 भाग	0-06-5	
			6 भाग	0-02-0	
			257-1 भाग	0-01-00	
			3 भाग	0-05-5	
			4 भाग	0-05-5	
			263-4 भाग	0-05-75	
			262-8 भाग	0-07-5	
			9 भाग	0-02-0	
			286-भाग	0-02-0	
			296-10भाग	0-02-0	
			297-भाग	0-02-0	
			325-2 भाग	0-16-0	
			334-1 भाग	0-04-0	
			2ए भाग	0-03-0	
			2बी भाग	0-03-0	
			333-2ए भाग	0-16-75	
			343-भाग	0-01-25	
			342-भाग	0-02-5	
			341-1 भाग	0-00-00	
			340-भाग	0-01-0	
			368-2बी भाग	0-16-0	
			369-16 भाग	0-00-5	
			18 भाग	0-02-0	
			19 भाग	0-03-5	
			366-2 भाग	0-08-0	
			363-भाग	0-04-0	
			364-2 भाग	0-04-5	
हेक्टे.				1-46.25	
				या	
				एकड़	3.61 1/2 सेन्टस

[सं. ओ - 14016/4/93 - जी. पी.]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 9th September, 1993

S.O. 2001.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum and Natural Gas through Vegayampeta to Yanam Branch Pipeline is to be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (i) of the Section 3 of the Petroleum & Minerals pipelines (Acquisition of Right of Users in the Land) Act,

1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. K. G. Basin Project, 29-7-1/3/1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

## SCHEDULE

Branch Gas Pipe Line from Vegayampeta to Yanam  
from Tatipakc-Kakinada Gas Pipe Line Project

District	Mandal	Village	Survey Nos.	Are (In Hect/ Acres)	Remarks
East Godavari	Kajulure	Palli Palem	246-2 part	0-00-5	G.P.
			3 part	0-05-5	
			250-part	0-01-0	
			258-3 part	0-06-5	
			5 part	0-06-5	
			6 part	0-02-0	G.P.
			257-1 part	0-01-0	
			3 part	0-05-0	
			4 part	0-05-5	
			263-4 part	0-05-75	
			262-8 part	0-07-5	G.P.
			9 part	0-02-0	
			286-part	0-02-0	
			296-10 part	0-02-0	
			297-Part	0-02-0	
			335-2 part	0-16-0	G.P.
			334-1 part	0-04-0	
			2A part	0-03-0	
			2B part	0-03-0	
			333-2A part	0-16-75	
			343-part	0-01-25	G.P.
			342-part	0-02-5	
			341-1 part	0-06-0	
			340-part	0-01-0	
			368-2B part	0-16-0	
			369-16 part	0-00-5	G.P.
			18 part	0-02-0	
			19 part	0-03-5	
			366-2 part	0-08-0	
			363-part	0-04-0	
			364-2 part	0-04-0	
			Total Hec.	1-46-25 Or	Ares
			Acs	3-6 1/2 cents	

[No. O-14016/4/93-G.P.]

ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1993

का. आ. 2002—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए वेगयम्पेरे-यानाम ब्रान्च गैस पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की संशा की घोषणा करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति संक्षेप प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इंडिया लि. के. जी. ब्रेसीन प्रोजेक्ट, 12/76 राजमंड्री - 533 103 आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत करना चाहता है।

## अनुसूची

टाटीपाका-काकीनाडा गैस पाइप मेहन लायन वेगयम्पेरे से यानाम

ब्रान्च लायन

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे. एकड़ में)	विवरण
1	2	3	4	5	6
ईस्ट गोदावरी	तालारेवू	उपयोगला	153-1 भाग	0-00-25	
			2 भाग	0-22-50	
			156-3 भाग	0-06-50	
			4 भाग	0-01-50	
			5 भाग	0-03-00	
			10 भाग	0-01-50	
			11 भाग	0-01-00	
			12 भाग	0-02-00	
			15 भाग	0-02-00	
			158-भाग	0-01-00	
			161-10 भाग	0-07-00	
			162-भाग	0-09-00	
			163-भाग	0-10-00	
			166-1 भाग	0-01-50	
			2 भाग	0-03-00	
			3 भाग	-03-00	
			5 भाग	0-03-00	
			167-भाग	0-10-00	
			169-भाग	0-03-00	
			171-भाग	0-00-50	
			170-2 भाग	0-04-50	
			3 भाग	0-05-00	

1	2	3	4	5	6
			115-1 भाग	0-05-00	
			2 भाग	0-11-00	
			114-2 भाग	0-12-25	
			3 भाग	0-06-75	
			107-1 भाग	0-01-00	
			2 भाग	0-06-00	
			8 भाग	0-09-50	
			10 भाग	0-03-00	
			11 भाग	0-02-00	
			106-1 भाग	0-05-00	
			105-1 भाग	0-04-50	
			2 भाग	0-13-50	
			103-4 भाग	0-03-50	
			हेक्टे.	1-84-25	
			या		
			एकड़	4-55 सेन्ट्स	

[सं. सो - 14016/4/93 - जी. पी.]

अश्वेन्द्रु सेन, निदेशक

New Delhi, the 9th September, 1993

S.O. 2002.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum and Natural Gas through Vegayammapet to Yanam Branch Gas pipeline is to be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for that purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (i) of the Section 3 of the Petroleum & Minerals

pipelines (Acquisition of Right of Users in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. K. G. Basin Project, 12/76, Prakash Nagar, Rajahmundry-533103, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

## SCHEDULE

Branch Gas Pipe Line from Vegayamapeta to Yanam  
from Tatipake-Kakinada Gas Pipe Line Project

District	Mandal	Village	Survey No.	Area (In Hect./ Acres)	Remarks
1	2	3	4	5	6
East Godavari	Tallarevu	Uppongala	153-1 part	0-00-25	
			153-2 part	0-22-50	
			156-3 part	0-06-50	
			156-4 part	0-01-50	
			156-5 part	0-03-00	
			156-10 part	0-01-50	
			156-11 part	0-01-00	
			156-12 part	0-02-00	
			156-15 part	0-02-00	

1	2	3	4	5	6
			158 part	0-01-00	
			161-10 part	0-07-00	
			162 part	0-09-00	
			163 part	0-10-00	
			166-1 part	0-01-50	
			166-2 part	0-03-00	
			166-5 part	0-03-00	
			166-3 part	0-03-00	
			167 part	0-10-00	
			169 part	0-03-00	
			171 part	0-00-50	
			170-2 part	0-04-50	
			170-3 part	0-05-00	
			115-1 part	0-05-50	
			115-2 part	0-11-00	
			114-2 part	0-12-25	
			114-3 part	0-06-75	
			107-1 part	0-01-00	
			107-2 part	0-06-00	
			107-8 part	0-09-50	
			107-10 part	0-03-00	
			107-11 part	0-02-00	
			106-1 part	0-05-00	
			105-1 part	0-04-50	
			105-2 part	0-13-50	
			103-4 part	0-03-50	
			Total	1-84-25	Ares
			Hec.	Or	
			Acs	4-55 Cents	

[No.O-4016/4/93-G.P.]

ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 9 मितम्बर, 1993

का. आ. 2003—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए वेगयम्पेट—यानाम ब्रान्च गैस पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत, पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमि. के. जी. बसीन प्रोजेक्ट राजमंडी - 533 103, आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराने समय किसी भी व्यक्ति को विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।



## अनुसूची

टाटीपाका-काकीनाडा गैस पाइप लेइन वेगयम्मपेट से यानाम  
माल्म लाइन

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे. एकड़ में)	विवरण
ईस्ट गोदावरी	तालारेवु	तुन्करपालेम	69-9 भाग	0-00-25	
			10 भाग	0-00-25	
			11 भाग	0-00-50	
			12 भाग	0-07-50	
			88-1 भाग	0-07-50	
			89-5 भाग	0-05-50	
			90-5 भाग	0-00-50	
			91-1 भाग	0-04-00	
			2 भाग	0-03-50	
			93-1 भाग	0-02-50	
			2 भाग	0-02-50	
			3 भाग	0-05-50	
			5 भाग	0-01-50	
			6 भाग	0-02-00	
			9 भाग	0-03-50	
			94-4 भाग	0-02-50	
			3 भाग	0-04-00	
			98-1 भाग	0-05-50	
				0-59-00 हेक्टे. या	
			एकड़	1-45 1/2 सेन्टम	

[सं. ओ - 14016/4/93 - जा पी]

अध्वंतु सेन, निदेशक

New Delhi, the 9th September, 1993

S.O. 2093.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum and Natural Gas through Vegayamma-  
set to Yam Branch Gas pipeline is to be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for that purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (i) of the Section 3 of the Petroleum & Minerals Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Pipelines (Acquisition of Right of Users in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. K. G. Basin Project, 12/76, Prakash Nagar, Rajahmundry-533103, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

## SCHEDULE

Branch Gas Pipe Line from Vegayamapeta to Yanam  
from Tatipake-Kakinada Gas Pipe Line Project

District	Mandal	Village	Survey No.	Area (In Hect./ Acres)	Remarks
East Godavari	Tallarevu	Sunkarapalem	69-9 part	0-00-25	
			69-10 part	0-00-25	
			69-11 part	0-00-50	
			69-12 part	0-07-50	
			88-1 part	0-07-50	
			89-5 part	0-05-50	
			90-1 part	0-00-50	
			91-1 part	0-04-00	
			91-2 part	0-03-50	
			93-1 part	0-02-50	
			93-2 part	0-02-50	
			93-3 part	0-05-05	
			93-5 part	0-01-50	
			93-6 part	0-02-00	
			93-9 part	0-03-50	
			94-4 part	0-02-50	
			94-3 part	0-04-00	
			98-1 part	0-05-50	
			Total	0-59-00	
				Or	
			AC	1-45½	Cents

[No. O-14016/4/93-G.P.]  
ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1993

का.आ. 2004.—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि गार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए वेगयम्मपेट-यानाम ब्रांच गैस पाइप लाइन परियोजना के अंतर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 क 50) के खंड 3 के उपखंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति संक्षेप प्राधिकारी गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लिमि. के. जी. बसोन प्रोजेक्ट, राजमंड़ी 533 103, आंध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत करना चाहता है।

## अनुसूची

टाटीपाका-काकीनाडा गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट मेहन लायन वेगयम्पेट से  
यानाम ब्रांच लायन

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे. एकड़ में)	विवरण
ईस्ट गोदावरी	तालारेवु	लच्छिपालेम	146—1 भाग	0.05.25	
			2 भाग	0.03.00	
			145—3 भाग	0.12.75	
			147—भाग	0.28.50	
			149—1 भाग	0.02—0	
			2ए भाग	0.00.50	
			150—1 भाग	0.01.40	
			152—भाग	0.01.00	
हेक्टे.				0.54.50	
				या	
				1.35.0	

[सं. ओ.—14016/4/93-जी. पी.]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 9th September, 1993

S.O. 2004.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum and Natural Gas through Vegayampeta to Yanam Brack Gas pipeline is to be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers confirmed by sub-Section (i) of the Section 3 of the Petroleum & Minerals

pipelines (Acquisition of Right of users in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. K. G. Basin Project, 29-7-1/3/1, Opp. Gowthami Library, Rajahmundry-533104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

## SCHEDULE

Branch Gas Pipe Line from Vegayampeta to Yanam  
from Tatipaka-Kakinada Gas Pipe Line Project

District	Mandal	Village	Survey No.	Area (In Hect./ Acres)	Remarks	
East Godavari	Tallarevu	Latchipalem	146-1 part	0-05-25	G.P.	
			146-2 part	0-03-00		
			145-3 part	0-12-75		
			147 part	0-28-50		
			149-1 part	0-02-00		
			149-2 part	0-00-50		
			150-1 part	0-01-50		
			152 part (G.P.)	0-01-00		
			Total			0-54-50
			AC			1-35 Cents

[No. O-14016/4/93-G.P.]

ARDHENDU SEN, Director.

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1993

का. शा. 2005.—जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए वेगयम्पेट—यानाम ब्रांच गैस पाइप लाइन परियोजना के अंतर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खंड 3 के उपखंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एनद्द्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सश्रेष्ठ प्राधिकारी गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लिमि. के. जी. बसीन प्रोजेक्ट, राज-मंजूरी-533 103, आंध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है।

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायिक के माध्यम से अपना मत करना चाहता है।

## अनुसूची

टाटीपाका-काकीनाडा गैस पाइप लाइन वेगयम्पेट से यानाम

ब्रांच लाइन

जनपद	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे. एकड़ में)	विवरण
			110—भाग	0.01.00	
			111—भाग	0.01.50	
			109—5 भाग	0.03—00	
			4 भाग	0.14.50	
			108—7 भाग	0.00.25	
			6 भाग	0.08—00	
			107— भाग	0.01.00	
			105—1 भाग	0.02.00	
			2 भाग	0.17—00	
			102—1 भाग	0.05.00	
			4 भाग	0.05.00	
			103—2 भाग	0.01.00	
			3 भाग	0.07.50	
			4 भाग	0.03.00	
			121—2 भाग	0.10.00	
			1 भाग	0.00.50	
पांडिचेरी	यानाम	मेड्टकुरु	98—भाग	01.50	
			93—5 भाग	0.03.00	
			हेक्टे.	0.85.25	
				या	
			A.C.	2.10 1/2 Cents.	

[सं. आ. 14018/4/93-जी. पी.]

अर्घेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 9th September, 1993

S.O. 2005.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum and Natural Gas through Vigyampate to Yanam Branch Gas pipeline is to be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (i) of the Section 3 of the Petroleum & Minerals

pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1952 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of User therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. K. G. Basin Project, 29 7-1/3/1, Opp. Gowthami Library, Rajamundry-533104, Andhra Pradesh.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

## SCHEDULE

Branch Gas Pipe Line from Vegayamapeta to Yanam  
from Tatipake-Kakinada Gas Pipe Line Project

District	Mandal	Village	Survey Nos.	Area (In Hect Acres)	Remarks
Pondicherry	Sub-Taluk :—Yanam	Mettakur	110 part (G.P.)	0-01-00	G.P.
			111 part (G.P.)	0-01-50	G.P.
			109-5 part	0-03-00	
			109-4 part	0-14-50	
			108-7 part	0-00-25	
			108-6 Part	0-08-00	
			107 part	0-01-00	G.P.
			105-1 part	0-02-00	
			105-2 part	0-17-00	
			102-1 part	0-05-50	
			102-4 part	0-05-00	
			103-2 part	0-01-00	
			103-3 part	0-07-50	
			103-4 part	0-03-00	
			121-2 part	0-10-00	
			121-1 part (G.P.)	0-00-50	G.P.
			98 part (G.P.)	0-01-50	G.P.
			93-5 part	0-03-00	
			Total	0-85-25	
				Or	
				(AC 2-10 ½ Cents)	

[No. O-14016/4/93-G.P.]  
ARDHENDU SEN, Director

## CORRIGENDUM

New Delhi, the 9th September, 1993

S.O. 2006.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, No. S.O. 424, dated 6th March, 1993, published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), at pages 546 to 547 issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared that the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines for the transport of petroleum should be acquired;

And whereas, it has been brought to the notice of the Central Government that certain errors of printing nature

have occurred in the publication of the said notification in the Gazette;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby amends the Schedule appended to the said notification as follows:

at page 547, in village Khanal Kaln, in column 3, for killa No. '77/18' read '77/10';

And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of the said section, the Central Government directs that the right of user in the lands shall instead of vesting in the Central Government, vest free from all encumbrances, in the Indian Oil Corporation Limited.

[No. R-31015/23/93-O.R-I]  
KULDIP SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1993

का.आ. 2007—केन्द्रीय सरकार ने पैट्रोलियम और खनिज पार्श्वलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन जारी और भारत के राजपत्र भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड(ii) पृष्ठ संख्या 551 से 608 पर प्रकाशित भारत सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 430, 431, 432, 433, 434, 435 और 436 तारीख 06 मार्च, 1993 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने घोषित किया कि उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पार्श्वलाईन बिछाने के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाये।

और केन्द्रीय सरकार के ध्यान में लाया गया है कि राजपत्र में प्रकाशित उपरोक्त अधिसूचना में मुद्रण संबंधी कुछ त्रुटियां हैं।

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है:—

का.आ. 430 :

पृष्ठ संख्या 551 : अधिसूचना के 7वें लाईन में का.आ. '695' के स्थान पर '696' पढ़ें।

पृष्ठ संख्या 552 : सुमेल गांव के खसरा नम्बर 68 के सामने क्षेत्रफल के ऐयर स्तम्भ के नीचे '04' के स्थान पर '03' पढ़ें।  
गांव का नाम स्तम्भ के नीचे 'जयसिंहपुरा खोर' के स्थान पर 'जयसिंहपुरा खोर' पढ़ें।

पृष्ठ संख्या 553 : जयसिंहपुरा खोर गांव के खसरा नम्बर 2093 के सामने क्षेत्रफल के ऐयर स्तम्भ के नीचे '60' के स्थान पर '06' पढ़ें।

खसरा नम्बर 2162 के सामने क्षेत्रफल के ऐयर स्तम्भ के नीचे '20' के स्थान पर '10' पढ़ें।

का.आ. 431 :

पृष्ठ संख्या 555 : अनुसूची में तहसील के सामने 'जमधा रामगढ़' के स्थान पर 'जमधा रामगढ़' पढ़ें।

अनुसूची में गांव का नाम स्तम्भ में 'गांव का नाम' के स्थान पर 'गांव का नाम' पढ़ें।

पृष्ठ संख्या 556 : भानपुर कलां गांव के खसरा नम्बर 445 के सामने क्षेत्रफल के वर्गमीटर स्तम्भ के नीचे '04' के स्थान पर '05' पढ़ें।  
यजबगढ़ उर्फ हाडी का बास गांव के खसरा नम्बर 17/1 के सामने क्षेत्रफल के ऐयर स्तम्भ के नीचे '85' के स्थान पर '65' पढ़ें।

का.आ. 432 :

पृष्ठ संख्या 559 : गांव का नाम स्तम्भ के नीचे 'पाथरोडी' के स्थान पर 'पाथरोडी' पढ़ें।

पृष्ठ संख्या 561 : राहेड़ा गांव के खसरा नम्बर 342 के सामने क्षेत्रफल के हेक्टर स्तम्भ के नीचे '5' के स्थान पर '0' पढ़ें।

का.आ. 433 :

पृष्ठ संख्या 573 : अधिसूचना के प्रथम पंक्ति में का.आ. '493' के स्थान पर '433' पढ़ें।

पृष्ठ संख्या 574 : गांव का नाम स्तम्भ के नीचे 'वानपुरा-(क्रमशः)' के स्थान पर 'जवानपुरा(क्रमशः)' पढ़ें।

पृष्ठ संख्या 576 : भाबरू गांव के खसरा नम्बर स्तम्भ के नीचे पंक्ति नम्बर 12 में '2786' के स्थान पर '2886' एवं पंक्ति नम्बर 13 में '2787' के स्थान पर '2887' पढ़ें।

पृष्ठ संख्या 577 : गांव का नाम स्तम्भ के नीचे 'अटिला-क्रमशः' के स्थान पर 'आतेला-क्रमशः' पढ़ें।

वागावास अहीरन गांव के खसरा नम्बर 1066 के सामने क्षेत्रफल के वर्गमीटर स्तम्भ के नीचे '08' के स्थान पर '00' पढ़ें।

पृष्ठ संख्या 578 : वागावास अहीरन गांव के खसरा नम्बर 1160 के सामने क्षेत्रफल के वर्गमीटर स्तम्भ के नीचे '50' के स्थान पर '56' पढ़ें।

खसरा नम्बर स्तम्भ के नीचे '1312' के स्थान पर '1313' पढ़ें।

का.आ. 434 :

पृष्ठ संख्या 583 : मनोहरपुर गांव के खसरा नम्बर 4355 के सामने क्षेत्रफल के हेक्टर स्तम्भ के नीचे '9' के स्थान पर '0' पढ़ें।

पृष्ठ संख्या 585 : कांठ गांव के खसरा नम्बर स्तम्भ के नीचे '173' के स्थान पर '171' पढ़ें।

का.आ. 435 :

पृष्ठ संख्या 591 : अनुसूची के स्तम्भ संख्या 2 में 'ग्रामेर नम्बर' के स्थान पर 'खसरा नम्बर' पढ़ें।

ग्रामेर गांव के खसरा नम्बर 4820 के सामने क्षेत्रफल के वर्ग-मीटर स्तम्भ के नीचे '14' के स्थान पर '15' पढ़ें। खसरा नम्बर 5284 के सामने क्षेत्रफल के ऐयर स्तम्भ के नीचे '03' के स्थान पर पर '04' पढ़ें।

पृष्ठ संख्या 592 : नांगल सुसावतान गांव के खसरा नम्बर 473 के सामने क्षेत्रफल के ऐयर स्तम्भ के नीचे '01' के स्थान पर '10' पढ़ें। खसरा नम्बर 495 के सामने क्षेत्रफल के वर्गमीटर स्तम्भ के नीचे '7 भ' के स्थान पर '70' पढ़ें।

पृष्ठ संख्या 593 : खोरा मीना गांव के खसरा नम्बर 429 के सामने क्षेत्रफल के वर्ग-मीटर स्तम्भ के नीचे '17' के स्थान पर '15' पढ़ें। खसरा नम्बर 1207 के सामने क्षेत्रफल के ऐयर स्तम्भ के नीचे '04' के स्थान पर '07' पढ़ें।

पृष्ठ संख्या 595 : कालवाड कला एवं खुर्द गांव के खसरा नम्बर स्तम्भ के नीचे '188/298' के स्थान पर '178/298' पढ़ें।

पृष्ठ संख्या 596 : चन्दवाजी गांव के खसरा नम्बर 14 के सामने क्षेत्रफल के वर्गमीटर स्तम्भ के नीचे '79' के स्थान पर '76' पढ़ें।

बीलपुर सुन्दरपुरा गांव के खसरा नम्बर स्तम्भ के नीचे '433' के स्थान पर '413' पढ़ें।

का.आ. 436 :

पृष्ठ संख्या 601 : अनुसूची में तहसील के सामने 'बहुरोड' के स्थान पर 'बहरोड' पढ़ें।

पृष्ठ संख्या 602 : श्यामपुर गांव के खसरा नम्बर 242 के सामने क्षेत्रफल के वर्गमीटर

स्तम्भ के नीचे '03' के स्थान पर '02' पढ़ें।

पृष्ठ संख्या 604 : नंगला रुंध गांव के खसरा नम्बर 323 के सामने क्षेत्रफल के ऐयर स्तम्भ के नीचे '07' के स्थान पर '97' पढ़ें।

गांव का नाम स्तम्भ के नीचे 'कोलिला जोग' के स्थान पर 'कोलिला जोगा' पढ़ें।

पृष्ठ संख्या 608 : कांकर गांव के खसरा नम्बर स्तम्भ के नीचे '885' के स्थान पर '875' पढ़ें।

यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि के उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय सभी बिल्लिंगमों से मुक्त होकर, इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

[संख्या आर.-31015/24/93-ओ.आर.-I]

कुलदीप सिंह, अवसर सचिव

New Delhi, the 9th September, 1993

S.O. 2007.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, No. S.O. 429, 430, 432, 433, 434, 435 and 436 dated the 6th March, 1993, published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), at pages 551 to 613, issued under sub-section (1) of section 6 of Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared that the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines for the transport of petroleum should be acquired;

And whereas, it has been brought to the notice of the Central Government that certain errors of printing nature have occurred in the publication of the said notification in the Gazette;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby amends the Schedule appended to the said notification as follows:

at page 551, in village Palri Meena, against Khasra No. 187, in column 5, for "88" read "84";

at Page 554, in village Jaisinzhpura Khor, against Khasra No. 1459/2391, in column 4, for "08" read "09"; in column 2, for Khasra No. "2048/2598" read "2248/2598";

at Page 568, in village Kidarode, against Khasra No. 636, in column 5, for "53" read "30", in village Pathredl against Khasra No. 130, in column 5, for "00" read "08" against Khasra No. 131, in column 5, for "48" read "42";

at Page 569, in village Goverdhanpura, against Khasra No. 1448, in column 5, for "33" read "32" in village Kanwarpura against Khasra No. 967, in column 5, for "76" read "96"; in village Putli, against Khasra No. 28, in column 5, for "38" read "98";

at Page 570, in village Putli, against Khasra No. 426, in column 5, for "722" read "70";

at Page 573, in village Morda, against Khasra No. 391, in column 5, for "9" read "96"; against Khasra No. 394, in column 5, for "99" read "90"; against Khasra No. 398, in column 5, for "00" read "90"; against Khasra No. 516, in column 5, for "2" read "24"; against Khasra No. 576, in column 4, for "12" read "07"; in column 5, for "96" read "00" after Khasra No. 576, in column 2, insert "577"; in column 3, insert "0"; in column 4, insert "12"; in column 5, insert "96";

at Page 580, in village Bhabru, against Khasra No. 725, in column 4, for "11" read "01"; against Khasra No. 877, in column 4, for "90" read "10"; against Khasra No. 2748, in column 5, for "4" read "94";

at Page 581, in village Bhabru, against Khasra No. 3002, in column 5, for "36" read "86"; against Khasra No. 3003, in column 5, for "48" read "36"; against Khasra No. 3006, in column 5, for "16" read "48"; against Khasra No. 3007, in column 5, for "62" read "16"; against Khasra No. 3012, in column 5, for "38" read "62"; against Khasra No. 3415, in column 5, for "00" read "38"; in village Aantela, in column 2, after Khasra No. 3271, insert Khasra No. "3272"; in village Bagawas Ahiran, against Khasra No. 828, in column 5, for "95" read "96";

at Page 582, in village Bagawas Ahiran, in column 2, for Khasra No. "2014" read "2041";

at Page 587, in village Manoharpur, against Khasra No. 3288, in column 5, for "90" read "96"; against Khasra No. 3400, in column 5, for "95" read "96";

at Page 588, in village Manoharpur, in column 2, for Khasra No. "5470" read "5460"; in village Neethara, against Khasra No. 651, in column 4, for "96" read "03";

at Page 589, in village Lakhnee, against Khasra No. 190, in column 4, for "08" read "03"; in village Kant, in column 2, for Khasra No. "56" read "46"; against Khasra No. 258, in column 4, for "04" read "02";

at Page 590, in column 1, for "Jaoja Khurd Urf Vishanpura, read "Jaoje Khurd Urf Vishanpura"; in so amended village Jaoje Khurd Urf Vishanpura, against Khasra No. 1026, in column 5, for "93" read "98";

at Page 597, in village Amber, against Khasra No. 4600, in column 4, for "04" read "00"; in column 2, for Khasra No. "5571" read "5577";

at Page 598, in village Kukas, in column 2, after Khasra No. 758 and before Khasra No. 869, insert Khasra No. "759";

at Page 599, in village Svari, in column 2, for Khasra No. "69/1" read "69";

at Page 600, in village Salarwas, against Khasra No. 55, in column 4, for "09" read "07"; against Khasra No. 80, in column 4, insert "09";

at Page 608, in village Jainpurwas, against Khasra No. 97, in column 3, for "02" read "0";

at Page 609, in village Kalyanpura, against Khasra No. 539, in column 3, for "12" read "0"; in village Jaguwas, against Khasra No. 61, in column 5, for "6" read "20"; against Khasra No. 63, in column 5, for "22" read "26";

at Page 612, in village Sasedi, in column 2, for Khasra No. "685" read "658"; for Khasra No. "658" read "685"; in village Jonaycha Khurd, against Khasra No. 111, in column 5, for "23" read "28";

at Page 613, in village Sirvani, against Khasra No. 653, in column 4, for "28" read "08"; against Khasra No. 654, in column 5, for "14" read "04";

And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of the said section, the Central Government directs that the right of user in the land shall instead of

vesting in the Central Government, vest free from all encumbrances, in the Indian Oil Corporation Limited.

[No. R-31015/24/93-O.R.I]

KULDIP SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1993

का. आ. 2008.—केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 217 तारीख 06 फरवरी 1993 द्वारा पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन विछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी,

और राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता की तारीख 28 फरवरी, 1993 को उपलब्ध करा दी गई थी,

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार की अपनी रिपोर्ट दे दी है,

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है।

यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए सभी विभागों से मुक्त, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

तहसील : फागी	जिला : जयपुर	राज्य : राजस्थान	क्षेत्रफल		
गांव का नाम	खसरा नं.	हैक्टर	आर	वर्गमीटर	
	1	2	3	4	5
निमेटड़ा	1363	0	00	68	
	1364	0	01	14	
	1369	0	00	68	

[संख्या आर-31015/20/93-ओ.आर.-I]

कुलदीप सिंह, अवर सचिव



New Delhi, the 9th September, 1993

S.O. 2008.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No. S. O. 217, dated the 6th February, 1993 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transport of petroleum;

And whereas copies of the Gazette notification has been made available to the public on the 28th February 1993;

And whereas the Competent Authority in pursuance of sub-section (1) of section 6 of the said Act has made his report to the Central Government;

And whereas the Central Government after considering the said report is satisfied that the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification should be acquired;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification are hereby acquired;

And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of the said section, the Central Government hereby directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest, free from all encumbrances, the Indian Oil Corporation Limited,

## Schedule

Tehsil : Phagi District : Jaipur State : Rajasthan

## Area

Name of Village	Khasra No.	Hec-	Are	Centi-
		tare		are
1	2	3	4	5
Nimera	1363	0	00	68
	1364	0	01	14
	1369	0	00	68

[No. R-31015/20/93-O.R.]

KULDIP SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1993

का. आ. 2009.—केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 218 तारीख 06 फरवरी, 1993 द्वारा पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी,

और राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता की तारीख

28 फरवरी, 1993 को उपलब्ध करा दी गई थी,

2004 GI/93-6.

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्टें दे दी है,

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है।

यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय सभी विरहणों से मुक्त, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

## अनुसूची

तहसील : किशनगढ़ जिला : अजमेर राज्य : राजस्थान

## क्षेत्रफल

गांव का नाम	खसरा नं.	हेक्टर	आर	वर्गमीटर
1	2	3	4	5
दसूक	144/2	0	01	30
	145	0	00	08
	146	0	00	60
	149	0	00	52

[संख्या:आर-31015/20/93-ओ.आर.-I]

कुलदीप सिंह, अवसर सचिव

New Delhi, the 9th September, 1993

S.O. 2009.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No. S. O. 218, dated the 6th February, 1993 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transport of petroleum;

And whereas copies of the Gazette notification has been made available to the public on the 28th February 1993;

And whereas the Competent Authority in pursuance of sub-section (1) of section 6 of the said Act has made his report to the Central Government;

And whereas the Central Government after considering the said report is satisfied that the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification should be acquired;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification are hereby acquired;

And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of the said section, the Central Government hereby directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest, free from all encumbrances, in the Indian Oil Corporation Limited.

**SCHEDULE**

Tehsil : Kishangarh District : Ajmer State : Rajasthan

Name of Village	Khasra No.	Area		
		Hec-tare	Are Centi-are	
1	2	3	4	5
Dhasuk	144/2	0	01	30
	145	0	00	08
	146	0	00	60
	149	0	00	52

[No. R-31015/20/93-O.R.-I]  
KULDIP SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1993

का. आ. 2010.—केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 224 में 225 तारीख 6 फरवरी, 1993 द्वारा पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी,

और राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 23 फरवरी, 1993 को उपलब्ध करा दी गई थी,

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है,

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार प्रदान करने की घोषणा करती है।

यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय सभी विलगनों में मुक्त, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

**अनुसूची**

महमूल—पाकी

जिला—पाकी

राज्य : राजस्थान

**क्षेत्रफल**

गांव का नाम	खसरा नं.	हेक्टर	आर	बर्गमीटर
1	2	3	4	5
मोरिया	64	0	00	30
	70	0	02	20
कीरवा	106	0	01	80
	103	0	00	50
	102	0	00	20

[संख्या आर-31015/20/93-ओ.आर.-I]

कुलदीप सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 9th September, 1993

S.O. 2010.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No. S.O. 224 to 225, dated the 6th February, 1993 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines for the transport of petroleum;

And whereas copies of the Gazette notification has been made available to the public on the 28th February, 1993;

And whereas the Competent Authority in pursuance of sub-section (1) of section 6 of the said Act has submitted his report to the Central Government;

And whereas the Central Government after considering the said report is satisfied that the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification should be acquired;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification are hereby acquired;

And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of the said section, the Central Government hereby directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest, free from all encumbrances, in the Indian Oil Corporation Limited.

## SCHEDULE

New Delhi, the 9th September, 1993

Tehsil : Pali	District : Pali	State : Rajasthan	Area		
Name of Village	Khasra No.		Hec- tare	Arc are	Centi- are
1	2		3	4	5
Moriya	64		0	00	30
	70		0	02	20
Kirwa	106		0	01	80
	103		0	00	50
	102		0	00	20

[No. R-31015/20/93-O.R.-1]  
KULDIP SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1993

का.घा. 2011 :- केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि (उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे हमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिनूचना संख्या का.घा. 2849 तारीख 14 नवम्बर, 1992 द्वारा पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिनूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार के अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्ति की घोषणा की थी,

और राजपत्रित अधिनूचना की प्रतियाँ जना को तारीख 24 नवम्बर, 1992 को उपलब्ध करा दी गई थी,

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम अधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है,

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इस अधिनूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम किया जाए,

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिनूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार अधिनियम करने की घोषणा करती है।

यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए सभी विस्तारों में मुक्त, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

## अनुसूची

तहसील : आमेर	जिला : जयपुर	राज्य : राजस्थान
गांव का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल
		हेक्टेयर
1	2	3
4	5	
कुकास	945	0 00 17
	952	0 01 10
	954	0 00 33

[संख्या आर-31015/17/93-ओ.आर.-1]  
कुलदीप सिंह, अवर सचिव

S.O. 2011. Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No. S.O. 2849, dated the 14th November, 1992 issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines for the transport of petroleum ;

And whereas copies of the Gazette notification has been made available to the public on the 24th November, 1992;

And whereas the Competent Authority in pursuance of sub-section (1) of section 6 of the said Act has made his report to the Central Government;

And whereas the Central Government after considering the said report is satisfied that the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification should be acquired;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification are hereby acquired;

And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of the said section, the Central Government hereby directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest, free from all encumbrances, in the Indian Oil Corporation Limited ;

## SCHEDULE

Tehsil : Amber	District : Jaipur	State : Rajasthan	Area		
Name of Village	Khasra No.		Hec- tare	Arc are	Centi- are
1	2		3	4	5
Kukas	945		0	00	17
	952		0	01	10
	954		0	00	33

[No. R-31015/17/93-OR-I]

KULDIP SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1993

का.घा. 2012 :- केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे हमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिनूचना संख्या का.घा. 2850 तारीख 14 नवम्बर, 1992 द्वारा पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिनूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार के अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्ति की घोषणा की थी,

और राजपत्रित अधिनूचना की प्रतियाँ जना को तारीख 24 नवम्बर, 1992 को उपलब्ध करा दी गई थी,

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम अधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है,

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इस अधिनूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम किया जाए,

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संगत अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है।

यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार निहित होने के कारण सभी विप्लवमयी से मुक्त, हडियन आबल कॉपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

## अनुसूची

तहसील : विराटनगर	जिला : अजमेर	राज्य : राजस्थान		
क्षेत्रफल				
गांव का नाम	खसरा नं.	हेक्टेयर	आर	वर्गमीटर
1	2	3	4	5
जवानपुरा	1056/2192	0	02	17
	1059	0	00	33

[संख्या आर-31015/17/93-ऑ.आर.-1]

कुलदीप सिंह, प्रवर सचिव

New Delhi, the 9th September, 1993

S.O. 2012.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. 2850 dated the 14th November, 1992, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines for the transport of petroleum,

And whereas copies of the Gazette notification has been made available to the public on the 24th November, 1992;

And whereas the Competent Authority in pursuance of sub-section (1) of section 6 of the said Act has made his report to the Central Government;

And whereas the Central Government after considering the said report is satisfied that the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification should be acquired;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification are hereby acquired

And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of the said section, the Central Government hereby directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest, free from all encumbrances, in the Indian Oil Corporation Limited;

## SCHEDULE

Tehsil : Viratnagar District : Jaipur State : Rajasthan				
Area				
Name of Village	Khassra No.	Hec-	Are	Centi-
1	2	3	4	5
Jawanpura	1056/2192	0	02	17
	1059	0	00	33

[No. R-31015/17/93-OR-1]

KULDEEP SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1993

का आ 2813—केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और नैसर्गिक गैस पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस अन्वेषण की अधिसूचना संख्या का आ 2851 तारीख 14 नवंबर 1992 द्वारा पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना से अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने प्राथम्य की घोषणा की थी,

और संबंधित अधिसूचना की प्रतियां भेजना को तारीख 21 नवंबर 1992 को बतलाना करा दी गई थी,

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है,

अब केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संगत अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए,

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संगत अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है।

यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार निहित होने के कारण सभी विप्लवमयी से मुक्त, हडियन आबल कॉपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

## अनुसूची

तहसील : बहुराड़	जिला : राजमेर	राज्य : राजस्थान		
क्षेत्रफल				
गांव का नाम	खसरा नं.	हेक्टेयर	आर	वर्गमीटर
1	2	3	4	5
जेनपुराबास	114	0	00	84
	115	0	00	82
	120	0	00	84

[संख्या आर-31015/17/93-ऑ.आर.-1]

कुलदीप सिंह, प्रवर सचिव

New Delhi, the 9th September, 1993

S.O. 2013.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. 2851 dated the 14th November, 1992, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transport of petroleum;

And whereas copies of the Gazette notification has been made available to the public on the 24th November, 1992;

And whereas the Competent Authority in pursuance of sub-section (1) of section 6 of the said Act has made his report to the Central Government;

And whereas the Central Government after considering the said report is satisfied that the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification should be acquired;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification are hereby acquired

And further in exercise of the powers conferred by subsection (4) of the said section, the Central Government hereby directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest, free from all encumbrances, in the Indian Oil Corporation Limited.

## SCHEDULE

Tehsil : Behror		District : Alwar	State : Rajasthan		
Name of Village	Khasra No.	Area			
		Hec-tare	Are	Centi-are	
1	2	3	4	5	
Jainpurwas	114	0	00	84	
	115	0	00	82	
	120	0	00	84	

[No. R-31015/17/93-OR-I]

KULDIP SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1993

का. आ. 2014 :—केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 30) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 140 तारीख 23 जनवरी, 1993 द्वारा पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन के अन्तर्गत प्राप्ति की घोषणा की गई ;

और राजस्थान अधिसूचना की प्रतियों जनता की तारीख 1 फरवरी, 1993 को उपलब्ध करा दी गई की ;

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण सक्षम प्राधिकार ने केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है .

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से सम्बन्धित भूमि में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाय ,

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जित करने की घोषणा करता है ;

यह और कि केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि के

उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए सभी विस्तारों में मुक्त, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

कहासा नं. बाबल	जिला : गिरवाही	राज्य : हरियाणा				
गांव का नाम	कहासा नं.	पु.सं.सं. नं./ किला नं.	क्षेत्रफल	हक्टर	आर	वर्ग- मीटर
1	2	3	4	5	6	
खर्वाला	50	10 1/1	0	06	07	
टाकरी	48	22 8 33 24 88 14 15	0 0 0	13 01 13 00	41 52 15 25	
धारण	7	20 7 25 10 41 23 46 8/1/2	0 0 0 0	06 10 10 01	32 61 62 77	
भरगावा	4	51 9 52 18/2/1 18/2/2	0 0	05 04 06	06 55 83	
मुल्ला	2	23 20 24 22/1 22/2 33 4/2 7 8 34 1/1 45 11 47 25 48 9	0 0 0 0 0 0 0 0	09 01 08 00 11 13 07 07 05 06	86 26 85 76 39 91 58 08 82 83	

1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
सहस्राल अञ्चल	जिला रोहतक	राज्य हरियाणा				इसमार्कल 9 बिक्रम—जारी					
कीका	247	29				5		0	11	63	
		23/2	0	08	32	6		0	00	51	
अहरी	246	55				7		0	13	15	
		19/2	0	03	29	13		0	06	07	
अमदपुर खेड़ा	241	52				14		0	07	33	
		4/2	0	02	28	18		0	13	41	
मण्डरोली	240	64				19		0	01	01	
		19	0	11	13	22/1		0	03	04	
बान्धपुर	239	25				23		0	00	51	
		16/2	0	07	59	44					
		25/1	0	11	38	2		0	06	07	
		25/2	0	00	06	11		0	08	60	
		26				12		0	01	01	
		1	00	11	38	20		0	11	38	
		10	0	11	38	21		0	11	38	
		11	0	08	10	45					
		20	0	02	53	25		0	00	07	
		40				49					
		5/1	0	11	64	5		0	05	56	
		6/2	0	09	86	6		0	11	38	
		7/1	0	01	01	15		0	11	38	
		14	0	06	07	10		0	10	88	
		15/1	0	06	07	24		0	01	01	
		16	0	04	05	25		0	10	62	
		17/1	0	08	09	50					
		24/2	0	09	86	1		0	06	58	
		25/1	0	00	51	10		0	00	25	
विजरीद	260	21				73					
		18	0	09	36	4		0	08	09	
		19	0	02	78	5		0	04	05	
		23	0	12	14	103					
		32				3		0	07	59	
		3	0	09	36	4		0	04	55	
		4	0	02	78	7		0	00	51	
		7	0	01	52	8		0	10	88	
		8	0	13	15	13		0	11	13	
		12	0	08	60	124					
		13	0	03	29	22		0	07	59	
		19	0	10	62	23		0	04	51	
		20	0	04	05	136					
		21	0	11	13	2		0	10	12	
						3		0	02	02	
मिलाली पाना जामम	262	3				39					
		6	0	12	39	20/2/2		0	04	55	
अञ्चल	100	296	5			105					
		9/2	0	10	62	20/2/1		0	00	06	
गुरावर	106	79				140					
		23	0	03	80	24		0	00	08	
		87				213					
		23	0	08	35	1		0	02	02	
सहस्राल रोहतक						2		0	09	11	
कुलाला	16	1388	0	07	73	9/1		0	02	53	
इसमार्कल 9 बिक्रम	38	21				9/2		0	01	26	
		4	0	02	02	10		0	06	83	

1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
राजकी	54	21				सारांश		24/1	0	02	03
		9/1	0	10	63			16			
		9/2	0	00	51			15/1	0	01	01
		79						27			
		25/2	0	03	54			8/2	0	02	53
		89						15	0	02	02
		1	0	01	01			16	0	08	85
		116						28			
		23	0	01	05			19	0	02	28
		160						20	0	13	41
		22/1	0	11	38	कसोर	102	78			
		10						11	0	00	25
पोलंगी	53	4/4	0	00	25			19	0	09	36
		14/1	0	01	26			20	0	13	66
								82			
तहसील गुरुवा		जिला कौशल						8/2	0	03	29
खेड़ी गुलाम अली	83	4						83			
		11	0	09	11			19/2/2	0	04	55
		13						20/2	0	13	66
		21	0	08	60	तहसील रेवाड़ा					
उभेवपुर	82	61				जिला रेवाड़ा					
		1	0	02	53	जिलावास	143	12			
		2/1	0	04	81			20	0	12	64
		2/2	0	06	58			14			
		3	0	00	10			8/1	0	11	13
								25			
प्रभात	81	17						1/2	0	04	55
		17/1	0	03	54	भावावास	146	108			
अनेवपुर	93	12						8/1	0	07	84
		20	0	04	30			9/2	0	12	39
		21	0	10	12			107			
		22	0	08	09			8/2	0	02	78
		14						8/3	0	06	83
		11	0	00	51			13/1	0	02	78
		20	0	03	29			108			
		15						11	0	00	25
		2	0	07	59			14/1	0	07	34
		3	0	10	12			14/2	0	02	28
		6	0	00	02			15	0	12	14
		7	0	12	90			20	0	12	14
		8	0	05	50			110			
		14	0	02	78			23	0	02	02
		15	0	14	16			119			
		16	0	01	01			17	0	02	02
लदागा अक्	97	57				भम्बाड़ी	150	8			
		11	0	00	25			17/1	0	09	86
		66						9			
		8/2	0	05	06			23	0	00	25
		107						14			
		4	0	05	82			1	0	00	25
		108						3	0	13	40
		1	0	06	07			4	0	06	07
		9	0	13	91			7/1	0	05	82
		205/2	0	12	65			7/2	0	05	82
								14	0	11	63
सारांश	101	15						16	0	06	32
		21/1	0	00	25			17	0	05	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
मम्बराह --जाल	25	0	11	61	रोहडाई	230	61				
	17					15		0	06	58	
	5	0	11	38		16/1/2		0	06	07	
मटुवास	148	29				16/2/2		0	03	01	
	22/2/2/1	0	02	28		16/2/3		0	00	76	
	37				हंसावास	240	38				
	20	0	13	41		9/1		0	02	02	
	22	0	10	86		9/2		0	09	61	
	38				काहूतोरो	242	34				
	3/2/1	0	04	05		19/1		0	04	55	
	7/2/1	0	09	86		18/2		0	08	09	
	14/1	0	05	31		22/1		0	06	07	
बालिबाकी	133	6				22/2		0	00	25	
	10	0	07	34		23/1		0	01	26	
	11	0	09	86							
	12	0	06	58							
	18	0	05	82							
	19	0	10	12							
	23	0	10	88							
	24/1	0	01	26							
	24/2	0	03	79							
	7										
	5/2	0	04	81							
	6/1	0	09	86							
	15										
	2	0	01	01							
बृमैनपुर	134	46									
	9/2	0	01	26							
	11/2	0	07	33							
	12	0	09	86							
कुलपुर मोला	131	26									
	2/2/1	0	01	52							
बासा माऊरा	126	15									
	21/3	0	04	55							
बासाबास	117	17									
	23	0	11	38							
	26										
	2	0	05	06							
	3	0	07	08							
	8	0	00	51							
	9	0	09	36							
	12	0	07	84							
	13/2	0	01	77							
	26	0	02	27							
बृहपुर	116	16									
	1/1	0	05	05							
	28										
	17/2	0	03	29							
गोकुलगाव	119	74									
	20	0	09	86							
रोहडाई	230	60									
	11/1	0	05	31							
	11/2	0	00	03							

[ संख्या अतः ; 31015/15/39 जो अतः-1 ]

कुलदीप सिंह, जबर मन्त्रि

New Delhi, the 9th September, 1993

S.O. 2014.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O. 140 dated the 23rd January, 1993, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transport of petroleum;

And whereas the copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 1st February, 1993;

And whereas the Competent Authority in pursuance of sub-section (1) of section 6 of the said Act has made his report to the Central Government;

And whereas the Central Government after considering the said report is satisfied that the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification should be acquired;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification are hereby acquired;

And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of the said section, the Central Government hereby directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest, free from all encumbrances, in the Indian Oil Corporation Limited.

#### SCHEDULE

Tehsil : Bawal District: Rewari State : Haryana

Name of Village	Hadbast No.	Mustateel/ Killa No.	Area		
			Hec- tare	Are	Centi- tare
1	2	3	4	5	6
Khandora	50				
		10	0	06	07
		1/1			



[illegible]



	1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6
			107							110			
			4	0	05	82				23	0	02	02
			108							119			
			1	0	06	07				17	0	02	02
			9	0	13	91		Bhambadi	150	8			
			205/2	0	12	65				17/1	0	09	86
Taran Wali	101		15							9			
			21/1	0	00	25				23	0	00	25
			24/1	0	02	03				14			
			16							1	0	00	25
			15/1	0	01	01				3	0	13	40
			27							4	0	06	07
			8/2	0	02	53				7/1	0	05	82
			15	0	02	02				7/2	0	05	82
			16	0	08	85				14	0	11	63
			28							16	0	06	32
			19	0	02	28				17	0	05	57
			20	0	13	41				25	0	11	63
Kasorc	102		78					Jatuwas	148	17			
			11	0	00	25				5	0	11	38
			19	0	09	36				29			
			20	0	13	66				22/2/2/1	0	02	28
			82							37			
			8/2	0	03	29				20	0	13	41
			83							22	'	10	86
			19/2/2	0	04	55				38			
			20/2	0	18	66				3/2/1	0	04	05
										7/2/1	0	09	86
										14/1	0	05	31
										6			
										10	0	07	34
										11	0	09	86
										12	0	06	58
										18	0	05	82
										19	0	10	12
										23	0	10	88
										24/1	0	01	26
										24/2	0	03	79
										7			
										5/2	0	04	81
										6/1	0	09	86
										15			
										2	0	01	01
										46			
										9/2	0	01	26
										11/2	0	07	33
										12	0	09	86
										26			
										2/2/1	0	01	52
										15			
										21/3	0	04	55
										17			
										23	0	11	38

1	2	3	4	5	6
		26			
		2	0	05	06
		3	0	07	08
		8	0	00	51
		9	0	09	36
		12	0	07	84
		13/2	0	01	77
		26	0	02	27
Bhudpur	116	16			
		1/1	0	05	05
		28			
		17/2	0	03	29
Gokal Garh	119	74			
		20	0	09	86
Rohrai	230	60			
		11/1	0	05	31
		11/2	0	00	03
		61			
		15	0	06	58
		16/1/2	0	06	07
		16/2/2	0	03	04
		16/2/3	0	00	76
Hansawas	240	38			
		9/1	0	02	02
		9/2	0	09	61
Kahnori	242	34			
		19/1	0	04	55
		18/2	0	08	09
		22/1	0	06	07
		22/2	0	00	25
		23/1	0	01	26

[No. R-31015/15/93-O.R.-I]

K. D. P. SINGH, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 1993

का.भा. 2015.—केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् (जुन/व) नियम, 1975 के नियम 2 के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 की संख्या 48) की धारा 3 के उप खंड 3(i) के खंड (क) के अन्तर्गत गठित की गई केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् के चुनाव कराने के लिए राजस्वधार चुनाव अधिकारी नियुक्त करती है।

क्रम राज्य का नाम नाम, पदनाम और चुनाव अधिकारी का नाम

1	2	3
1.	माध्य प्रदेश	डॉ. ए. लक्ष्मीकांत रेड्डी, निरीक्षक, बोर्ड ऑफ इन्विजम मेडिसिन, 3/3/1979, कुट्टीगुडु, काबी-गुवा, हैदराबाद, माध्य प्रदेश।

1	2	3
2.	दिल्ली	डॉ. भार. पी. वसिष्ठ, उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन, ई-ब्लॉक सरस्वती भवन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
3.	गुजरात	बैद्य जी. एच. साहूने, पंच कर्मा विभाग, राजकीय प्रायुर्वेद अस्पताल, सेक्टर-22, गांधी नगर, गुजरात।
4.	हरियाणा	डॉ. पी. के. जैन, निदेशक, प्रायुर्वेद, एस. पी. ओ. - नं. 3, सेक्टर-7, नंजीगढ़, हरियाणा।
5.	हिमाचल प्रदेश	डॉ. जी. भार. आचार्य, सहायक निदेशक, प्रायुर्वेद निदेशालय, गिमला हिमाचल प्रदेश-171001
6.	कर्नाटक	डॉ. श्रीनिवास वर्मा, पंजीयक, कर्नाटक प्रायुर्वेद, और यूनानी चिकित्सा व्यवसायी बोर्ड, धनवंतरी रोड, बंगलूर, कर्नाटक-560009
7.	केरल	श्री के. पी. गोपीनाथन नायर, पंजीयक ट्राइनकोर कोषीन, चिकित्सा परिषद्, रेड क्रॉस रोड, तिरुवनन्तपुरम, केरल
8.	उड़ीसा	डॉ. सोमनाथ पांडे, उप निदेशक (आई एम), भारतीय चिकित्सा एवं होमियोपैथी निदेशालय, एम्बेस्सडर बौरक, ब्लॉक—4 स्टेट गैस्ट हाऊस के पोस्ट यूनिट-न्यू दुवनेश्वर, उड़ीसा-751001
9.	पंजाब	श्रीमती कृपान कोर, उप निदेशक (प्रायुर्वेद), ओ. रू. नं. 823-824, सेक्टर-22ए, नंजीगढ़-110022, (पंजाब)
10.	राजस्थान	श्री सतीश कुमार गुप्ता, अपर निदेशक, प्रायुर्वेद निदेशालय, लोहागढ़ रोड, अजमेर, राजस्थान।
11.	तमिलनाडु	डॉ. वी. मुकामणियम, संयुक्त निदेशक, आई एस एम और एच, अरम्माक्कम परिसर। मद्रास-600160 तमिलनाडु।
12.	उत्तर प्रदेश	डॉ. शिवा राज सिद्ध, निदेशक, प्रायुर्वेद और यूनानी चिकित्सा, 32—सरोजनी माधु मार्ग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
13.	जम्मू और कश्मीर	श्री के. वी. गुप्ता, निदेशक, औषध और खाद्य, केन्द्रीय संगठन, जम्मू, (जम्मू और कश्मीर)
14.	महाराष्ट्र	बैद्य एस. बी. जोशी, प्रायुर्वेद निदेशक, महाराष्ट्र सरकार, खन्ना कंस्ट्रक्शन हाऊस, वोरली, मम्बई-400018
15.	पश्चिम बंगाल	(1) प्रायुर्वेद डॉ. विलावाप्पा चक्रवर्ती, पंजीयक, पश्चिम बंग प्रायुर्वेद परिषद्, बी. आर्सेस रेंज (तृसरी मंजिल), कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)। (2) यूनानी श्री एस. भार. मसूदी, विशेष अधिकारी (यूनानी), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, राहटमस बिल्डिंग कलकत्ता
16.	मध्य प्रदेश	डॉ. विजय शंकर शिवेदी, प्रभारी निदेशक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी निदेशालय, सोपास, मध्य प्रदेश।

1	2	3	1	2	3
17.	बिहार	डा० प्रमिलकुम मिश्र, चिकित्सा अधिकारी, राजकीय आयुर्वेद नर्सिंग और अस्पताल पटना बिहार।	6	Karnataka	Dr. Shrinivas Verma, Registrar, Karnataka Ayu. & Unani Practitioners Board, Dhanwantri Road, Bangalore, Karnataka-560 009.
		[सं. बी.-26025/4/91ए.ई.] प्रियम जिल्हा, अक्षर मण्डल भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद मुंबई कक्ष	7.	Kerala	Shri K.P. Gopinathan Nair, Registrar, Travencore Cochin Medical Council, Red Cross Road, Thiruvananthapuram, Kerala.
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (Deptt. of Health)  New Delhi, 29th July, 1993			8.	Orissa	Dr. Somnath Panda, Deputy Director (IM), Directorate of Indian Medicine & Homocopathy, Abestus Barrack, Block-4, Behind State Guest House, Unit-U, Bhubaneswar, Orissa-751 001.
S.O. 2615- In exercise of the powers conferred by Clause (d) rule 2 of the Indian Medicine Central Council (Election) 1975, the Central Government hereby appoint the returning officers state-wise, for conducting elections to the Central Council of Indian Medicine constituted, under clause (a) of sub-section ( ) of Section 3 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (No. 48 of 1970).			9.	Punjab	Smt. Kripal Kaur, Deputy Director (AY), Show Room No. 823-824, Sector-22A, Chandigarh-110 022, Punjab.
Sl. Name of the State No.	Name, address of the	Designation and Returning officer			
1	2	3			
1.	Andhra Pradesh	Dr. A. Laxmikantha Reddy, Inspector, Board of Indian Medicine, 3/3/79, Kuttiguda, Kachiguda, Hyderabad, Andhra Pradesh.	10.	Rajasthan	Shri Satish Kumar Gupta, Additional Director, Ayurveda Directorate, Lohagarh Road, Ajmer, Rajasthan.
2.	Delhi	Dr. R.P. Vashisht, Deputy Director, Directorate of Health Services, Delhi Administration, E-Block, Saraswati Bhawan, Connaught Place, New Delhi.	11.	Tamil Nadu	Dr. V. Subramaniam, Joint Director, ISM & H, Arumbakkam Compound, Madras-600 160, Tamil Nadu.
3.	Gujarat	Vaidhya D.H. Shahane, Panch Karma Department, Govt. Ayurvedic Hospital, Sector-22, Gandhi Nagar, Gujarat.	12.	Uttar Pradesh	Dr. Shiva Raj Singh, Director, Ayu. & Unani Medicine, 32-Sarojini Naidu Marg, Lucknow (Uttar Pradesh)
4.	Haryana	Dr. P.K. Jain, Director, Ayurveda, S.C.O. No. 3, Sector-7, Chandigarh, Haryana.	13.	Jammu & Kashmir	Shri K. V. Gupta, Controller, Drugs and Food Central Organisation, Jammu, (Jammu & Kashmir).
5.	Himachal Pradesh	Dr. D.R. Acharya, Assistant Director, Ayurveda Directorate, Shimla, Himachal Pradesh-171 001.	14.	Maharashtra	Vd. S.B. Boshi, Director of Ayurveda, Maharashtra Govt. Khanna Construction House Worli, Bombay-18.

## 15. West Bengal

## (i) Ayurveda

Dr. Bilwapada Chakrabarty,  
Registrar,  
Paschim Bang Ayurveda  
Parishad,  
8, Lyone range  
(2nd Floor)  
Calcutta  
(West Bengal)

## (ii) Unani

Shri S.R. Massoodi,  
Special Officer (Unani),  
Deptt. of Health & F.W.  
Writers Building,  
Calcutta-1.

## 16. Madhya Pradesh

Dr. Vijay Shanker Trivedi,  
Incharge Director,  
Directorate of Indian  
Systems of Medicine and  
Homeopathy,  
Bhopal,  
Madhya Pradesh.

## 17. Bihar

Dr. Anirudh Mishra,  
Medical Superintendent,  
Govt. Ayurvedic College  
& Hospital,  
Patna,  
Bihar.

[No. V. 26025/4/91-AE]

SHYAM, JINDAL Under Secy.  
CENTRAL COUNCIL OF INDIAN  
MEDICINE, ELECTION CELL.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1993

का.आ. 2016.—केन्द्रीय सरकार का दिल्ली मुख्य योजना-2001 में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/कोई सुझाव देना हो, तो वह अपनी आपत्ति/सुझाव सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, "बी - ब्लॉक, आई. एन. ए." नई दिल्ली को इस सूचना की तिथि से 30 दिनों के अन्दर लिखित रूप में भेज सकता है। आपत्ति करने/सुझाव देने वाला व्यक्ति अपना नाम और पता भी दे।

संशोधन :—

1. पृष्ठ 154 पर (बायां कॉलम), भारत का राजपत्र, भाग - 2, खण्ड - 3, उप खण्ड (ii) दिनांक 1-8-90, उप-शीर्षक पी - 2 (जिला पार्क) में "चिड़ियाघर" शब्द के पीछे निम्नलिखित संशोधन जोड़ा जाना प्रस्तावित है :—

40 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले जिला पार्क में रेस्तरां, जोकि निम्नलिखित शर्तों पर आधारित है :—

(क) रेस्तरां के प्लॉट का क्षेत्रफल 0.8 हेक्टे. (2 एकड़) अथवा जिला पार्क का 1% जो भी कम हो, से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ख) रेस्तरां का प्लॉट गैर जिला पार्क के क्षेत्रफल से वास्तविक रूप से असंग नहीं है।

(ग) भवन अधिकतम 5 एफ. ए. आर. सहित एक मंजिला होगा और बिना किसी आवास सुविधा के इसकी ऊंचाई 4 मी. से अधिक नहीं होगी तथा यह अड़ोस-पड़ोस के अनुकूल होगा।

(घ) जहाँ पर अड़ोस पड़ोस में गाड़ियों के पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है, वहाँ पर रेस्तरां प्लॉट के अन्दर पार्किंग की व्यवस्था की जानी है।

(ङ) स्थल पर जहाँ पानी, सीवर और अन्य सुविधाएं नहीं हैं, अथवा स्थानीय निकाय द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई हैं, वहाँ पर उक्त सुविधाओं की व्यवस्था उद्यमी करेगा।

2. पृष्ठ 155 पर (दाएं कॉलम), भारत का राजपत्र, भाग - II खण्ड - 3, उपखण्ड (ii), दिनांक 1-8-90, उप-शीर्षक "सिनेमा (028)" में "व्यावसायिक कार्यालय" शब्द के पीछे निम्नलिखित शब्दों को हटाने का प्रस्ताव है :—

"(कुल तल क्षेत्रफल के 20 प्रतिशत तक)"

प्रस्तावित संशोधन निरीक्षण हेतु उप निदेशक, मुख्य योजना अनुभाग, छोटी मंजिल, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट नई दिल्ली के कार्यालय में उपर्युक्त अधि के अन्दर सभी कार्य विषयों को उपलब्ध होंगे।

[सं. एफ-10 (19)/91 - एम. पी.]

रणबीर सिंह, सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY  
PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 9th September, 1993

S.O. 2016.—The following modifications which the Central Government proposes to make in the Master Plan for Delhi-2001. Any person having any objection/suggestion with respect to the proposed modifications may send the objection/suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, 'B' Block, I.N.A., New Delhi, within a period of 30 days from the date of this notice. The person making the objection/suggestion should also give his name and address:

Modifications:

1. At page 154 (left hand column), Gazette of India, Part II Section 3, sub-section (ii) dated 1st August, 1990 under sub heading P-2 (District Park), the following modifications are proposed to be added after the words 'Zoological Garden':

"Restaurant in a District Park having area about 40 hectares, subject to that:

(a) area of the restaurant plot is not more than 0.1 hectares (2 acres) or 1 per cent of the District Park, whichever is less.

(b) restaurant plot has no physical segregation from the rest of the District Park Area.

- (c) the building is to be a single storey structure with maximum FAR of 5 and height not more than 4 mtrs. without any residential facility and to harmonise with the surroundings.
- (d) in case there is no parking lot, in the vicinity, parking is to be provided within the restaurant plot.
- (e) the entrepreneur is to make all arrangements of water, sewerage and other utilities wherever not available at site or provided for by the local body.

2. At page 155 (right hand column), Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (ii) dated 1st August, 1990 under sub-heading 'cinema (028)', the following words occurring after the words 'commercial office', are proposed to be deleted:

"(upto 20 per cent of the total floor area)".

The proposed modifications will be available for inspection at the Office of the Dy. Director, Master Plan Section, 6th floor, Vikas Minar, I.P. Estate, New Delhi on all working days within the period referred above.

[No. F. 10(19)/91-MP]

RANBIR SINGH, Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 1993

का. आ. :—2017 केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोगों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के उपनियम 10 (4) के अन्तर्गत सूचना और प्रसारण मंत्रालय के निम्नलिखित कार्यालयों को जिनके 80 % से अधिक कर्मचारी बृहन् नै हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :—

1. क्षेत्रीय वितरण केन्द्र,  
विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय,  
डी. एच. ब्लॉक, एम. एस. ओ. बिल्डिंग,  
साल्ट लेक सिटी, कलकत्ता।
2. क्षेत्रीय प्रदर्शनी एकक,  
35, हैडोस रोड,  
भुतल, ब्लॉक नं. 1,  
नुगुम्बकम, मद्रास - 6
3. क्षेत्रीय प्रदर्शनी वर्कशॉप,  
35, हैडोस रोड,  
भुतल, ब्लॉक नं. 1,  
नुगुम्बकम, मद्रास - 6
4. क्षेत्रीय कार्यालय,  
विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय,  
67, इन्फेंटरी रोड,  
बंगलोर - 560001

[संख्या ई-11011/1/93-हिन्दी]

प्रेस कृष्ण गोरारारा, निदेशक (रा. भा.)

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 6th September, 1993

S.O. 2017.—In pursuance of Sub-rule (4) of rule 10 of the Official Languages (use for official purposes of the union) Rules, 1976 the Central Government hereby notify the following offices of the Ministry of Information and Broadcasting

where more than 80 per cent of the staff have acquired the working knowledge of Hindi :—

1. Regional Distribution Centre,  
D.A.V.P.,  
D.F. Block, M.S.O. Building,  
Salt Lake City, Calcutta.
2. Regional Exhibition Unit,  
35, Hades Road,  
Basement, Block No. 1,  
Nugumbakam, Madras-6.
3. Regional Exhibition Workshop,  
35, Hades Road, Basement,  
Block No. 1,  
Nugumbakam, Madras-6.
4. Regional Office,  
D.A.V.P.,  
67, Infentary Road,  
Bangalore-560001.

[No. E-11011/1/93-Hindi]

P. K. GORAWARA, Director (O.L.)

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1993

का. आ. 2018:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बम्बई डक लेबर बोर्ड के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण बम्बई संख्या 2 के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-8-93 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-31011/1/88-डी-IV (ए)/डी III (बी)]

कै० वी० बी० उष्णी, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 1st September, 1993

S.O. 2018.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal Bombay No. 2, as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bombay Dock Labour Board and their workmen, which was received by the Central Government on 30-8-1993.

[No. L-31011/1/88-D.IV (A)/D.III (B)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

PRESENT :

Shri P. D. Apshankar, Presiding Officer.

Reference No. CGIT-2/25 of 1988

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Bombay Dock Labour Board, Bombay

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Employer—Shri P. Ramaswamy, Advocate.

For the Workmen—Shri M. B. Anchan, Advocate.  
**INDUSTRY :** Port and Docks **STATE :** Maharashtra  
 Bombay, the 30th July, 1993

#### AWARD

The Central Government by their Order No. L-31011/1/88-D.IV(A)/D.III (B) dated 18-8-1988 have referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

"Whether the action of the management of Bombay Dock Labour Board, Bombay, in demoting three Tindal workmen, viz., Shri S. Nagarajan, Shri S. Vetriyappan, and Shri N. Shekar, as General Purpose Mazdoors w.e.f. 18th June, 1983, is justified? If not, what relief the workmen concerned are entitled to?"

2. The case of the above said three workmen, as disclosed from the Statement of Claim (Ex. W/2) filed on their behalf by General Secretary of the National Dock Workers' Union, Bombay, in short, is thus :

Before the implementation of the Bombay Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme 1956, the above said workmen were working with M/s. United Liner Agencies of India Pvt. Ltd. as Tindels since July 1981. At the time of the implementation of the above said Scheme of 1956 i.e. on 1-5-1983, the United Liner Agencies of India Pvt. Ltd. filed in forms as per the requirements of the said Scheme, and submitted them through the Bombay Stevedores Association to the Bombay Dock Labour Board, wherein the said workmen were shown as Tindels. The said three workmen worked with the United Liner Agencies as Tindels till 31-5-1983. Thereafter they were absorbed as Tindels in the Bombay Dock Labour Board as required under the said Scheme on the basis of the said list. After their absorption the said three workmen became the employees of the Bombay Dock Labour Board and they were working as Tindels upto 3-7-1983. From 4-7-1983 the Bombay Dock Labour Board refused to book them as Tindels, and demoted them, by posting them as General Purpose Mazdoors. Since then the three workmen were working as General Purpose Mazdoors under protest. When they were demoted as General Purpose Mazdoors, no reason was given by the management for their demotion, nor they were issued with any charge sheet for any alleged misconduct. As such, their demotion is unjust and illegal.

After their demotion, the said three workmen made necessary representations to the different authorities for restoring them to their original posts of Tindels. However, their request was not granted by the management. Hence the workmen raised the necessary industrial dispute before the Regional Labour Commissioner (Central). However, the conciliation proceedings ended in failure.

3. The Union further alleged thus :

The United Liner Agencies of India Pvt. Ltd. is a member of Bombay Stevedores Association. The said three workmen were appointed as Tindels by United Liner Agencies of India Pvt. Ltd. When the General Purpose Mazdoors Pool was formed, the United Liner Agencies of India Pvt. Ltd. submitted a list of workers to the Bombay Stevedores Association, and the Bombay Stevedores Association forwarded the said list to the Bombay Dock Labour Board showing these three workers as Tindels, and hence they were absorbed as Tindels by the Board. After the reversion of these three workmen from the posts of Tindels to the posts of General Purpose Mazdoors, about 40 General Purpose Mazdoors were promoted as Tindels by the said Board. Some of the Tindels who were promoted, were juniors to the workmen in question and they were working under three workmen in question as General Purpose Mazdoors. The reversion of the said three workmen to the posts of General Purpose Mazdoors, is

unjust and illegal. The Union, therefore, lastly prayed that this Tribunal should hold the action of the Bombay Dock Labour Board in reverting the said three workmen as General Purpose Mazdoors, is unjust and illegal, and should direct the Board to restore them to their original posts of Tindels with the necessary consequential benefits, including the continuity of service and the back wages.

4. The Bombay Dock Labour Board by their Written Statement (Ex. M/3) opposed and contested the said claim of the workmen, and in substance contended thus :

Prior to the registration of the General Purpose Mazdoors with the Bombay Dock Labour Board, the three workmen in question were working with different stevedoring firms, including M/s. United Liner Agencies of India Pvt. Ltd. as temporary/casual General Purpose Mazdoors. The list of such employees was submitted by the United Liner Agencies for registration with the Bombay Dock Labour Board, and on verification of that list the said workmen were registered with the Board. This registration was temporary and was not permanent as the temporary casual employees of various stevedoring firms were being registered in a group. After the registration, the Board had rearranged various categories in accordance with their seniorities and requirement of the Board. It had also to consider the complaints received from some of the employees in respect of other categories.

The list of employees was submitted by the United Liner Agencies through stevedores to the Bombay Dock Labour Board. It was found on complaints received from senior employees that the three workmen in question were in fact juniors and had managed to get their names mentioned in the list that they were working as Tindels with M/s. United Liner Agencies of India Pvt. Ltd. The then Chief Administrative Officer of the Board went through those complaints and directed the Assistant Administrative Officer to transfer the said three workmen from the posts of Tindels to the category of General Purpose Mazdoors.

5. The management further contended thus :

In the beginning at the time of registration the said three workmen were absorbed as Tindels. Further prior to the registration of these temporary General Purpose Mazdoors, the Bombay Dock Labour Board had already registered 150 General Purpose Mazdoors in its pool. At the time of registration, the seniority list of the temporary workmen who had worked with the different employers was prepared on the basis of number of years of services rendered by them with their respective employers.

After the said seniority list was prepared, it was found that the three workmen in question were junior in the common list, and there were no vacancies in the category of Tindels. Hence, they were asked to work as General Purpose Mazdoors. In the common seniority list prepared by the Board, the number of the said three workmen is below nine other workmen. Hence, three workmen in question will have to wait till the vacancies occur in the posts of Tindels. It is not true to say that the said three workmen were demoted from the posts of Tindels to the category of General Purpose Mazdoors. Initially, the said three workmen had worked as Tindels for a few days until the common seniority list was prepared. Thereafter as they were found junior in the list, they had to work as General Purpose Mazdoors. Merely by working with different employers as Tindels, the workmen do not get any inherent right to claim that they should be posted as Tindels with the Dock Labour Board. The three workmen in question were not demoted by the Board. They were given their correct place as per their seniority as soon as the common seniority list was prepared. The union has not made out any case for interference in the matter by this Tribunal. The management, therefore, lastly prayed for the rejection of the prayer of the union.



6. The Issues framed at Ex. 4 are :

- (1) Whether the three workmen in question prove that they were working as Tindels with M/s. United Liner Agencies of India Pvt. Ltd. from July 1981 to 31-5-1983 ?
- (2) Whether they prove that they were absorbed as Tindels in the Bombay Dock Labour Board ?
- (3) Whether the Bombay Dock Labour Board proves that the said three workmen were in fact juniors in the list, and that they managed to get their names mentioned in the list that they were working as Tindels with M/s. United Liner Agencies of India Pvt. Ltd. ?
- (4) Whether the said three workmen were in fact demoted from Tindels to General Purpose Mazdoors category, by the Dock Labour Board ?
- (5) Whether the Dock Labour Board proves that the three workmen in question were not demoted, but were placed at their correct place in the common seniority list ?
- (6) Whether the action of the management of Bombay Dock Labour Board, Bombay, in demoting three Tindel workmen, viz. Shri S. Nagarajan, Shri S. Veeriyappan, and Shri N. Shekar, as General Purpose Mazdoors w.e.f. 18th June, 1983, is justified ?
- (7) If not, what relief the workmen concerned are entitled to ?
- (8) What Award ?

7. My findings on the said Issues are :

- (1) Yes.
- (2) Yes
- (3) No.
- (4) Yes.
- (5) No.
- (6) No.
- (7) As per Award below.
- (8) As per below.

#### REASONS

#### ISSUES NOS. 1 AND 2 :

8. Shri S. Nagarajan, one of the three workmen in question, filed his affidavit (Ex. W/32) in support of the case of the workmen. The Union filed the affidavit of Shri Balsara, the Dock Officer with M/s. United Liner Agency Pvt. Ltd., Bombay (Ex. W/35), in support of the case of the workmen. Both these witnesses were cross-examined on behalf of the management, i.e. Bombay Dock Labour Board. The Bombay Dock Labour Board filed the affidavit (Ex. M/37) of the Secretary, Shri Vasant Namdeo Ahire in support of their case. He was also cross-examined on behalf of the union.

9. According to the three workmen in question, they were working as Tindels with M/s. United Liner Agencies of India Pvt. Ltd. from July 1981 to 31-5-1983 and that they were thereafter absorbed as Tindels in the services of the Bombay Dock Labour Board. There is ample documentary evidence on record in that respect. Ex. W/8 is the letter dated 18-6-1983 by the United Liner Agencies to the Bombay Dock Labour Board stating that Shri S. Veeriyappan was working as a Tindel with them. Exs. W/9 and W/10 are similar letters in respect of other two workmen, viz. Shri N. Shekar and Shri S. Nagarajan stating that they were working as Tindels with the United Liner Agencies. Ex. W/12 is a copy of photo pass of Shri S. Nagarajan. It is seen therefrom that in May 1983 he was working as Casual Workman (Tindel) with United Liner Agencies. Ex. W/13 is the attendance card of the workman Shri N. Shekar for the month of June 1983. He has been described there in as G. P. Maz. (T) i.e. General Purpose Mazdoor, (Tindel). As such, he was absorbed as a Tindel in the service of Bombay Dock Labour Board Exs. 2004 G1/93-8

W/11 and W/15 are the attendance cards of the workmen Shri S. Veeriyappan and Shri S. Nagarajan, who have also been described there in as General Purpose Mazdoors (Tindels). As such, they were also absorbed in the service of Bombay Dock Labour Board as Tindels in June 1983.

10. Ex. W/17 is a letter dated 8-7-1983 addressed to the Chief Administrative Officer of the Bombay Dock Labour Board. It is seen there from that a number of workmen had written that letter to the Bombay Dock Labour Board stating that the three workmen in question, viz. Shri S. Veeriyappan, Shri S. Nagarajan and Shri N. Shekar were previously working with United Liner Agencies as General Purpose Mazdoors, Tindels, and that they have now been removed from the list of Tindels. By the said letter, the large number of workers requested the Bombay Dock Labour Board to reinstate those three workmen in question to the posts of Tindels. As such, the three workmen in question were working as Tindels with United Liner Agencies before they were taken in service of the Bombay Dock Labour Board. By the letter dated 15-10-1988 the United Liner Agencies had written to the Bombay Dock Labour Board that the above said three workmen were registered in the category of General Purpose Mazdoors. As such the three workmen in question were reverted from the posts of Tindels to the post of General Purpose Mazdoors. Exs. M/27, M/28 and M/29 are the proformas of the United Liner Agencies. It will be seen there from that the three workmen in question were listed in the category of Casual Workers (Tindels) with them. It is, therefore, quite clear from the above said documentary evidence on record that the above said three workmen in question were working as Tindels with United Liner Agencies during the period of 1981 and 1982 till they were engaged in the services of Bombay Dock Labour Board on 31-5-1983. It is further seen from the said documentary evidence that they were initially absorbed as Tindels by the Bombay Dock Labour Board in 1983. The management also admitted in their written statement that the three workmen in question were initially absorbed as Tindels. The management's above said witness also admitted in his cross-examination that the three workmen in question were initially registered as Tindels with the Bombay Dock Labour Board on the basis of information supplied by the United Liner Agencies. Therefore, Issues Nos. 1 and 2 are found in the affirmative.

#### ISSUE NO. 3 :

11. According to the management, the three workmen in question were in fact juniors in the list, and that they had managed to get their names mentioned in the list that they were working as Tindels with the United Liner Agencies. However, on this point, there is no convincing and satisfactory documentary evidence on record to show that the three workmen in question were juniors. There is absolutely no documentary evidence on record to hold that the three workmen in question had managed to get their names mentioned in the list that they were working as Tindels with United Liner Agencies. On the contrary, in the list of casual workers working with Contractor, S. Madasamy, i.e. before the workmen in question were taken in the services of Bombay Dock Labour Board, the workmen in question Shri S. Veeriyappan was at Sr. No. 2 and the other workmen Shri S. Nagarajan was at Sr. No. 13, and as such they were senior to Shri I. Vincent, who was at the Sr. No. 32 in that list. Admittedly Shri I. Vincent is working as a Tindel in the services of Bombay Dock Labour Board, even though he was junior to the two workmen in question, viz. S. Veeriyappan and S. Nagarajan. Therefore, the contention of the management that the three workmen in question were in fact junior in the list, and that they had managed to get their names mentioned in the list that they were working as Tindels with United Liner Agencies, cannot at all be accepted.

Issue No. 3 is therefore, found in the negative.

#### ISSUE NOS. 4 AND 5 :

12. According to the union, the three workmen in question were demoted from the post of Tindels to that of General Purpose Mazdoor, by the Bombay Dock Labour Board. According to the Bombay Dock Labour Board, those three workmen were not demoted, but that they were placed at their correct places in the common seniority list. However, the management's witness, Shri Ahire admitted in his cross-examination that the three workmen in question worked as Tindels with the Bombay Dock Labour Board for about a

New Delhi, the 1st September, 1993

month, and thereafter, they were reverted to the post of General Purpose Mazdoors without issuing any show cause notice to them, and without issuing any chargesheet to them. As such it is quite clear from the evidence on record that the three workmen in question were demoted from the post of Tindels to the post of General Purpose Mazdoors. It is seen from the evidence on record that about 6 to 7 workers work under a Tindel, and as such the post of a Tindel is of higher rank than that of General Purpose Mazdoor. For the above said reasons, Issue No. 4 is found in the affirmative, while Issue No. 5 is found in the negative.

## ISSUES NOS. 6 AND 7 :

13. Admittedly, before reverting the said three workmen from the post of Tindels, to the post of the General Purpose Mazdoors, no show cause notice was issued to them by the management, nor any reason for the reversion was communicated to them for their demotion by the management. According to the management, there were some complaints from the other workmen against the three workmen in question. However, the witness for the management admitted in his cross-examination that those complaints were not in writing, but were only oral complaints. As noted above, Shri I. Vincent was junior to the two workmen in question, viz. Shri S. Vetriyappan and Shri S. Nagarajan (Ex M/6). However, Shri I. Vincent was appointed as a Tindel, and he continued to be in services of the Bombay Dock Labour Board as a Tindel. Therefore, the action of the management in reverting the three workmen in question from the post of Tindel to the post of Casual Purpose Mazdoor was not at all just, proper and legal and as such, they are entitled to the reinstatement in service to the post of Tindel from the dates they were reverted to the post of Casual Purpose Mazdoor with all consequential benefits of their service.

Issue No. 6, is therefore, found in the negative, and Issue No. 7 is found accordingly.

## ISSUE NO. 8 :

14. In the result, the following award is passed :

## AWARD

The action of the management of Bombay Dock Labour Board, Bombay, in demoting three Tindel workmen, viz. Shri S. Nagarajan, Shri S. Vetriyappan and Shri N. Shekar, as General Purpose Mazdoor with effect from 18th June 1983, is not just, legal and proper.

The abovesaid management is hereby directed to restore the above said three workmen to the posts of Tindels from the dates they were reverted to the posts of General Purpose Mazdoor with all consequential service benefits arising there from, including those of arrears of wages, the increments and further promotions, etc.

The parties to bear their own costs of this reference.  
30th July, 1993.

P. D. APSHANKAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1993

का. अ. 2019—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबन्ध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण ओडीसा—भुवनेश्वर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 27-8-93 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-38012/3/84 - डी-4 (ए)]

के. वि. बी. उन्नी, डेस्क अधिकारी

S.O. 2019.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Orissa, Bhubaneswar as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Paradip Port Trust and their workmen which was received by the Central Govt. on 22-8-93.

[No. L-38012/3/84-D.IV(A)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer  
ANNEXURE

INDUSTRIAL TRIBUNAL, ORISSA, BHUBANESWAR  
PRESENT :

Sri R. K. Dash, LL.B.,  
Presiding Officer,  
Industrial Tribunal,  
Orissa, Bhubaneswar.

Industrial Dispute case No. 8 of 1985 (Central)

Dated, Bhubaneswar, the 18th August, 1993

## BETWEEN :

The Management of Paradip Port Trust, Paradip.  
.. First party-management.

## AND

Their workman Sri Chandramani Kar, represented  
through Paradip Port Workers' Union, Paradip.

## AND

Sri N. Mohanty, K. Patil & R. K. Mohapatra represented  
through Paradip Port Shramik Sangha, Paradip.

.. Second party-workmen.

## APPEARANCES :

Sri S. K. Mohanty, Dy. Secretary (Law)—for the first  
Party-management.

1. Sri S. K. Bhattacharyya, General Secretary of the  
Workers' Union—For the Paradip Port Workers'  
Union.

2. None. .. For the Paradip Port Shramik Sangha.

## AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of powers conferred upon it by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) (for short 'Act') have referred the following dispute for adjudication by this Tribunal vide their Order No. L-38012/3/84-D.IV(A) dated 13th November, 1985 :—

"Whether the action of the management of Paradip Port Trust in altering the position of seniority of Shri Chandramani Kar as Welder Grade-II and Welder Grade-I with effect from 24-3-82 and 24-11-82 respectively is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled to?"

2. Briefly stated the case of the Paradip Port Workers' Union is that Sri Chandramani Kar the present workman was initially appointed in the Port on 14-2-64 as a Welder and about two years thereafter, that is on 1-6-66 he was promoted to the next higher post i.e. Welder Grade-II. Since his date of appointment till 31-3-70 he served in the work-charged establishment of the Paradip Port Trust. There was a settlement between the management and the Union on 25-6-68 regarding conversion of all the work-charged posts into regular posts and for determination of the seniority of the employees/workmen working in those posts. It was stipulated in the said settlement that all the existing posts which were of regular and not casual or seasonal in nature and had been in existence for more than three years would

be converted into regular posts latest by 30-6-88 and the workman who had been working in the work-charged posts would be brought to their respective regular posts on the basis of their seniority by 31-7-88. In accordance with the terms of the said settlement the post of Welder Grade-II which the workman was holding though was to be converted to regular post, but it was not done. Instead, the management directly appointed three outsiders towards the end of 1969 as regular Grade-II Welders. Only on 1-4-70 the post which the workman was holding was converted to regular post and his services were regularised. However, in view of the terms of the settlement as aforesaid his seniority was well protected and in the seniority list published by the management on 8-6-77 the three persons who came to be appointed directly in 1969 were kept below to him. Considering his seniority, the management promoted him to Welder Grade-I vide office order dated 2-2-73 in the regular establishment and then as a chargeman vide order dated 12-2-82. In the seniority list of Welders Grade-I the workman was shown at Serial No. 1. But all of a sudden and behind his back the management violating the terms of settlement revised the seniority list and put him below the three direct recruits. It is, therefore, urged that he being admittedly senior to the direct recruits the change of his seniority effected by the management as mentioned in the schedule of reference should be answered in his favour.

3. The case of the management of Paradip Port Trust on the other hand is that the workman came to be appointed on 17-2-64 as a Welder Grade-II when the Port was under the administrative control of the State Government. He was again given temporary appointment as Welder Grade-II with effect from 1-6-66. In later part of 1967 Paradip Port Trust was created under the Major Port Trust Act, 1963. Admitting what has been pleaded by the workman that there was a settlement between the parties for converting the work-charged posts to that of regular posts, it is urged inter-alia that according to the terms of settlement only those posts which were in existence for three years or more on the date of settlement were agreed to be converted to regular posts. In pursuance of the said settlement 318 work-charged posts were made regular but not the posts of Welder Grade-III and Grade-II as those did not satisfy the terms of settlement as aforesaid. In other words, those posts were not in existence for a minimum period of three years for converting the same to regular posts. Subsequently, on 30-7-69 three regular posts in Welder Grade-I and one post in Welder Grade-II were created. To fill-up those posts the management decided to recruit I.T.I. qualified candidates in conformity with the Recruitment Rules of the Port Trust. Consequently, the management filled-up those posts by selecting Sri N. Mohanty, K. Pati and R. K. Mohapatra (These three persons have been added as parties as their interest is involved in the proceeding). In early part of 1970 a post of Welder Grade-II was converted to regular post as a consequence of which the workman was brought under the regular cadre with effect from 1-4-70. In 1971 a seniority list of the workers was published wherein the workman was placed in fourth position as because the direct recruits and the work-charged employees belonged to distinct and separate source. There having no objection from any quarter, the said list was approved by the Chairman on 21-12-73. The concerned file of the Welders was transferred to Electrical & Mechanical Department and for reasons not known to the management the seniority list as aforesaid was revised and a fresh seniority list of Grade-II Welders was prepared and circulated by the Chief Electrical & Mechanical Engineer wherein the workman was placed in Sl. No. 1 and his counterparts, namely, Sri N. Mohanty, K. Pati and R. K. Mohapatra were placed in Sl. No. 7, 8 and 9 respectively.

Anticipating that vacancies might occur in the posts of Welder Grade-I which were to be filled up on the basis of seniority-cum-merit, the names of the workman and three others were empanelled by the Departmental Promotion Committee and in the list prepared by the said Committee the workman was kept in Sl. No. 1. Later on, when the post of Grade-I Welder fell vacant the workman being in Sl. No. 1 of the list was given appointment temporarily on 3-2-73. Long after his appointment others whose names appeared below him were appointed as Grade-I Welders.

The next higher post is the Chargeman (Welding) and the same being a promotional post is to be filled-up from amongst the Grade-I Welders on the basis of merit-cum-seniority and on consideration of their C.C. Rs. as well as the result of trade test. A post of Chargeman in due course fell vacant and the workman on his being selected by the D.P.C. on 15-2-82 was promoted to hold the said post. Till then there was no dispute or difference between him and Sri N. Mohanty and two others, the newly added parties to the proceeding. A dispute however arose in respect of inter-se-seniority of the motor vehicle drivers for which a clarification was sought for from the Ministry of Shipping & Transport, Government of India. It was then clarified that inter-se-seniority of the drivers in work-charged establishment vis-a-vis the regular establishment would be counted on the basis of their appointment in the regular establishment and the service period of the drivers in work-charged establishment would not be taken into account for considering their seniority. Keeping in view this guideline, the seniority list of the Welders Grade-II was revised wherein Sri N. Mohanty, K. Pati and R. Mohapatra were assigned in Sl. No. 1, 2 & 3 respectively and the workman was kept below them. Basing on the said list a tentative seniority list of Grade-I Welders was again prepared and circulated. The management, therefore, has urged that in view of the clear indication of the Ministry of Shipping & Transport, Government of India for fixing inter-se-seniority between the direct recruits and the work-charged employees as mentioned above, the workman who was although being treated to be senior to his counterparts was made junior and accordingly he was placed below them in the seniority list.

4. The three workmen named above whose interest is directly involved on being added as parties appeared through Paradip Port Shramik Sangha and filed written statement. Their case in short is that they were appointed as regular and permanent Grade-II Welders in December 1969 and by the time of their appointment there was no other confirmed or regular Welder Grade-II working in the establishment. In the year 1971 a seniority list was prepared wherein they were placed above the aggrieved workman Sri Kar. So, they being seniors to Sri Kar the management appeared to have committed no mistake in placing him below them in the seniority list.

5. In view of the pleadings of the parties, the sole question for consideration is whether the workman Sri Kar should be treated senior to his counterparts, namely, Sri N. Mohanty, K. Pati and Sri R. K. Mohapatra. If this is answered in the affirmative, subsequent change of the seniority list by the management has to be held to be illegal.

6. All the parties declined to adduce oral evidence. They only relied upon certain documents which have been marked exhibits on admission.

7. The aggrieved workman is admittedly much senior to Sri N. Mohanty, K. Pati and R. K. Mohapatra in service. The appointment order, Ext. 1 would indicate that he entered in the service of Paradip Port Trust as a Welder Grade-III in 1964. Subsequently, in 1966 when the post of Grade-II Welder was either created or fell vacant he was given fresh appointment under office order, Ext. 2. According to the management, the post of Grade-II Welder held by the workman was a work-charged post which was made regular in 1970; whereas Sri N. Mohanty and two others on their being selected were appointed as Grade-II Welders against permanent posts. So, in the opinion of the management the workman is junior to his counterparts and accordingly, he has been kept below them in the seniority list.

8. The Central Government in exercise of its powers conferred upon it by the provisions of Major Port Trust Act, 1963 framed Regulations known as "Paradip Port Employees (Recruitment, Seniority & Promotion) Regulations, 1967". Clause-7 of the said Regulations clearly envisages that the Port shall layout the manner for filling-up vacancies of various grades of posts by direct recruitment and departmental promotion. This being the Rule the management in the present case ought to have laid down the criteria as to how many of the three regular posts in Grade-I Welders created in 1969 would be filled-up by direct recruitment and

by promotion from the departmental candidates. Without doing so, the management filled up those posts by direct recruitment by giving appointment to Sri N. Mohanty and two others over-looking the claim of the workman. By the time of such appointment when the workman was already in the job as a Grade-II Welder in the work-charged establishment and there having no allegation against him about his efficiency and sincerity, the management of Port Trust which is expected to be a model employer ought to have regularised his service against a regular post of Grade-II Welder and filled-up the remaining two posts by recruitment from open market. It needs no mention that an employee with unblemished service career if made junior by whimsical and arbitrary administrative orders of the officials of the management certainly the standard of work would deteriorate which may adversely affect the interest of the management. That exactly what has happened in the present case. The workman who was initially treated as senior to his counterparts and was promoted to Grade-I Welder and finally as a Chageman was again made junior and kept below in the seniority list. It is the management's own admitted case that not only the workman was senior to others but his performance all throughout was quite satisfactory and that he had no adverse entry to his credit in the service record. A reference in this context may be made to paragraph-10 of the management's written statement where it is clearly stated that after considering the merit-cum-seniority, C.C.R. and the result of trade test the workman was selected to be promoted to the post of Chageman (Welding) and accordingly he was given promotion (see appointment order, Ext. 8). So, the workman's sincerity, efficiency and devotion to duty weighed with the management for giving him promotion at two stages; one from Grade-II Welder to Grade-I Welder and from Grade-I Welder to Chageman (Welding). Now at this stage if he is made junior to his counterparts because of the fact that he was brought to regular post of Grade-II Welder in 1970 though he was holding the said post since 1964, it would seriously affect his interest in all respect. It should be remembered that if sincerity, efficiency coupled with seniority has no consideration in service life then in that case the administration will collapse particularly when our national character has deteriorated.

9. In view of my discussions made above, I hold that the alteration of the seniority position of the workman as mentioned in the schedule of reference is not legal and justified. In view of my such finding the workman being senior to his counterparts, namely, Sri N. Mohanty, K. Pati & R. K. Mohapatra his seniority in all stages should be maintained and his name should be placed above them in the seniority list.

10. The reference is thus answered accordingly.

Dictated & corrected by me.

R. K. DASH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1993

का. आ. 2020—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार विशाखापटनम पोर्ट ट्रस्ट के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निश्चित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण हैदराबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-8-93 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-34011/4/88-डी IV (ए)/डी-III(बी)]

के. वि. बी. उन्नी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 1st September, 1993

S.O. 2020.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of

Visakhapatnam Port Trust and their workmen, which was received by the Central Government on 30-8-1993.

[No. I-34011/4/88-D.IV (A)/D.III (B)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT HYDERABAD

PRESENT :

Sri Y. Venkatachalam, M.A., B.L., Industrial Tribunal.  
Industrial Dispute No. 26 of 1989

BETWEEN

The Workmen of Visakhapatnam Port and Dock Employees Association, represented by the General Secretary Sri R. Rahamau, Port and Dock Employees Association, Rama Padma Nilayam, Door No. 14-25-32-A (Upstairs) Dandu Bazar, Maharanipeta, Visakhapatnam-530002.

AND

The Management of Visakhapatnam Port Trust,  
Visakhapatnam-530035. —Respondent

APPEARANCES :

M/s. G. Bikshupathi, G. Vidya Sagar, V. Vishawanathan  
N. Vinesh Raj and K. V. V. Bhaskar, Advocate—  
For the Petitioner.

M/s. K. Srinivasa Murthy, G. Sudha and Mitra Das,  
Advocates—For the Management.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by its Order No. I-34011/04/88-D.IV(A)/D.III(B) dated 20-3-1989 referred the following dispute under Section 10(1)(d) and (2-A) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the employers in relation to the Management of Visakhapatnam Port Trust and their workmen to this Tribunal for adjudication :

"Whether the demand of Port and Dock Employees Association for withdrawal of punishment imposed on S/Sri K. Satya Raju, Operator Gr. II of OHC, CH. Appa Rao, Khalasi, OHC and K. Maria Das, AF (Operation) OHC by the management of Visakhapatnam Port Trust consequent upon the incidence occurred during 3rd Shift of 10-8-85 is justified? If so, what relief are the workmen concerned entitled to?"

This reference was registered as Industrial Dispute No. 26 of 1989 and notices were sent to the parties

2. The claim statement filed on behalf of the Workmen in brief as follows :

It is submitted that the Petitioner Union is a Trade Union having been registered under the provisions of the Trade Union Act. The workmen concerned in the dispute are the members of the Petitioner Union and their cases have been espoused by the Petitioner Union. It is submitted that Sri K. Satya Raju was working as Operator Grade II at Ore Handling Plant. He was in the 3rd Shift on 10-8-1985 commencing from 10.00 P.M. to 6 A.M. on 11-8-1985. The workman was posted at Stacker. As per the existing rule, the workman posted at Stacker-I has to signal for Stack filing. The movement of the dumping operations has to be signalled to the Operator Grade-I at Chute who will divert the dumping operations so as to void filing at Stacker-I. Except this, he has nothing to do with the operations of the conveyor belt system. That one Appa Rao, Operator Grade I at Chute controlling operations. For any faulty operations, he is responsible as the entire operational system is under his control. The workman was issued with a charge sheet dated 22-8-1985 and the workman submitted the explanation denying the charge framed against him. The

Management conducted a common domestic enquiry for the same and similar charge in respect of the three workmen including K. Satya Raju. The three workmen concerned in the joint enquiry are Sri T. Appa Rao, Operator Grade I, Sri K. Satya Raju, Operator Grade II/OHC and Sri V. S. Padmanabha Raju Operator Gr. II/OHC. The Management examined four witnesses including Sri Sumitra Rao Executive Engineer and Sri G. S. L. Murthy Asst. Engineer. The workmen were also examined in defence of their respective cases. Thereafter a show cause notice dated 6-2-1987 was issued to the workman stating that the charges were partly proved and that the punishment or reduction of pay any four stages was proposed to be imposed. Along with the show cause notice the enquiry report was also furnished to the workman. The workman submitted detailed explanation on 20-5-1987. The Chief Mechanical Engineer passed an order dated 31-3-1987 reducing the pay of the workman to Rs. 881.00 from Rs. 965.00 for a period of two years without cumulative effect. The workman filed an appeal to the Chairman and it was partly allowed to the effect that reduction of pay was modified to two stages for two years without cumulative effect. The punishment as imposed is illegal and contrary to the provisions of the Visakhapatnam Port Trust Employees (CCA) Regulations 1968. The workman was not given the documents as set out in the Annexure III to the charge sheet. Further, the enquiry officer is the Junior Officer and the witnesses examined in the enquiry are the superiors to the Enquiry Officer. The fact that one of the witnesses is an Executive Officer and the Enquiry Officer being the Asst. Executive Engineer establishes same. The enquiry is vitiated for non-observance of principle of natural justice. Even otherwise it is clearly brought out in the enquiry that the Petitioner is not at all connected with the presence of M.S. Plates which is alleged to have caused jam at H-2 and H-1 extensions and also snapping of R-3 Conveyor Belt. As already submitted, the workman was at Stacker-I and he has no control over the Conveyor system. He has to give only signal to the Operator Grade-I at Chute. Beyond this, he has nothing to do with the other operations. Therefore the workman cannot be blamed for the non-functioning of the conveyor system. It is further submitted that the Chute Plug was provided at the chute where the Operator Grade-I functions. Apart from that the Tension meters are provided to the R-3 Conveyor Belt at H-1 and H-2. Any discrepancy in the system of the chute plug come into operations and automatically stops the entire system. It is also not uncommon that foreign elements do come in the ore and sometimes the operation are also jammed. It would not be possible for the persons charging the Operators about the presence of any plates or other items especially in the nights, as the foreign items are not visible. It is not established in the enquiry as to how the workman is responsible for the jamming of the ore, and snapping of conveyor belt. The charge itself is very vague which says that had Sri K. Satya Raju be vigilant and more cautious in stopping the belt in time, the failure of R-3 conveyor belt could have been averted. The Enquiry Officer did not consider the contentions raised by the workman in his defence brief and proceeded with pre-conceived notion. It is prayed that the Hon'ble Court may be pleased to set aside the order of punishment passed in No. E/M/PC/3371 dated 31-3-1987 and as modified by the Chairman by proceeding dated 9-12-1987 as illegal, arbitrary and unjustified and pass an Award accordingly.

3. It is submitted that the workman Sri K. Maria Das was issued with a charge sheet by the Chief Mechanical Engineer, dated 21-8-1985. It is submitted that Sri K. Maria Das, the workman herein was functioning as Asst. Foreman (Operations) in OHC. On 10-8-1985 in third Shift, commencing at 10 P.M. and concluded at 6 A.M. on 11-8-1985. As Asst. Foreman, the duties assigned to him are to watch the overall performance of the plant and he has to supervise the operations at Dumper, (2) R-I Sonveyor Belt, (3) H-I Mechanical House and (4) R-II Conveyor and (5) H-3 Mechanical House.

The petitioner being not responsible for the incident submitted an explanation denying the charge. Therefore, the enquiry was ordered by proceedings dated 30-10-1985 and one Sri K. Bheema Rao, Asst. Executive Engineer was appointed as Enquiry Officer to conduct the enquiry. In the enquiry, it is clearly brought out by the witnesses for the Management itself that the workman at the relevant time was attending his duties at H-3 Mechanical House. Therefore, it would not be possible for him to immediately proceed to the other operations for stopping the irregular movement of machinery. It was further brought out in the evidence that the workman was at H-III Drive House and monitoring the operations. As there was no operator during the day shift, there was no opportunity for the workman to look at Stacker I. It is not known whether there was foreign element like steep plate in the conveyor system or due to some mechanical defect, the conveyor belt was snapped. The so-called iron plate was not removed in the presence of the workman and other connected operators. Therefore the presence of the plate itself is indoubt. Hence the workman under the circumstances cannot be made responsible for the incidence which took place at Stacker I. The tension meters which were fitted to the operations should have functioned when there is faulty operations in the conveyor system. The workman could not have averted this incident as he was at a far away place attending to H-III Mechanical House and it is beyond his control to have come out immediately to the Stacker-I and attend to the functions. The Enquiry Officer is bound to be prejudiced against the workman, when the superior officer to Enquiry Officer gives statement before him. The workman was issued with a show cause notice dated 6-4-1987 by the Chief Mechanical Engineer, proposing to impose the penalty of reduction of pay to the minimum scale of Rs. 880.00 from Rs. 1502.00 in the time scale of pay of Rs. 880—1542. The Chief Mechanical Engineer passed an order dated 12-5-1987 imposing the punishment of reduction of pay by four stages from Rs. 1502.00 to 1342 in the scale of Rs. 880—1542.00 for a period of one year without cumulative effective w.e.f. the date of issue of these proceedings. On an appeal, the Chairman reduced the rigor of the punishment and modified the punishment to that of reduction of pay by three stages for six months without cumulative effect. Infact the charge is vague and it cannot be called out as there is no specific omission and negligence committed by the workman. The findings of the E.O. are equally perverse and based on no evidence on record. On the other hand, it is established in the enquiry that the workman was not at the Stacker-I at the relevant time and he was at H-III Mechanical House, attending to some operations. Therefore, the punishment as imposed on the workman is quite illegal and arbitrary. It is prayed that the Hon'ble Tribunal may be pleased to set aside the order of the punishment imposed by the Chief Mechanical Engineer in proceedings dated 12-5-1987 as modified by the Chairman in proceedings dated 18-12-1987 and pass an Award holding that the punishment imposed on the workman is illegal and unjustified.

4. It is submitted that the workman Ch. Appa Rao, Khalasi, OHC was issued with charge sheet dated 28-8-1985. The workman submitted explanation to the charge denying the charges framed against him. It was specifically contended by him that he was only Khalasi and he is nothing to do with the operations of the conveyor belt, or the alleged equipments. However, without considering the same, an enquiry was ordered and on Sri Y. Raja Rao, was appointed as Enquiry Officer. The Enquiry Officer was in the rank of Asst. Engineer and witness examined are of higher status that is Executive Engineer. Therefore the initial prejudice have already been caused to the workman by recording the statement of superior Officer by the inferior officer in the enquiry. It is clearly brought out in the enquiry that the workman went for Tea and it is the normal practice admitted by the Management witness that for taking the Tea, the workman has not taken permission. At the relevant time, when the snapping of the conveyor belt took place, the petitioner was not at the spot and he is nothing to do with the conveyor belt, operations. His duty is only to protest the Stacker from automatic driving because of in effect breaker power of the controlling gear by plaining skids. This was admitted by the witness of the Management itself and he has no authority or competence to set right the operational system. The workman cannot be fastened with negligence of duties causing jam of chute house and snapping of conveyor belt. However, the Enquiry Officer, without appreciating the real facts and circumstances

mechanically found the workman guilty of the charge. Therefore, a show cause notice was issued on 8-8-1986 proposing the punishment of reduction of pay to minimum of scale to Rs. 550.00 from Rs. 627.00 in the time scale of pay of Rs. 550—726.00 for a period of one year without cumulative effect. The workman submitted his explanation to the said show cause notice and thereafter final orders were passed on 17-9-1986 by the Chief Mechanical Engineer imposing punishment of reduction of pay from Rs. 627.00 to Rs. 583.00 in the pay scale of Rs. 550—726 for a period of one year without cumulative effect w.e.f. the date of issue of the proceedings. As already set out the enquiry is vitiated by the sole fact that the higher official was the witness in the enquiry before the Enquiry Officer who is the lower rank. It is also brought out in the evidence that no tea arrangements are made at the place of work and the superior to the workman had permitted him to go for Tea by mere signals. Therefore, the charge is not at all proved against the workman. It is therefore prayed that the Hon'ble Tribunal may be pleased to hold that the punishment imposed on the workman by proceedings dt. 17-9-1986 as illegal, arbitrary and contrary to rules and consequently pass an award setting aside the punishment order and grant such other relief as this Hon'ble Court deems fit and proper.

5. The brief contents of the counter filed by the Respondent Management read as follows : Without prejudice to the rights of the Respondent-Management it is respectfully submitted that Sri K. Satya Raju, Operator Gr. II was posted at Stacker-I in third shift (22.00 hrs. to 6.00 hrs.) on 10-8-85. The duties of Operator Gr. II are extracted below :

"Responsible for the operation and maintenance of any equipment, entrusted to him during the shift in an efficient manner and to assist the operator in his duties on plant where this is provided for."

The allegation that the workman (Operator Gr. II) has nothing to do with the operation of the conveyor belt system except giving signals for stacking piling and that for any faulty operations, Gr. I Operator was reasonable as the entire Operational system was under his control is not tenable, since the Operator Gr. II Sri K. Satya Raju should assist the Gr. I Operator and also required to check the equipment along with the Gr. I Operator for efficient and smooth operation besides giving signals for stack piling. It may be noticed that on 10th August, 1985 in third shift the operators who are on duty along with other workmen are responsible to see the smooth functioning of the conveyor belt, because of the dereliction of duties and negligence on the part of the employees i.e. Operators and Khalasi who are working at H2 and H1 extension resulted in snapping of R-3 conveyor belt and the Respondent-Management issued charge sheets to all the workmen concerned and conducted a domestic enquiries. It is the mandatory duty on the part of the operators and Khalasi who are on the workspot to watch the conveyor belt and if any trouble or untoward incidents or mechanical breakdown occurred to watch the thing and to take appropriate remedial action but they cannot take a defence that the operator posted near the equipment did not notice and thereby failed to take prompt and suitable action to avert the situation which certainly shows his negligence and carelessness in performing the duties entrusted to him. With reference to para 3 of the claim statement it is true that the Management issued charge sheet on 22-8-85 and the workman submitted his explanation and as management was not satisfied with the explanation given by the workman i.e. Sri K. Satya Raju the CME according to VPE (CC&A) Regulations 1968 issued a proceeding dt. 27-12-1985 appointing Sri Ch. Srinivasa Rao, Asst. Exe. Engineer as Enquiry Officer. As such, the allegation that without considering the representation submitted by the workman in response to show cause notice issued to him, the Disciplinary Authority passed the order of punishment as imposed and that the said punishment is illegal and contrary to the provisions of the V.P.E. (CC&A) Regulations 1968 is not correct. It is also true that a common enquiry was conducted for three workers i.e. S/Sri K. Satya Raju, T. Appa Rao and V. S. Padmanabha Raju, Operators on duty on that day. The

Enquiry Officer gave full and fair opportunity to the delinquent employee conducted the domestic enquiry as per principles of natural justice. The Enquiry Officer forwarded his findings to the Management and according to VPE (CC&A) Regulations a show cause notice was issued on 6-2-87. The workman submitted the reply. The Management considered their replies and looked into the entire record and imposed a punishment of reduction of pay by four stages. Later an appeal has been filed by Sri Satya Raju and other two operators to the Appellate Authority Chairman, Visakhapatnam Port Trust who has gone into the entire record of enquiry officer's findings, past record of the employee applied his mind and reduced the punishment from 4 stages to 2 stages in the pay scale without cumulative effect. The petitioner is put to strict proof with regard to the allegation that it is not uncommon that foreign elements do come in the ore and sometimes operations are also jammed. The further allegation that is not possible for the persons or operators to notice the foreign material in the nights is not correct and wherever the operators are working in the night shift proper lighting arrangements have been made by the Management. It is therefore submitted that no injustice was done to the workman by awarding the aforesaid punishment though the negligence of the workman which led to the breakdown of the plant warrants for a severe penalty than what was imposed on him. Incidentally it is submitted that along with the claimant workman, Sri K. Satya Raju two more operators S/Sri P. Apparao, Operator Gr. I and V. S. Padmanabha Raju, Operator Gr. II who were in 3rd shift on 10-8-85 i.e. the date of occurrence of the incident were also charge sheeted for their negligence and carelessness resulting in snapping of R-3 conveyor belt. It is submitted that a joint enquiry was held under common proceedings in terms of Regulation 14 of VPE (CC&A) Regulations, 1968. Having proved in the enquiry that all the three workmen were guilty of the charge and having accepted the findings of the Enquiry Officer, the disciplinary authority had awarded the penalty of reduction of pay by four stages for a period of two years without cumulative effect. All the three employees have appealed against the proceedings of the disciplinary authority and the appellate authority having allowed their appeals partly reduced the punishments to that of reduction of pay by two stages for two years without cumulative effect. With reference to para 5 of the claim statement it is submitted that Sri K. Maria Das, Asst. Foreman (Operation) OHC was posted at Area-1 in third shift (22.00 hrs. to 6.00 hrs.) on 10-8-85 and the workman was in charge of a specific zone and was supposed to monitor and control the system for smooth efficient and uninterrupted operation in his area. Sri Maria Das was charge sheeted on 21-8-1985 because of negligence and dereliction of duty. But he failed to notice the abnormality and take prompt and suitable action to avert the situation which clearly shows that he had not paid adequate attention towards his legitimate duties entrusted to him and hence the charge was made against him. Regarding the allegation of the claimant Union that the workman was attending to his duties at H-3 Mechanical House and that it would not be possible for him to immediately proceed to other operations for stopping the irregular movement of machinery and hence the workman cannot be made responsible for the incident which took place at Stacker 1, It is submitted that the workman was in charge of Area-I on the day of Occurrence of the incident and was required to monitor and control all the operations in his area, wherever he may stay in that specific zone under his control. The very avowal of the claimant Union that the duties assigned to the workman as Asstt. Foreman are to watch the overall performance of the plant and he was to supervise the operations at Dumper R1 convey belt H1, Mechanical House, R-2 conveyor, H3 Mechanical House and he was expected to go round all the places to ensure proper functioning of the equipment, disclose the fact that being a supervisor, holding the post of Asst. Foreman and in charge of Area-I on the day in question failed to observe the overflow of fine ore, though it took place for about an hour, Maria Das failed to monitor and control the operation in his specific zone of operation. The reasoning given in page No. 7 & 8 of the claim statement is contra to the enquiry proceedings. This Hon'ble Court may be pleased to read the entire domestic enquiry file as part and parcel of this counter. The allegation that Sri Maria Das cannot be made responsible for the incident that took place at Stacker-1 is not correct. The meters have not functions as such the automatic system got halted is not correct. It is submitted



that after going through the Enquiry Report submitted by the Enquiry Officer carefully, the Disciplinary Authority accepted the findings of the Enquiry Officer and the workman was issued with a show cause notice proposing to impose on him the penalty of reduction of his pay to the minimum of his scale of pay. However, having considered the representation submitted by the workman to the show cause notice the Disciplinary Authority took a lenient view and reduced the penalty of reduction of pay to the maximum of scale of pay proposed in the show cause notice to that of reduction of pay by four stages of a period of one year without cumulative effect. It is submitted that the punishment was awarded after going through the entire record. The Appellate Authority applied his mind and modified the order which is legal and justified and the workman is not entitled to any relief as prayed for. With reference to para-7 of the claim statement it is submitted that Sri Ch. Appa Rao Khalasi (Shore) OHC was posted at Stacker-I in the 3rd shift (22.00 hrs. to 06.00 hrs.) on 10-8-85. The workman was not available at the duty spot at the time of occurrence of the incident of snapping of R-3 conveyor belt during 3rd shift on 10-8-85 and he thereby exhibited gross negligence and lack of interest in performing his legitimate duties entrusted to him. The Management issued a charge sheet on 28-8-85 and the workman submitted his explanation to the charge memo and the management was not satisfied with the explanation given and appointed Sri Y. Raja Rao as Enquiry Officer who conducted the domestic enquiry as per principles of natural justice. It is the duty of the Khalasi to be present during the duty hours and also to be watchful and vigilant and if there is any untowards incidence to report to the Superior Officials. In the present case Sri Ch. Appa Rao was not present in the workspot. Normally a conveyor belt takes about an hour to develop tension and to snap. The Officer concerned found that this Khalasi was not in the workspot and he has gone for tea. The workman concerned are not vigilant as well as careless in their attitude which was a main cause for snapping of the belt. It is submitted that since the workman denied the charge, a departmental enquiry was ordered by the Disciplinary Authority under the provisions of the VPE (CC&A) Regulations 1968. It is submitted that the allegation of the claimant union that initial prejudice was caused to the workman by appointing an Enquiry Officer hold the rank of an Asst. Engineer and Management witnesses was an Officer of higher status is not tenable. It is submitted that the workman's contention that he was not at the spot at the time of incident and he had nothing to do with the operations of the conveyor belt is not tenable as it is the primary duty of the workman to be present at the workspot throughout the shift. It is submitted that in this case the workman was not available at the duty spot at the time of occurrence of the incident and his contention that he had gone for tea at the time of the incident was not established during the enquiry. The allegation of the claimant workman that there was no negligence on his part is not correct and his absence at the workspot during the shift without informing his superiors clearly shows his negligence and lack of interest towards his legitimate duties entrusted to him. The Disciplinary Authority having carefully considered the representation submitted by the workman to the show cause notice, took a lenient view and reduced the proposed penalty and awarded the penalty of reduction of pay by four stages for a period of one year without cumulative effect. Without exhausting all the remedies available under Service Rules, the petitioner is not entitled to raise an Industrial Dispute. As such, the reference made to the extent of Sri Ch. Appa Rao concerned is bad in law. With this ground alone the

claim statement of Sri Ch. Appa Rao is liable to be dismissed. Without prejudice to the rights of the Respondent-Management, it is respectfully submitted that the workman in dispute made the allegation that the enquiries were not conducted as per principles of natural justice. Under these circumstances this Hon'ble Tribunal may be pleased to decide of validity of domestic enquiries as preliminary issues before going into the merits of the case. With reference to para 8 of the claim statement, it is submitted that the punishment imposed on the workman by the Disciplinary Authority is legal and in accordance with the VPE (CC&A) Regulations, 1968 which have statutory force and the workman cannot claim any relief from the Hon'ble Tribunal. In view of the above mentioned facts the Hon'ble Tribunal may be pleased to dismiss the claim petition of the claimant Union claiming relief for three workmen in the reference, as the same has no merits and confirm the orders passed by the Management are valid, legal and binding on the workman in dispute.

6. No oral evidence have been adduced on either side but marked Exs. M1 to M39 on behalf of the Respondent-Management. No documents were marked for the Petitioner.

7. The point for adjudication is whether the demand of Port & Dock Employees Association for withdrawal of punishment imposed on S/Sri K. Satya Raju, Operator Gr. II of OHC, Ch. Appa Rao, Khalasi, OHC and K. Maria Das, AF (Operation) OHC by the Management of V.P.T. consequent upon the incidence occurred during 3rd shift of 10-8-85 is justified?

8. The charge against Sri K. Satya Raju, Operator Gr. II is as follows :

"That the said Sri K. Satya Raju while functioning as Operator Gr. II in OHC was posted at Stacker in the 3rd Shift i.e. from 22-00 hrs. to 06.00 hrs. on 10-8-1985. During the shift, at about 04.30 hrs. on 11-8-85 (i.e. 3rd shift of 10-8-1985) one M. S. Plate of Sizes 100 mmx400 mm of 20 mm thickness got entangles in the stacker I receiving chute i.e. R-3 discharge chute on Stacker I resulting in overflow of ore and jamming of fine ore at H-2 and H1 extensions and also snapping of R-3 conveyor belt. This has occurred due to sheer negligence and utter carelessness in performing the legitimate duty of Sri K. Satya Raju. Thus Sri K. Satya Raju is responsible for failure of R-3 Conveyor belt. By the above act, Sri K. Satya Raju has exhibited gross negligence, utter carelessness and dereliction of duty."

The concerned workman denied the above charge by submitting an explanation. A common domestic enquiry was conducted along with two other workmen namely Sri T. Appa Rao, Operator Grade I OHC and Sri V. S. Padmanabha Raju, Operator Gr. II of OHC for the similar charges. In the domestic enquiry the Management examined four witnesses including Sri Sumitra Rao, Executive Engineer and Sri G. S. L. Murthy, Asst. Engineer and in defence the workman were also examined. Then a show cause notice dt. 6-2-1987 was issued to the workmen stating that the charge were partly proved and that the punishment of reduction of pay. The argument of the learned counsel of the Petitioner Union that the Petitioner Sri K. Satya Raju, Operator Grade II is not at all connected with the presence of M. S. Plates which is alleged to have caused jamming at H-2 and H-1 extensions and also snapping of R-3 Conveyor belt. His duty is to give only signal to the Operator Grade-I at Chute and he was at the Stacker-I and has no control over the Conveyor System. Beyond this he has

nothing to do with the other operations. The failure of the mechanical system cannot be attributable either directly or indirectly against the concerned workman. Even in the enquiry proceedings against his workman in question, the Enquiry Officer has given his report stating that it is established that Sri K. Satya Raju was at Stacker boom conveyor end, giving signalling for stock-piling. He had to assist Sacker Grade-I Operator in the operation of the equipment by giving signals and also to check the control over smooth operation. He may not have direct control over the equipment. This itself clearly shows that K. Satya Raju has nothing to do with the overflow of ore and jamming of fine ore at H-2 and H-1 extension and also snapping of R-3 conveyor belt. So I find that no charge can be attributed to the workman Sri K. Satya Raju, Operator Grade-II. Further, no job description of the post was evolved by the Management for Operator Grade II OHC.

9. The second charged workman is Sri K. Maria Das, Asst. Foreman (Operation) OHC. The charge against him is as follows :

"During the shift, at about 4.30 hrs. on 11-8-1985 (i.e. 3rd shift of 10-8-85) one M. S. Plate size 1000 mm x 400 mm of 20 mm thickness got entangled in the stacker I receiving chute i.e. R3 discharge chute on Stacker I resulting in overflow of fine ore and jamming of fine ore at H2 and H1 extension and also snapping of R3 conveyor belt. His sheer negligence and utter carelessness in performing his legitimate duties, caused the failure of R3 conveyor belt during the shift. Thus Sri Maria Das is responsible for snapping of R3 conveyor belt. By the above act Sri Maria Das exhibited gross negligence, utter carelessness and dereliction of duty. He therefore failed to maintain absolute devotion to duty as required under Reg. 3 of VPE's (C) Reg. 1964."

To the abovesaid charge the workman in question gave an explanation dt. 3-9-1985 which read as follows :

"On 10-8-1985 I was in 3rd shift and I have to supervise the area from dumper to H3. The quarterly shut down was not lifted up at by 10.00 p.m. The welding works were going on, in the tail end chute of R3 conveyor. Though contract labour I get cleared the pulleys etc. Dumping was started at 00.00 hrs. Maintenance Staff gave clearance at about 00.30 hrs. on 11-8-85. Then I took steps for starting the receiving conveyors. At about 4.30 hrs. on 11-8-85 when I was at H3 the R3 conveyor was stopped. Later, I came to know that R3 conveyor belt snapped. Previously, from 1965 the Operators were posted in H2 and H3 drive houses. They were removed from December, 1984. As an assistant Foreman I have carried out by duties as a Supervisor. Previously the metal detector was there which was not functioning at R1 conveyor. After installing O.B.M.S. (Overband magnetic separator) only small metal pieces are being removed and big metal pieces are not being removed. Again on 17-8-85 and 18-8-85 during 3rd and 2nd shift metal plates were collected at stacker H2."

The duties assigned to Asst. Foreman i.e. K. Maria Das are to watch the overall performance of the plant and he has to supervise the operations at Dumper, R-I Conveyor belt, H-I Mechanical House and R-II Conveyor and H-3 Mechanical House. He is expected to go round all these places and ensure proper function of the equipment. The argument of the counsel for the Petitioner-workman, he stated that in the enquiry, it is clearly brought out by the witnesses for the Management itself that the workman at the relevant time was attending his duties at H-3 Mechanical House. Therefore, it would not be possible for him to immediately proceed to the other operations for stopping the irregular movement of machinery. He was given instructions to attend various operations including the conveyor systems and mechanical house. He is not expected to be stationed

at one place and that he has to move from place to place throughout his duty hours. It is also brought out in the evidence that the workman was at H-3 Drive house and monitoring the operations. As there was no operator during the day shift, there was no opportunity for the workman to look at Stacker I. He further stated that it is not known whether there was foreign element like steel plate in the conveyor belt or due to some mechanical defect, the conveyor belt was snapped. The so-called iron piece was not removed in the presence of the workman and other connected operators. Therefore the presence of the plate itself is in doubt. Hence the workmen cannot be made responsible for the incidence which took place at Stacker-I. A perusal of the enquiry report Ex. M30 reads as follows :

"... It was the fact that R-3 belt was snapped due to jamming of fine ore at H-2 and H-1 extensions due to entangling of M. S. plate in the Stacker-I. As per the depositions of all the state witnesses it was understood that this incident could have been averted if the Area Incharge Sri K. Maria Das, Asst. Foreman (Op) would have noticed this in time. On the other hand Defence had tried to establish that it is not the fault of the charged officer as he was at H-3 at the time of this accident. ...."

From the above findings of the Enquiry Officer, it is not possible for the Asst. Foreman K. Maria Das to have averted the incident as he was at far off place attending to H-3 Mechanical House and it was beyond his control to have come immediately to the Stacker-I and attend to the function. Moreover the Enquiry Officer has not proved the charge against the workman in question but gave his findings on mere surmises and conjectures. I find that the charge against the workman Sri K. Maria Das is not proved.

10. The third charged workman is Sri Ch. Appa Rao, Khalasi, OHC. This workman was issued with charge sheet dated 18-8-1985 with the following charges :

"During the shift, at about 4.30 hrs. on 11-8-1985 (i.e. 3rd shift of 10-8-85) one M.S. Plate of sizes 1000 mm x 400 mm of 20 mm. thickness got entangled in the Stacker I receiving chute i.e. R-3 discharge chute on Stacker I resulting in overflow of ore from Stacker forming big heaps there and jamming of fine ore at H2 and H1 extensions and also snapping of R3 conveyor belt. Sri Appa Rao was supposed to be at Stacker I throughout the shift but he was not available at his duty spot at the time of occurrence of the aforesaid incident. From the above, it is clear that Sri Appa Rao exhibited gross negligence and lack of interest in performing his legitimate duties and thus Sri Appa Rao is responsible for snapping of R-3 conveyor belt."

He is careless and negligent in performing the legitimate duties and thereby failed to maintain absolute devotion to duty as required under Reg. 3 of VPE's (C) Reg. 1964."

To the above charge sheet the workman Ch. Appa Rao gave explanation denying the charges framed against him. He mentioned in the explanation the following statement :

"On 10-8-1985 I came to III Shri (22hrs. to 6 Hrs. Foreman (Operation) posted me at Stacker I. I was at my work spot from 10.30 P.M. to 6 A.M. I am only Class-IV employee and will do work entrusted to me by Operator-I at Stacker. I have carried out all the works entrusted to me on the day. I have not left the workshop, as alleged. I have to go stores, go to canteen to bring water to the operators attend works entrusted by foreman (Operation). I have to work any where during the shift."

The arguments of the counsel for the Petitioner-workman is that the workman Ch. Appa Rao, specifically contended that he was only Khalasi and he is nothing to do with the opera-



tions of the conveyor belt or the allied equipment. He further argued that at the relevant time, when the snapping of the conveyor belt took place, the workman in question was not at the spot and he is nothing to do with the conveyor belt operations. His duty is only to protect the Stacker from automatic driving because of in effect brake power of the controlling gear by placing skids. It is purely a non-technical action to Khalasi category. A perusal of the enquiry report submitted by the Enquiry Officer read thus :

"It is established that Shri T. Appa Rao, C. O. 1 was at Operator's cabin and operating the Stacker-I equipment that time of R-3 conveyor belt snapped. While operating the equipment for stackpiling it is not possible for him to check up the stacker-I chute in the inadequate lighting during the night filled with dust due to fines stackpiling. But as an experienced operator he could have sense the seriousness of the situation by the difference in sounds....."

"The measurements of the plate that had jammed in the stacker chute indicate in the memorandum of charges are not tallying with the plate that was submitted before the enquiry board which could be a typographical error. ....

There are some technical things such as protective devices like chute plug tensionmeter etc. failed, the belt 1051-B was relatively weak and in addition to that C. O-1 failed to execute his legitimate duties carefully in the adequate measure. Thus, if not, full he is also responsible for the snapping of R-3 conveyor belt"

From the above enquiry report, there is no evidence establishing the alleged misconduct. The Enquiry Officer has clearly mentioned in his enquiry report that while operating the equipment for stackpiling it is not possible for the workmen in question to check up the Stacker-I chute in that inadequate lighting during the night filled with dust due to fines stackpiling. How is it possible the workman in question to have paid adequate attention to his surroundings and the equipment which he is operating and exhibited his negligence and carelessness. Whereas the job of the Khalasi, the evidence adduced by the Management reveals that the workman has nothing to do with the conveyor belt or chute operations, except arranging skids to the stacker as and when required. So from the above I find that the charge against the workman Ch. Appa Rao has not been proved by the Enquiry Officer.

11. On a consideration of the evidence, facts and circumstances of the case, I am clearly of the view that no specific charge have been framed against the workman in question the enquiry was violative of principles of natural justice and the Enquiry Officer gave his findings on mere surmises conjectures. The report of the Enquiry Officer is perverse and based on no evidence on record. Further it is seen that M. S. Plate was found at R-3 but infact on a perusal of the record. it was found at R-5. There is no evidence to show that M. S. Plate was seen by so and so persons, actually there was no such M. S. Plate found at R-3. It is also seen that there is no proper lighting and tension meter provided at the site. If tension meter was there, this incident would not have taken place. It is also seen that there was no proper path-way along the conveyor belt, at some places there was damaged pathway and that the operator cannot move from one place to the other place which is far end. The measurement of M. S. Plate given in the charge sheet and the measurement given at the enquiry does not tally and the operator has to move from one end and the other end which is far away from each other. In view of all the facts and circumstances, I am of the opinion that the punishment imposed on the workmen in question are illegal, arbitrary and contrary to rules.

12. In the result, the demand of Port & Dock Employees Association for withdrawal of punishment imposed on S/Sri K. Satya Raju, Operator Grade II of OHC, Ch. Appa Rao, Khalasi, OHC and K. Maria Das, AF (Operation) OHC by the Management of Visakhapatnam Port Trust consequent 2004 GI/93—9.

upon the incident occurred during the 3rd Shift of 10-8-1985 is justified. The Proceedings No. E/M/PC/3371 dt. 31-3-1987 and the modified proceedings No. A/Appeals/8687/87 dt. 9-12-1987, Proceedings No. E/M/PC/3107/5062 dt. 12-5-1987 and the modified Proceedings No. A/19021/Appeals/87 dt. 18-12-1987 and Proceedings No. EM/9998, dt. 17-9-1986 are set aside.

Award passed accordingly.

Typed to my dictation, given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 5th day of August, 1993.

Y. VENKATACHALAM, Industrial Tribunal-I.

#### Appendix of Evidence

Witnesses Examined  
for the Management :

NIL

Witnesses Examined  
for the Workmen :

NIL

Documents marked for the Management with consent :

- Ex. M1.—Memorandum of charge sheet dt. 28-8-85 issued to Ch. Appa Rao by the Chief Mechanical Engineer, Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam.
- Ex. M2.—Explanation dt. 10-9-85 submitted by Ch. Appa Rao to the Chief Mechanical Engineer, Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam.
- Ex. M3.—Order dt. 5-9/10-85 appointing Y. Raja Rao as Enquiry Officer.
- Ex. M4.—Enquiry Proceedings Pertaining to Ch. Appa Rao.
- Ex. M5.—Enquiry report and findings pertaining to Ch. Appa Rao.
- Ex. M6.—Memorandum of penalty dt. 8-8-86 imposed on Ch. Appa Rao by the Chief Mechanical Engineer Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam.
- Ex. M7.—Representation dt. 22-8-86 made by Ch. Appa Rao to the Chief Mechanical Engineer, Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam in view of show cause notice dt. 8-8-86 (Ex. M6).
- Ex. M8.—Office Order No. CME/E/766 dt. 22-9-86 and proceedings of the disciplinary authority dt. 17-9-86 under Visakhapatnam port employees (Classification, Control & Appeal) Regulations, 1958 with regard to Disciplinary action against Ch. Appa Rao.
- Ex. M9.—Memorandum of Charge Sheet dt. 22-8-85 issued to K. Satya Raju by the Chief Mechanical Engineer, Visakhapatnam Port Trust (Disciplinary Authorities).
- Ex. M10.—Explanation dt. 11-9-85 submitted by K. Satya Raju to the Chief Mechanical Engineer, Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam.
- Ex. M11.—Order dt. 1-11-85 appointing C. Ramakrishna Rao as Enquiry Officer to conduct joint enquiry.
- Ex. M12.—Enquiry Proceedings pertaining to K. Satya Raju.
- Ex. M13.—Defence Brief of K. Satya Raju in continuation to the enquiry proceedings.
- Ex. M14.—Enquiry Report pertaining to K. Satya Raju.
- Ex. M15.—Order dt. 27-12-85 appointing Ch. Srinivasa Rao as Enquiry Officer to conduct enquiry.
- Ex. M16.—Memorandum dt. 6-2-87 issued to K. Satya Raju by the Chief Mechanical Engineer, Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam.
- Ex. M17.—Representation made by K. Satya Raju to the Chief Mechanical Engineer, Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam in view of Memorandum dt. 6-2-87 (Ex. M16).

- Ex. M18.—Proceedings dt. 31-3-87 of the Disciplinary Authority with regard to Disciplinary action against K. Satya Raju.
- Ex. M19.—Office Order No. CME/E/34 dt. 1-4-87 with regard to disciplinary action against K. Satyaraju issued by Chief Mechanical Engineer, Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam.
- Ex. M20.—True Copy of the Appeal dt. 21-5-87 of K. Satyaraju to the Chairman Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam.
- Ex. M21.—Remarks dt. 11-11-87 of the Chief Mechanical Engineer to the Secretary, Visakhapatnam Port Trust, Mechanical Department on the Appeal of K. Satya Raju dt. 21-5-87 (Ex. M20).
- Ex. M22.—Proceedings of the Appellate Authority under Visakhapatnam Port Employees (Classification Control and Appeal) Regulations 1968 on the Appeal dt. 21-5-87 of K. Satyaraju.
- Ex. M23.—Office Order No. CME/EM/216 dt. 15-12-87 with regard to disciplinary action against K. Satya Raju.
- Ex. M24.—Memorandum of Charge Sheet dt. 21-8-85 issued to K. Mariadas by the Chief Mechanical Engineer, Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam.
- Ex. M25.—Explanation dt. 3-9-85 submitted to the Chief Mechanical Engineer, Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam by K. Mariadas in view of Memorandum dt. 21-8-85 (Ex. M24).
- Ex. M26.—Order dt. 30-10-85 appointing K. Bheema Rao as Enquiry Officer.
- Ex. M27.—Enquiry Proceedings.
- Ex. M28.—Prosecution Brief dt. 25-10-86.
- Ex. M29.—Defence Brief dt. 4-11-86 of K. Mariadas.
- Ex. M30.—Report of the Enquiry Officer.
- Ex. M31.—Memorandum dt. 6-4-87 with regard to penalty of reduction of pay of K. Mariadas imposed by Chief Mechanical Engineer Visakhapatnam Port Trust.
- Ex. M32.—Representation dt. 27-4-87 made by K. Mariadas to the Chief Mechanical Engineer, Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam.
- Ex. M33.—Proceedings dt. 12-5-87 of the Disciplinary Authority under Visakhapatnam Port Employees (Classification Control & Appeal) Regulations, 1968 with regard to Disciplinary action against K. Maria Das.
- Ex. M34.—Office Order No. CME/E/50 dt. 12-5-87 with regard to Disciplinary action against K. Mariadas.
- Ex. M35.—Appeal dt. 26-6-87 of K. Mariadas to the Chairman, Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam.
- Ex. M36.—Remarks dt. 11-11-87 of the Chief Mechanical Engineer to the Secretary, Visakhapatnam Port Trust, Mechanical Department on the appeal of K. Maria Das (Ex. M35).
- Ex. M37.—Proceedings dt. 18-12-87 of the Appellate Authority under Visakhapatnam Port Employees (Classification Control & Appeal) Regulations 1968 on the Appeal dt. 26-6-87 of Sri Mariadas (Ex. M35).
- Ex. M38.—Office Order No. CME/EM/222 dt. 28-12-87 with regard to Disciplinary action against K. Mariadas.
- Ex. M39.—Photos Number in 20 pertaining to incident place.

Documents marked for the Workmen :

NIL

Y. VENKATACHALAM, Industrial Tribunal-I

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1993

का. आ. 2021.— केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान होने जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (द) के उपखंड (6) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 705 दिनांक 16 मार्च, 1993 द्वारा बैंकिंग कम्पनी द्वारा चलाया जाता है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 19 मार्च, 1993 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था,

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है,

अतः अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (द) के उपखंड (6) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 19 सितम्बर, 1993 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[संख्या एस - 11017/2/85 - डी - 1 (ए)]

एस. एम. पराशर, अधीन सचिव

New Delhi, the 3rd September, 1993

S.O. 2021.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provision of sub-clause (vi) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. No. 705 dated the 16th March, 1993 the Banking Industry carried on by a Banking Company as defined in clause (bb) of section 2 of the said Act to be a public utility service for the purpose of the said Act, for a period of six months from the 19th March, 1993.

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by provision to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purpose of the said Act, for a further period of six months from the 19th September, 1993.

[No. S-11017v2/85-D.I(A)]

S. S. PRASHER, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1993

का.आ. 2022— केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (द) के उपखंड (6) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 511 दिनांक 22 फरवरी, 1993 द्वारा भारत सरकार

टकसाल, कलकत्ता को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 4 मार्च, 1993 से छह मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था,

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छह मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है,

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (द) के उपखंड (6) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 4 सितम्बर, 1993 से छह मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[सं. एम-11017/6/85-डी-1 (ए)]

एस. एस. पराशर, अवसर सचिव

New Delhi, the 7th September, 1993

S.O. 2022.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provision of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 511 dated the 22nd February, 1993 the India Government Mint, Calcutta to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months, from the 4th March, 1993;

And whereas, the Central Government is of opinion that the public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purpose of the said Act, for a further period of six months from the 4th September, 1993.

[No. S-11017/6/85-DJ(A)]

S. S. PRASHER, Under Secy.

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1993

का.ग्रा. 2023— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधन के संबद्ध निबोधकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, तमिलनाडु मद्रास के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 27-8-93 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/108/92-आईआर (बी-III)]

एस. एस. के. राव, हेड ऑफ अधिकारी

New Delhi, the 1st September, 1993

S.O. 2023.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Tamil 2004 GI/93—10.

Nadu, Madras as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 27-8-93.

[No. L-12012/108/92-DR(III)]

S.S.K. RAO, Desk Officer

#### ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL,  
TAMIL NADU, MADRAS

Thursday, the 12th day of August, 1993

#### PRESENT :

Thiru K. Sampath Kumaran, B.A.B.L., Industrial Tribunal

Industrial Dispute 77 of 1992

(In the matter of the dispute for adjudication under Section 10(1) (d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workmen and the Management of State Bank of India, Madras-1).

#### BETWEEN

Thiru K. Ibrahim,  
No. 66, State Bank Colony Extn.,  
Nanganallur,  
Madras-600061.

#### AND

The Chief General Manager,  
State Bank of India,  
Local Head Office,  
21, Rajaji Salai,  
Madras-600001.

#### REFERENCE :

Order No. L-12012/108/92-IR.B.III, dated 7-9-1992,  
Ministry of Labour, Government of India.

This dispute coming on this day for final disposal upon perusing the reference and other connected papers on record and the workman being absent, this Tribunal made the following:

#### AWARD

This is a dispute between the Workman and the Management of State Bank of India, Madras-1 arising out of a reference under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 by the Government of India, for adjudication of the following issue:

"Whether the Management of State Bank of India is justified in dismissing Shri K. Ibrahim with effect from 14-3-90? If not, to what relief is the workman entitled to?"

When the dispute is called today, Mr. V. Chandrasekar filed Vakalat for petitioner. Though Vakalat is filed today for petitioner, Claim statement has not been filed in spite of the fact that sufficient opportunity has been given. Further time prayed for by the Counsel for the petitioner is refused. Petitioner is called and is absent. Hence this Industrial Dispute is dismissed for default.

Dated, this 12th day of August, 1993.

THIRU K. SAMPATH KAMARAN, Industrial Tribunal

## कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1993

का. भा. 2024.—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 29 सितम्बर, 1990 में प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना संख्या का० भा० 2549 तारीख 11 सितम्बर, 1990 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि अर्जन और अधिकार के अपने आशय की सूचना दी की;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को दे दी है:

और उक्त रिपोर्ट पर विचार करते हुए मध्य प्रदेश सरकार से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 291.83 हेक्टर (लगभग) या 721.111 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि अर्जन करनी चाहिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में वर्णित 291.83 हेक्टर (लगभग) या 721.111 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि का अर्जन किया जाता है।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले रेखांक सं. एस. ई. सी. एल./बी. एस. सी./एन. ई. आर./ए. सी. एम. ई./भूमि/79 तारीख 7 नवम्बर, 1990 का निरीक्षण कलक्टर बिलासपुर (मध्यप्रदेश) के या कोयला नियंत्रक, 1 काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय या साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व अनुभाग) सीरत रोड बिलासपुर-495001 (मध्य प्रदेश) के कार्यालय में किया जा सकता है।

## अनुसूची

मानिकपुर का दक्षिणी विस्तार ब्लॉक

कोर्बा कोलफील्ड्स

जिला—बिलासपुर (मध्य प्रदेश)

## सभी अधिकार

क्रम संख्या	ग्राम	हल्का संख्या	तहसील	जिला	क्षेत्र हेक्टर में	टिप्पणियाँ
1.	भिलाई	10	कोरबा	बिलासपुर	60.80	भाग
2.	बारबासपुर	14	कोरबा	बिलासपुर	51.44	भाग
3.	कुडूरमल	14	कोरबा	बिलासपुर	42.22	भाग
4.	सोनपुरी	54	कटघोरा	बिलासपुर	61.80	भाग
5.	कनबेरो	55	कटघोरा	बिलासपुर	75.57	भाग

कुल

291.83 हेक्टर (लगभग)

या

721.111 एकड़ (लगभग)

ग्राम भिलाई (भाग) में अर्जित किए गए प्लॉट संख्यांक—1

ग्राम बारबासपुर (भाग) में अर्जित किए गए प्लॉट संख्यांक—सर्वेक्षण नहीं किया गया?

ग्राम कुडूरमल (भाग) में अर्जित किए गए प्लॉट संख्यांक—1 (पी)

ग्राम सोनपुरी (भाग) में अर्जित किए गए प्लॉट संख्यांक—661

ग्राम कनबेरो (भाग) में अर्जित किए गए प्लॉट संख्यांक—465 (पी)

## सीमा वर्णन :—

क—ख—ग	रेखा ग्राम भित्ताई में 'क' बिन्दु से आरंभ होती है और ग्राम भित्ताई-बरबासपुर की सोनपुरी-खतराज की सामान्य सीमा के साथ गुजरती है जो कि हसदेव नदी से होकर गुजरती है और बिन्दु 'ग' पर मिलती है।
ग—घ—ङ	रेखा हसदेव नदी के पश्चिमोत्तर किनारे से होकर गुजरती है और बिन्दु 'ङ' पर मिलती है।
ङ—च—छ	रेखा ग्राम कनवरी में प्लॉट संख्या 465 और ग्राम कुदुरमल में प्लॉट संख्या 1 से होकर गुजरती है और 'छ' बिन्दु पर मिलती है।
छ—ज—ट	रेखा हसदेव नदी के पूर्वी किनारे से होकर गुजरती है और ग्राम कुदुरमल-बरबासपुर की सामान्य सीमा पर मिलती है और बिन्दु 'ट' पर मिलती है।
ट—ठ—ड	रेखा हसदेव नदी के पूर्वी किनारे से होकर गुजरती है और आरंभिक बिन्दु 'क' पर मिलती है।

[फा. सं. 43015/8/89-एन. एस. डब्ल्यू.]

बी. बी. राव, अधीन सचिव

## MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 16th September, 1993

S. O. 2024.—Whereas by the notification of the Government of India in the then Ministry of Energy (Department of Coal) number S.O. 2549 dated the 11th September, 1990 under sub-Section (1) of Section 7 of the Coal Bearing Areas (Aquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act) and published in Part II, Section 3, Sub-Section (ii) of the Gazette of India dated the 29th September, 1990, the Central Government give notice of its intention to acquire land and rights in the locality specified in the Schedule appended to that notification;

And whereas the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act has made his report to the Central Government;

And whereas, the Cental Government after considering the report aforesaid and consulting the Government of Madhya Pradesh is satisfied that the lands measuring 291.83 hectares (approximately) or 721.111 acres (approximately), described in the Schedule appended hereto, should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands measuring 291.83 hectares (approximately) or 721.111 acres (approximately) described in the said Schedule are hereby acquired.

The Plan No. SECL/BSP/LER/ACME/LAND/79 dated the 7th November, 1990 of the area covered by this notification may be inspected in the Office of the Collector, Bilaspur (Madhya Pradesh) or in the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta or in the Office of the South Eastern Coalfields Limited (Revenue Section), Seepat Road, Bilaspur-495001 (Madhya Pradesh).

## SCHEDULE

## SOUTH EXTENSION BLOCK OF MANIKPUR

## KORBA COALFIELD

## DISTRICT—BILASPUR (MADHYA PRADESH)

## All Rights

Serial No.	Village	Halka number	Tahsil	District	Area in hectares	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bhilai	10	Korba	Bilaspur	60.80	Part
2.	Barbaspur	14	Korba	Bilaspur	51.44	part

1	3	4	5	6	7
3. Kudurmāl	14	Korba	Bilaspur	42.22	part
4. Sonpuri	54	Katghora	Bilaspur	61.80	part
5. Kanberi	55	Katghora	Bilaspur	75.57	part
Total				291.83	hectares
				(approximately)	
				OR	721.111
					acres
					(approximately)

Plot numbers acquired in village Bhilai (part)—1.

Plot numbers acquired in village Barbaspur (part)—unsurveyed.

Plot numbers acquired in village Kudurmāl (part)—1(P).

Plot numbers acquired in village Sonpuri (part)—61.

Plot numbers acquired in village Kanberi (part)—465(P).

#### Boundary Description --

A—B—C	Line starts from point 'A' in village Bhilai and passes along the common boundary of villages Bhilai-Bisalmpur, Sonpuri-Jatiaj which is also through Hasdeo river and meets at point 'C'.
C—D—E	Line passes along the western bank of the Hasdeo river and meets at point 'E'.
E—F—G	Line passes in village Kanberi through plot number 465 and in village Kudurmāl through plot number 1 and meets at point 'G'.
G—H—I	Line passes along the eastern bank of Hasdeo river and meets on the common boundary of villages Kudurmāl-Barbaspur and meets at point 'I'.
I—J—A	Line passes along the eastern bank of Hasdeo river and meets at the starting point 'A'.

[F. No. 43015/8/89-LSW]

B. B. RAO, Under Secy.